आज का विचार
विचारों का मिलन ही किसी रिश्ते का सूत्रधार होता है। चाहे वह रिश्ता कोई भी हो।

दैनिक
सिटी दर्पण
आईना सच का

5

सिटी दर्पण-राष्ट्रीय दैनिक हिंदी समाचार पत्र की अधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए स्कैन करें।

चंडीगढ़ । मंगलवार, 26 मई, 2026 | वर्ष 24, अंक 126, मूल्यः 3 रुपए, पृष्ठ 8 | RNI Regn No.: CHAHIN/2003/09265 Established 2003 | www.citydarpan.com

शाह करेंगे सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा सुरक्षा व्यवस्था की करेंगे समीक्षा

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिनों में देश के विभिन्न सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे और सीमा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर उच्चस्तरीय बैठकें करेंगे। इस दौरान वह सुरक्षा बलों के जवानों से संवाद करने के साथ-साथ सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी करेंगे।

गृहमंत्री अमित शाह के कार्यालय के मुताबिक गृहमंत्री 25 मई की रात राजस्थान के बीकानेर पहुंचेंगे। इसके बाद 26 मई की सुबह वह सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की सीमा चौकी सांचू का दौरा करेंगे। वहां वह जवानों से बातचीत करेंगे तथा सुरक्षा बलों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे।

इसके बाद दोपहर दो बजे बीकानेर में सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक आयोजित होगी। बैठक में गृह मंत्रालय, राजस्थान सरकार और बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। साथ ही राजस्थान के पांच सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी मौजूद रहेंगे।

गृहमंत्री 29 मई को गुजरात के भुज का दौरा करेंगे। इस दौरान वह बीएसएफ की सीमा चौकी का निरीक्षण करेंगे और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हरामी नाला क्षेत्र का भी दौरा करेंगे।

इसके बाद जून में उनका पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के सीमावर्ती इलाकों का दौरा प्रस्तावित है। कार्यक्रम के अनुसार 5 जून को वह त्रिपुरा में सीमा क्षेत्रों का दौरा करेंगे, जबकि 15 जून के आसपास पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों का प्रवास करेंगे। वहां भी वह सीमा सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे और सुरक्षा बलों के अधिकारियों के

नीट-यूजी पुनर्परीक्षा के सुचारु आयोजन के लिए राज्यों से सहयोग की अपील, धर्मेंद्र प्रधान ने लिखी चिट्ठी

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी)2026 पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सफल आयोजन के लिए सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों को पत्र लिखकर सहयोग मांगा है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने मौजूदा भीषण गर्मी और लू की स्थिति को देखते हुए परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने का विशेष आग्रह किया। उन्होंने राज्यों से कहा कि जिला प्रशासन तथा परीक्षा आयोजित करने वाले स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों को उचित निर्देश जारी किए जाएं।

पत्र में उन्होंने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षित पेयजल, पर्याप्त बैठने की व्यवस्था, पंखे और कूलर, स्वच्छ शौचालय, छायादार प्रतीक्षालय, निर्बाध बिजली आपूर्ति तथा आवश्यकता पड़ने पर पोर्टेबल शौचालय उपलब्ध कराने पर जोर दिया।

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि विद्यार्थियों का हित और उनका स्वास्थ्य सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने परीक्षा के दिन अभ्यर्थियों के लिए पर्याप्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री ने विश्वास जताया कि सभी राज्य सरकारें पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगी ताकि नीट (यूजी) 2026 की पुनर्परीक्षा निष्पक्ष, पारदर्शी और सुचारु रूप से संपन्न हो सके।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) देश में मेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए नीट-यूजी आयोजित करती है। इस वर्ष 3 मई को नीट-यूजी 2026 की परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा में कथित अनियमितताओं और जांच एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर एनटीए ने परीक्षा को रद्द करते हुए 21 जून को दोबारा परीक्षा कराने का फैसला किया है। यह ऑफलाइन परीक्षा होगी, जिसमें 22 लाख से अधिक छात्रों के बैठने की उम्मीद है। इस दौरान छात्रों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा।

दस दिन में चौथी बार बढ़े ईंधन के दाम, पेट्रोल 2.61 रुपये, डीजल 2.71 रुपये हुआ महंगा

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

पश्चिम एशिया संकट के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं गैस विपणन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज एक बार फिर इजाफा किया है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमत 2.61 रुपये प्रति लीटर, जबकि डीजल के दाम 2.71 रुपये प्रति लीटर बढ़ाये हैं। पिछले 10 दिन में यह चौथी बढ़ोतरी हैं। नई दरें लागू हो गई हैं।

इंडियन ऑयल के वेबसाइट के मुताबिक राष्टीरय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 2.61 रुपये प्रति लीटर बढ़कर 102.12 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जो पहले 99.51 रुपये प्रति लीटर थी। वहीं, डीजल के दाम 2.71 रुपये बढ़कर 95.20 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गए हैं, जो पहले 92.49 रुपये प्रति लीटर था।

इसके अलावा कोलकाता में पेट्रोल 113.51 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है, जहां 2.87 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। मुंबई में इसका भाव 111.21 रुपये प्रति लीटर हो गया है, जबकि चेन्नई में कीमत 107.77 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गई। इसी तरह कोलकाता में डीजल की कीमत 99.82 रुपये प्रति लीटर हो गई है। मुंबई में डीजल का दाम 97.83 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया।

विशेषज्ञों का कहना है कि पेट्रोल-डीजल की कीमतों में की गई यह वृद्धि वैश्विक कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और रुपये में कमजोरी के बीच की गई है। वैश्विक कच्चे तेल की कीमत बढ़ने और रुपये के कमजोर होने से तेल विपणन कंपनियों की आयात लागत पर दबाव बढ़ा है। इससे पहले शनिवार को पेट्रोल और डीजल के दाम में 87 पैसे और 91 पैसे प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी हुई थी।

पेट्रोल-डीजल के दाम में फिर से हुई बढ़ोतरी पर आम आादमी पार्टी (आआपा) के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने कहा, ‘पिछले 10 दिनों में ही पेट्रोल-डीजल की कीमत साढ़े सात रुपये बढ़ गई है। देश में अब ऐसा कोई शहर या राज्य नहीं बचा है जहां पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर से कम में मिल रहा हो। एक गरीब आदमी आखिर ईंधन का खर्च कैसे उठाएगा?

उल्लेखनीय है कि ईंधन की कीमतों में 15 मई को पहली बार संशोधन हुआ था। तब से अब तक पेट्रोल और डीजल के दाम कुल मिलाकर करीब 7.5 रुपये प्रति लीटर बढ़ चुके हैं। ईंधन की बढ़ती कीमतों ने मध्यम वर्ग और रोजाना वाहन इस्तेमाल करने वाले लोगों की चिंता बढ़ा दी है।

पेट्रोल-डीजल के दामों में चौथी बढ़ोत्तरी जनता की जेब पर हमला : राहुल गांधी

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार चौथी बार बढ़ोतरी पर केंद्र सरकार पर लोगों की जेब काटने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार चुनाव के बाद लगातार ईंधन की कीमतें बढ़ाकर जनता पर बोझ डाल रही है। राहुल गांधी ने 'एक्स' पर लिखा कि महंगाई मानव का फिर से हमला हुआ है। पेट्रोल-डीजल के दाम किश्तों में बढ़ाए जाते हैं, ताकि चुपके-चुपके जनता की जेब कटती रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि महीनों से वे आर्थिक तूफान आने की चेतावनी दे रहे थे लेकिन प्रधानमंत्री चुनाव में व्यस्त रहे और चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल-डीजल आठ रुपये महंगा कर दिया। उन्होंने कहा कि यह बढ़ोतरी आगे भी जारी रहेगी और मोदी सरकार का एक ही काम है, चुनाव में वादे करना और बाकी समय जनता की जेब पर वार करना। बीते एक महीने में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी की कीमतों में लगातार चौथी बार बढ़ोतरी हुई है। 25 मई को दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर हो गया। इससे पहले 23 मई को पेट्रोल में 87 पैसे और डीजल में 91 पैसे की बढ़ोतरी हुई थी, जिसके बाद पेट्रोल 99.51 रुपये और डीजल 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया। 18 मई को भी पेट्रोलियम पदार्थों में बढ़ोत्तरी की गई थी। तब पेट्रोल और डीजल में लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी और सीएनजी भी एक रुपये प्रति किलो महंगी हुई थी। उससे पहले 15 मई को पेट्रोल और डीजल में तीन-तीन रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी, इसी दिन सीएनजी भी दो रुपये प्रति किलो महंगी हुई थी। और सबसे पहले 01 मई को वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर में 993 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी जिससे दिल्ली में इसकी कीमत 3,071.50 रुपये हो गई थी।

नायब सिंह सैनी ने महिला पत्रकारों के साहस और योगदान की सराहना की

भूपेंद्र शर्मा
चंडीगढ़

बोले- महिला, युवा, किसान और गरीब विकसित भारत के चार मजबूत स्तंभ, हरियाणा में महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार लगातार कर रही काम

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वुमन जर्नलिस्ट वेल्फेयर ट्रस्ट की महिला पत्रकारों से मुलाकात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जेटली साथ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने पत्रकारिता क्षेत्र की चुनौतियों के बावजूद महिला सशक्तिकरण के साथ आगे बढ़ रही महिलाओं के मनोबल की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता हित में गति और ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है तथा मीडिया जगत से मिलने वाली सूचनाओं और अपडेट पर वह स्वयं संज्ञान लेते हैं।

मुख्यमंत्री ने बीते 11 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए कार्यों पर चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महिला, युवा, किसान और गरीब व्यक्ति चार प्रमुख स्तंभ हैं। महिला सशक्तिकरण पर सरकार के प्रयासों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा से बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरूआत की थी। हरियाणा सरकार ने समाज के विभिन्न वर्गों को इस मुहिम से जोड़कर सकारात्मक परिणाम हासिल किए हैं। कई पंचायतों में बेटियों की जन्म दर बेटों से अधिक हुई है, जिन पंचायतों को सरकार द्वारा सम्मानित भी किया गया। साथ ही महिला सरपंचों को इन पंचायतों का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों (सेल्फ हेल्प ग्रुप) के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा रहा है। पंचकूला में आयोजित स्वदेशी मेले का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि एक महिला ने स्वयं सहायता समूह से जुड़कर आत्मनिर्भर बनने और बेटी की शादी जैसे खर्चों की चिंता समाप्त होने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की अनाज मंडियों में किसानों के लिए खोली गई अटल कैंटीनों का संचालन भी स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं कर रही हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नमो ड्रोन दीदी योजना में हरियाणा अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

बाढ़ के समय पंजाब के हर जिले में राहत सामग्री भेजी गई

पंजाब को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वहां बाढ़ की स्थिति के दौरान हरियाणा सरकार ने हर जिले की समस्याओं को चिन्हित कर राहत सामग्री और सहायता पहुंचाने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि पंजाब के नेता किसानों को फसल खराबे के मुआवजे की सही जानकारी तक नहीं दे पाए। अब इसका जवाब आने वाले चुनावों में पंजाब की जनता देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन के लिए हर माह 2100 रुपये की सहायता दी जा रही है और यह जनहितकारी कार्य सरकार बनने के पहले वर्ष में ही शुरू कर दिया गया। उन्होंने कहा कि पंजाब में महिलाओं को सहायता राशि देने की घोषणा तो की गई, लेकिन अब तक एक रुपया भी महिलाओं के खातों में नहीं पहुंचा, जबकि पंजाब सरकार अपना कार्यकाल लगभग पूरा कर चुकी है। गुरुग्राम क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि मुनक नहर से सीधे गुरुग्राम और नूंह तक पाइपलाइन परियोजना के जरिए जलापूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए लगभग दो हजार करोड़ रुपये के टेंडर की तैयारी पूरी कर ली गई है। साथ ही लो लाइन एरिया में एसटीपी बनाकर सोहना क्षेत्र के माध्यम से जल प्रबंधन की योजना पर भी कार्य किया जाएगा। एसवाईएल मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में उन्होंने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर चर्चा की है।

राहुल गांधी ने लगाया, सीबीएसई कॉपी मूल्यांकन में गड़बड़ी का आरोप

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

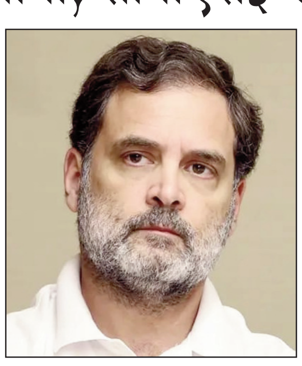

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की कॉपियों के मूल्यांकन के बारे में उठे विवादों को लेकर केंद्र सरकार पर आज आरोप लगाया कि सरकार ने एक और संस्था को धांधली का प्रतीक बना दिया है।

राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि दशकों में पहली बार सीबीएसई बोर्ड परीक्षा पर इतने गंभीर सवाल उठे हैं। 18.5 लाख बच्चों ने परीक्षा दी और एक हफ्ते से ऑन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम), गलत मार्किंग और जांच की गड़बड़ी की शिकायतें अनसुनी पड़ी हैं। एक 17 साल का बच्चा, जिसकी कॉपी गलत जांची गई, न्याय की उम्मीद में सोशल मीडिया पर आया, लेकिन उसे मदद नहीं मिली बल्कि सोशल मीडिया पर उसे देशद्रोही, जॉर्ज सोरोस का एजेंट और डीप स्टेट का हिस्सा कहकर बदनाम किया गया।

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं और जेन जी से डरती है, क्योंकि वे सवाल पूछ रहे हैं। जो सवाल पूछे, उसे यह सरकार बदनाम करती है, डराती है और कुचलती है।

उल्लेखनीय है कि सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद पुनः मूल्यांकन प्रक्रिया विवादों में घिर गई है। छात्रों का कहना है कि बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई जा रही उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपियां इतनी धुंधली हैं कि उन्हें पढ़ना मुश्किल है। कई छात्रों ने फीस जमा करने के बावजूद पेमेंट कंफर्मेशन न मिलने और पोर्टल पर तकनीकी खामियों की शिकायत की है। पुनः मूल्यांकन पोर्टल पर बार-बार साइट अंडर मेंटेनेंस का संदेश आने से अभिभावक और छात्र परेशान हैं।

इस पर बोर्ड ने सफाई देते हुए कहा कि ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से पेमेंट स्टेटस अपडेट में देरी हो रही है और छात्रों को बार-बार आवेदन नहीं करना चाहिए। बोर्ड ने यह भी घोषणा की कि अब छात्र मात्र 100 रुपये में अपनी आंसर शीट देख सकते हैं, जबकि पहले इसके लिए 700 रुपये शुल्क देना पड़ता था। किसी विशेष प्रश्न की दोबारा जांच कराने के लिए 25 रुपये फीस तय की गई है। बोर्ड ने कहा कि यह कदम पारदर्शिता और छात्रों के हित में उठाया गया है।

राजस्थान, हिमाचल में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गडकरी ने की समीक्षा

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

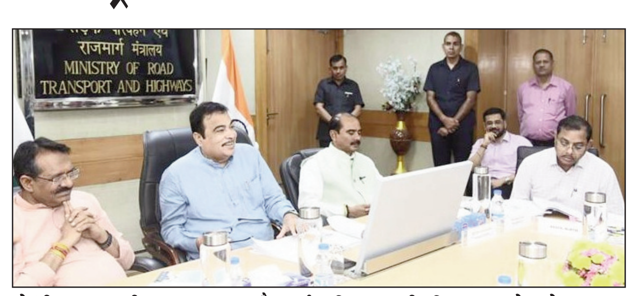

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव की स्थिति की व्यापक समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और ठेकेदारों को समयबद्ध तरीके से परियोजनाओं को पूरा करने, गुणवत्ता मानकों का सख्ती से पालन करने और आधुनिक तकनीकों व निर्माण पद्धतियों को अपनाने के निर्देश दिए।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि यहां हुई इस बैठक केंद्रीय राज्यमंत्री अजय टम्टा और हर्ष मल्होत्रा, एनएचएआई और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी तथा परियोजना ठेकेदार शामिल हुए। बैठक में गडकरी ने राजस्थान में 10,064 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की गुणवत्ता और रखरखाव की स्थिति का आकलन किया। वहीं, हिमाचल प्रदेश में 1,947 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों की प्रगति और रखरखाव की समीक्षा की गई। मंत्री ने परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन, गुणवत्ता मानकों का सख्ती से पालन और आधुनिक तकनीकों व निर्माण पद्धतियों को अपनाने पर जोर दिया। गडकरी ने अधिकारियों को मानसून से पहले व्यापक तैयारी करने के निर्देश दिए। इसमें प्रभावी जल निकासी प्रबंधन, ढलानों की सुरक्षा, सक्रिय रखरखाव और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र शामिल हैं, ताकि बारिश के दौरान यातायात बाधित न हो, सड़क सुरक्षा बनी रहे और लंबे समय तक राजमार्गों की स्थायित्व सुनिश्चित हो सके। मंत्री ने कहा कि टिकाऊ और कुशल राजमार्ग नेटवर्क देश में कनेक्टिविटी सुधारने, आर्थिक विकास तेज करने, यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और प्रमुख कॉरिडोरों पर निर्बाध गतिशीलता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं।

राजस्व वृद्धि के साथ विश्वास आधारित प्रशासन पर हो विशेष फोकसः योगी आदित्यनाथ

एजेंसी (हि.स.)
लखनऊ

उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में जीएसटी और वैट मद में कुल एक लाख 15 हजार 977 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया, जो पुनरीक्षित अनुमान का लगभग 98.8 प्रतिशत रहा। जीएसटी में उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर रहा, जबकि महाराष्ट्र प्रथम और कर्नाटक तीसरे स्थान पर रहे। यूपी देश में सर्वाधिक 21.82 लाख सक्रिय जीएसटी करदाताओं वाला राज्य बना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथने कर संग्रह बढ़ाने के साथ-साथ ईमानदार व्यापारियों को सुविधा, सम्मान और त्वरित समाधान की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं।।

मुख्यमंत्री योगी सोमवार को राज्य कर विभाग के शासन, मुख्यालय और फील्ड स्तरीय अधिकारियों के साथ विशेष बैठक कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य तक पहुंचाने में राज्य कर विभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और विभाग को राजस्व वृद्धि के साथ विश्वास आधारित प्रशासन का मॉडल प्रस्तुत करना होगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि कर प्रणाली को अधिक सरल, डिजिटल और जवाबदेह बनाया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जीएसटी पंजीयन, रिटर्न दाखिल, अपील निस्तारण और रिफंड जैसी प्रक्रियाओं में अनावश्यक देरी समाप्त होनी चाहिए। उन्होंने व्यापारियों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखने, छोटे कारोबारियों को जागरूक करने तथा जिला एवं खंड स्तर तक करदाता सहायता कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग कर कर चोरी रोकने के साथ-साथ वैध व्यापार को प्रोत्साहन देना आवश्यक है।

बैठक के दौरान अधिकारियों ने बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य ने जीएसटी और वैट मद में कुल एक लाख 15 हजार 977 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया है, जो पुनरीक्षित अनुमान का लगभग 98.8 प्रतिशत है। जीएसटी में उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर रहा, जबकि महाराष्ट्र प्रथम और कर्नाटक तीसरे स्थान पर रहे। बैठक में यह भी बताया गया कि जीएसटी बकाया के रूप में 2658 करोड़ रुपये जमा हुए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 228 प्रतिशत अधिक हैं। वहीं वैट बकाया के रूप में 800 करोड़ रुपये की वसूली हुई, जो गत वर्ष से 29 प्रतिशत अधिक है। प्रवर्तन इकाइयों के माध्यम से 2071 करोड़ रुपये की वसूली की गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13 प्रतिशत अधिक रही।

अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विभाग को कुल एक लाख 98 हजार 071 करोड़ रुपये का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें जीएसटी का लक्ष्य एक लाख 49 हजार 956 करोड़ रुपये तथा वैट का लक्ष्य 48 हजार 115 करोड़ रुपये है। अप्रैल 2026 में राज्य ने 10 हजार 896 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह किया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 9.6 प्रतिशत अधिक है।

गौतमबुद्ध नगर जोन ने राजस्व में 18 प्रतिशत वृद्धि

जोन वार समीक्षा में बताया गया कि अप्रैल 2026 में राज्य के अधिकांश जोनों में राजस्व वृद्धि दर्ज की गई। गौतमबुद्ध नगर जोन ने 1506 करोड़ रुपये के संग्रह के साथ 18 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की, जबकि गत वर्ष इसी अवधि के सापेक्ष इस वर्ष सहारनपुर जोन में 35.1 प्रतिशत और वाराणसी प्रथम जोन में 33.2 प्रतिशत वृद्धि रही। मुरादाबाद जोन ने भी अप्रैल 2025 के सापेक्ष अप्रैल 2026 में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की। मुख्यमंत्री ने अपेक्षाकृत कम प्रदर्शन वाले जोनों को विशेष कार्ययोजना बनाकर लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि वरिष्ठ अधिकारी स्वयं फील्ड में उतरें, व्यापारियों से संवाद करें।

जीएसटी चोरी करने वाले वालों कड़ी कार्रवाई के निर्देश

मुख्यमंत्री ने फर्जी फर्मों और कर चोरी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि बोगस फर्मों के खिलाफ 477 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई तथा 168 गिरफ्तारियां की गईं। 7 नवंबर 2025 को एसआईटी का गठन किया गया। 180 करोड़ रुपये की इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक की गई तथा न्यायनिर्णयन कार्रवाई से 2250 करोड़ रुपये की मांग सृजित हुई। अपील निस्तारण की समीक्षा के दौरान बताया गया कि वर्ष 2025-26 में जीएसटी की 52 हजार 432 और वैट की 11 हजार 365, कुल 63 हजार 797 अपीलों का निस्तारण किया गया। वर्तमान में जीएसटी की 18 हजार 504 तथा वैट की 2,193, कुल 20 हजार 697 अपीलें विचाराधीन हैं। मुख्यमंत्री ने लंबित अपीलों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश 21.82 लाख सक्रिय करदाताओं के साथ देश में सबसे अधिक जीएसटी करदाताओं वाला राज्य बन गया है। जीएसटी पंजीयन आवेदनों के निस्तारण की औसत अवधि प्रदेश में आठ दिन है, जबकि राष्ट्रीय औसत 14 दिन है। प्रदेश में 100 प्रतिशत भौतिक सत्यापन की व्यवस्था लागू है। रिटर्न दाखिले की स्थिति में भी प्रदेश राष्ट्रीय औसत से आगे है। देय तिथि तक 90 प्रतिशत से अधिक करदाता रिटर्न दाखिल कर रहे हैं।

बढ़ती महंगाई और पेट्रोल-डीजल कीमतों के खिलाफ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन

केंद्र सरकार पर साधा निशाना, महंगाई पर नियंत्रण की मांग उठाई

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

जिला कांग्रेस कमेटी शिमला शहरी ने सोमवार को देश में लगातार बढ़ रही महंगाई और पेट्रोल-डीजल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी के विरोध में उपायुक्त कार्यालय शिमला के बाहर धरना-प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व जिला कांग्रेस कमेटी शिमला शहरी के अध्यक्ष इंद्रजीत ने किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए महंगाई पर नियंत्रण की मांग उठाई।

धरने को संबोधित करते हुए इंद्रजीत सिंह ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अमृतकाल के बड़े-बड़े दावे करने वाली केंद्र सरकार जनता को राहत देने में पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ये कैसा अमृतकाल है, केंद्र सरकार कंगाल है। उन्होंने

आरोप लगाया कि केंद्र सरकार वास्तविक मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए नए-नए राजनीतिक शिगूफे छोड़ रही है। इंद्रजीत सिंह ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है और आम जनता लगातार महंगाई का बोझ झेल रही है। उन्होंने कहा कि बीते 10 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में चार बार वृद्धि हुई है, जिससे परिवहन, खाद्य सामग्री और रोजमर्रा की वस्तुओं के दामों पर सीधा असर पड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अपने करीबी उद्योगपतियों और ह्लमोदी के मित्रोंह्व के कारनामों को छिपाने के लिए जनता को भ्रमित करने की राजनीति कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि केंद्र सरकार हर मोर्चे पर असफल साबित हुई है और उसे देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक अस्थिरता के कारण आम लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है।

नाहन में भी कांग्रेस का धरना प्रदर्शन

नाहन। जिला मुख्यालय नाहन में कांग्रेस हाई कमान के आवाहन पर सिरमौर जिला कांग्रेस कमेटी ने बढ़ती महंगाई को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ सोमवार को धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान विधायक अजय सोलंकी की अगवाई में डीसी कार्यालय के बाहर मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी ने कहा कि आज लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम महंगाई को सातवें आसमान पर पहुंचा रहे हैं। आम व्यक्ति का जीना मुहाल हुआ है और मोदी सरकार लगातार जन विरोधी नीतियां ला रही है। उन्होंने कहा कि जहां एक ओर देश में जनता त्राहिमाम है बढ़ती महंगाई से लोग बेहाल हैं लगातार बढ़ते डीजल पेट्रोल के दाम सीधा लोगों की जेब पर डाका डाल रहे हैं तो वही मोदी सरकार पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही हैं।

शिमला में पेट्रोल 102 रुपये के पार

शिमला। देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार चौथी बार बढ़ोतरी होने से आम लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। राजधानी शिमला में पेट्रोल का दाम बढ़कर 102.51 रुपये प्रति लीटर और डीजल 94.50 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है। लगातार बढ़ती कीमतों का असर अब सीधे लोगों की जेब पर पड़ता दिखाई दे रहा है। पेट्रोल पंपों पर वाहन चालकों में नाराजगी देखने को मिल रही है और लोग इसे आम आदमी पर बढ़ता आर्थिक बोझ बता रहे हैं। शिमला के संजौली निवासी राजेश शर्मा का कहना है कि अगर एक बार में 2 या 3 रुपये की बढ़ोतरी होती तो लोग किसी तरह संभाल लेते, लेकिन रोजाना दाम बढ़ने से परेशानी लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नौकरीपेशा लोगों के लिए अब रोज गाड़ी चलाना महंगा होता जा रहा है।

हिमाचल के सरकारी स्कूलों को बनाया जाएगा देश में सर्वश्रेष्ठ: मुख्यमंत्री

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को नव स्तरोन्नत सीबीएसई राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, छोटा शिमला में विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों के प्रश्नों का सहजता से उत्तर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में व्यापक स्तर पर बदलाव किए हैं और इनके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे यहां भाषण देने नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के साथ बातचीत करने आए हैं ताकि शिक्षा व्यवस्था की कमियों की पहचान कर उन्हें प्रभावी ढंग से दूर किया जा सके।

संवाद के दौरान विद्यार्थियों ने सीबीएसई प्रणाली से लेकर मुख्यमंत्री के निजी अनुभवों से संबंधित अनेक प्रश्न पूछे। छात्र आरव ठाकुर ने उनके स्कूली दिनों के पसंदीदा खेल के बारे में पूछा। मुख्यमंत्री ने बताया कि वे वाद-विवाद प्रतियोगिताओं में सक्रिय रूप से भाग लेते थे और हॉकी, क्रिकेट तथा हैंडबॉल खेलते थे। उन्होंने कहा कि वे हैंडबॉल टीम के कप्तान भी रहे हैं और उन्हें ट्रैकिंग का भी शौक रहा है। उन्होंने बताया कि उनकी पहली ट्रैकिंग यात्रा टापरी से रिकांगपिओ तक थी। स्कूल के विद्यार्थी ने बताया कि वर्तमान में भौतिकी विज्ञान विषय के शिक्षक नहीं हैं और राजनीति विज्ञान के भी केवल एक ही शिक्षक हैं। विद्यार्थी ने रिक्त पदों को भरने का आग्रह किया। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह स्कूल सीबीएसई संस्थान बना है और अब इस वर्ष 30 जून से पहले सभी रिक्त पदों को भर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब विद्यार्थियों को सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत अधिक विषयों का विकल्प मिलेगा।

कक्षा 12 के छात्र दिव्यांश ने पूछा कि वर्तमान में, जब विद्यार्थी 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं, तब अंक महत्वपूर्ण हैं या कौशल! मुख्यमंत्री ने कहा कि अंक महत्त्वपूर्ण हैं, लेकिन विद्यार्थियों को इसके साथ-साथ कुशल और सक्षम व्यक्ति भी बनना चाहिए। राज्य सरकार के नशा-निवारण अभियान में युवाओं की भूमिका के महत्त्व के बारे में पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा-निवारण अभियान में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। नशे के सरगना पहले युवाओं को नशे का आदी बनाते हैं और बाद में उन्हें तस्करी के काम में शामिल कर लेते हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि 5 जून को शिमला में एंटी-चिट्टा रैली आयोजित की जाएगी। उन्होंने विद्यार्थियों से इसमें भाग लेने का आह्वान किया। कक्षा 7 की छात्रा राधा ने मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचने की उनकी जीवन यात्रा के बारे में पूछा। मुख्यमंत्री ने बताया कि जब वे कक्षा 10 में थे, तब उनके स्कूल में हड़ताल हुई थी, जिसके बाद वे 17 वर्ष की आयु में कक्षा प्रतिनिधि बने।

मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट की

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज लोक भवन में राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश में विकास एवं जनकल्याण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। बैठक के दौरान सुशासन, जनकल्याण और प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही विकासात्मक पहलों पर भी संवाद किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को हिमाचली टोपी और शॉल भेंट कर सम्मानित किया।

गणित शिक्षक भर्ती का फाइनल परिणाम घोषित 308 उम्मीदवारों का चयन

हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने शिक्षा विभाग में गणित के शिक्षकों के 312 पदों को फिक्स मानदेय के आधार पर भरने के लिए पोस्ट कोड-26003 के तहत आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच के बाद अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि इन पदों के लिए कुल 3339 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिनमें से 2792 उम्मीदवारों ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा दी थी और इस परीक्षा में 493 उम्मीदवारों का चयन दस्तावेजों की जांच के लिए किया गया था। 14 से 19 मई तक दस्तावेजों की जांच के बाद 308 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। पात्र उम्मीदवार न मिलने के कारण ओबीसी (स्वतंत्रता सेनानी परिजन) और एससी (स्वतंत्रता सेनानी परिजन) के 2-2 पद खाली रह गए हैं।

सतवारी गिरोह संघर्ष में दो भाई घायल तीन गिरफ्तार, पिस्तौल जब्त

एजेंसी (हि.स.)
जम्मू

देर रात जम्मू के सतवारी थाना क्षेत्र के हरिपुर, फल्लैन मंडल इलाके में रिंग रोड पर प्रतिद्वंद्वी गिरोह के हमले में दो भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने सतवारी थाना में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर अपराध में शामिल तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। हमले में इस्तेमाल की गई पिस्तौल भी जब्त कर ली गई है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार घायल भाई जिनकी पहचान पारस शर्मा और ऋषु शर्मा के रूप में हुई है जो पवन कुमार के पुत्र और सुर चक, मंडल निवासी हैं, देर रात करीब 8 बजे हरिपुर, फल्लैन मंडल इलाके में स्कॉर्पियो वाहन में यात्रा कर रहे थे तभी गुगली गिरोह के सदस्यों ने कथित तौर पर उन्हें रोक लिया। गुगली गिरोह का

सरगना हैप्पी चौधरी उर्फ गुगली है। हमलावरों ने कथित तौर पर वाहन का रास्ता रोक दिया और भाइयों पर धारदार हथियारों से हमला किया और उन पर गोलियां भी चलाईं जिससे इलाके में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज ले गई जहां से सिर और पैर में गंभीर चोटों को देखते हुए उन्हें आगे के इलाज के लिए अमृतसर के एक अस्पताल में रेफर कर दिया गया। घटना के बाद पुलिस ने सतवारी पुलिस स्टेशन में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर घटना में शामिल सभी लोगों की तलाश शुरू कर दी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि अब तक राजिंदर कुमार उर्फ बब्बू, रघुवीर और शिवम चौधरी नाम के तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कथित तौर पर अपराध में इस्तेमाल की गई पिस्तौल भी जब्त कर ली गई है। उन्होंने बताया कि मुख्य आरोपी हैप्पी चौधरी उर्फ गुगली समेत बाकी आरोपियों को गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं। सूत्रों के अनुसार यह झड़प दो गुटों के बीच पुरानी दुश्मनी का नतीजा थी जो लगभग पांच साल पहले बुरे चक गांव में होली के दौरान हुए विवाद से शुरू हुई थी। तब से प्रतिद्वंद्वी गुटों के बीच कई हमले और झड़पें हो चुकी हैं।

सूत्रों ने आगे बताया कि हैप्पी चौधरी को हाल ही में सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत उनकी हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद लगभग एक महीने पहले जेल से रिहा किया गया था

संक्षिप्त-समाचार

विकास खंड पच्छाद के दो मतदान केंद्र में संशोधन

नाहन। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि विकास खंड पच्छाद की ग्राम पंचायत शाड़िया के दो मतदान केंद्रों में संशोधन किया गया है। उन्होंने बताया कि विकास खंड पच्छाद की ग्राम पंचायत शाड़िया के वार्ड नं0-1 मासरिया पंजोपड़-1 के मतदान केंद्र राजकीय प्राथमिक पाठशाला शोटी, कमरा नं0-1 के स्थान पर अब संशोधन उपरांत राजकीय प्राथमिक पाठशाला शाड़िया कमरा नं0-2 तथा वार्ड नं0-5 मासरिया पंजोपड़-ए के मतदान केंद्र राजकीय प्राथमिक पाठशाला शाड़िया, कमरा नं0-2 के स्थान पर राजकीय प्राथमिक पाठशाला शोटी कमरा नं0-1 में परिवर्तित किया गया है।

हिमाचल में बकरीद की सरकारी छुट्टी 27 की बजाय अब 28 मई को, अधिसूचना जारी

शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ईद-उल-जुहा (बकरीद) की छुट्टी को लेकर नई अधिसूचना जारी की है। सरकार ने पहले 27 मई बुधवार को घोषित गजटेड अवकाश में बदलाव करते हुए अब 28 मई गुरुवार को सरकारी छुट्टी घोषित की है। मुख्य सचिव की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 23 अक्तूबर 2025 को जारी अवकाश सूची में संशोधन किया गया है। इसके तहत अब हिमाचल प्रदेश में बकरीद का गजटेड अवकाश 27 मई की जगह 28 मई को रहेगा। सरकार ने यह फैसला त्योहार की तारीख में बदलाव के चलते लिया है। बता दें कि पहले वर्ष 2026 की सरकारी छुट्टियों की सूची में बकरीद का अवकाश 27 मई को रखा गया था। बाद में चांद दिखने और त्योहार की तारीख तय होने के बाद कई राज्यों की तरह हिमाचल सरकार ने भी छुट्टी की तारीख बदल दी। अब प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम और शिक्षण संस्थान 28 मई को बंद रहेंगे।

आज और कल केंद्र शासित प्रदेश में मौसम आम तौर पर गर्म और शुष्क रहने की संभावना

श्रीनगर। श्रीनगर मौसम विज्ञान केंद्र ने 25 मई की सुबह जम्मू और कश्मीर में आम तौर पर शुष्क मौसम का पूर्वानुमान लगाया है। दोपहर और शाम के समय छिटपुट स्थानों पर हल्की बारिश, तेज हवाएं और ओलावृष्टि की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 26 और 27 मई को केंद्र शासित प्रदेश में मौसम आम तौर पर गर्म और शुष्क रहने की संभावना है। विभाग ने बताया कि 28 से 29 मई तक जम्मू और कश्मीर में आम तौर पर बादल छाए रहने की संभावना है साथ ही छिटपुट से लेकर व्यापक स्थानों पर एक या दो बार बारिश, गरज के साथ बौछारें, ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने की संभावना है। 30 मई से 3 जून तक मौसम आम तौर पर शुष्क रहने की संभावना है हालांकि शाम के समय छिटपुट स्थानों पर हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। मौसम विभाग ने अपनी सलाह में चेतावनी दी है कि 28 और 29 मई को कुछ स्थानों पर गरज, बिजली, ओलावृष्टि और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है।

झेलम नदी में कूदे युवक का शव छह दिन बाद शाल्टेंग ब्रिज के पास बरामद

श्रीनगर। इस सप्ताह की शुरूआत में श्रीनगर के बुदशाह ब्रिज से झेलम नदी में कूदे युवक का शव सोमवार को शाल्टेंग ब्रिज के पास नदी से बरामद किया गया। एक अधिकारी ने बताया कि एक पुलिस दल ने नदी में शव को देखा और बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया। बाद में उसकी पहचान उस युवक के रूप में की गई, जिसने 20 मई को बुडशाह ब्रिज से छलांग लगा दी थी। इसके बाद एसडीआरएफ, पुलिस और सेना के मार्कोस गहरे गोताखोरों को शामिल करते हुए बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चलाया गया था। मृतक की पहचान बेमिना के हमदानिया कॉलोनी निवासी गुलाम मोहम्मद डार के बेटे जावेद अहमद डार (20) के रूप में हुई है।

जम्मू-कश्मीर में 29 मई को ईद-उल-अजहा के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश घोषित

जम्मू। जम्मू-कश्मीर सरकार ने ईद-उल-अजहा मनाने के इच्छुक केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों के लिए 29 मई (शुक्रवार) को एक दिन की विशेष आकस्मिक छुट्टी मंजूर की है। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के अनुसार पूरे जम्मू और कश्मीर में धार्मिक त्योहार मनाने के संबंध में छुट्टी दी गई है। सरकार के आयुक्त सचिव एम. राजू (आईएएस) के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया है कि विशेष आकस्मिक अवकाश उन कर्मचारियों पर लागू होगा, जो ईद-उल-अजहा के अवसर पर छुट्टी का लाभ उठाने का इरादा रखते हैं। आदेश की प्रतियां सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, उपायुक्तों और अन्य संबंधित प्राधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई और वितरण के लिए भेज दी गई हैं।

सरकार ने सूचना विभाग में 17 सूचना अधिकारियों को नियमित और पदोन्नत किया

जम्मू। जम्मू और कश्मीर सरकार ने सोमवार को सूचना विभाग में 17 प्रभारी सूचना अधिकारियों और सहायक सूचना अधिकारियों को सूचना अधिकारी और समकक्ष पदों पर नियमित करने और पदोन्नत करने का आदेश दिया। सूचना विभाग द्वारा जारी सरकारी आदेश संख्या 17-जेके(आईडी) दिनांक 25 मई, 2026 के अनुसार पदोन्नत अधिकारियों को वेतन स्तर-8 (47,600-1,51,100) में रखा गया है। पदाधिकारियों में शौकत अहमद खान, रियाज अहमद फजिली, परशोत्तम दास, राजिंदर पॉल सिंह, गुलशन सुम्ब्रिया, मजीब अहमद गनई, गुलशन आरा, अशोक कुमार शर्मा, सैयद गुलाम जीलानी कादिरी, शब्बीर अहमद भट, गुरप्रीत सिंह, लियाकत अली मीर, मोहम्मद ओवैस गुरकू, नाट्यपाल सिंह, परवेज अहमद लोन, सज्जाद अहमद शाह और हरदीप सिंह चौधरी शामिल हैं।

हिमाचल में बढ़ी तपिश, आधे प्रदेश में अगले दो दिन लू का अलर्ट

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

हिमाचल प्रदेश में मई के आखिरी सप्ताह में उमस भरी गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। राज्य के निचले और मैदानी इलाकों में तेज गर्मी कहर बरपा रही है। दिन के साथ अब रातें भी गर्म होने लगी हैं। पिछले दो दिनों से कई इलाकों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। राजधानी शिमला और पर्यटन नगरी मनाली जैसे हिल स्टेशनों में भी गर्मी की तपिश महसूस की जा रही है और तापमान सामान्य से अधिक दर्ज हो रहा है। सोमवार को शिमला सहित प्रदेशभर में मौसम साफ है और तेज धूप खिली है।

मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिन प्रदेश के कई जिलों में लू चलने की संभावना है। 26 मई को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और सोलन जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अगले दिन 27 मई को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सिरमौर और सोलन जिलों में भी लू चलने का येलो अलर्ट रहेगा।

विभाग ने लोगों को दोपहर के समय धूप में निकलने से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है।

हालांकि 28 मई से मौसम करवट लेने के आसार हैं। मौसम विभाग का कहना है कि एक नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय होने जा रहा है। इसके असर से प्रदेश में मौसम बदल जाएगा। 28, 29 और 30 मई को कई इलाकों में आंधी, बारिश और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 28 और 29 मई को ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम में इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। 31 मई को भी प्रदेश के कुछ भागों में हल्की बारिश का अनुमान जताया गया है, हालांकि उस दिन कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है।

मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार सोमवार सुबह शिमला का न्यूनतम तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.3 डिग्री अधिक रहा। सुंदरनगर में 17.6, भुंतर में 14.2, कल्पा में 8.6, धर्मशाला में 19.2, ऊना में 18.6, नाहन में 22.8, केलांग में 4.6, पालमपुर में 18.5, सोलन में 17.4, मनाली में 12.7, कांगड़ा में 20.4, मंडी में 18.6 और बिलासपुर में 21 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा जुब्बड़हट्टी में 22, कुफरी में 13.4, कुकुमसेरी में 4.6, सेओबाग में 10.4, बरठीं में 15.8, पांवटा साहिब में 26, सराहन में 16.3, देहरा गोपीपुर में 22, ताबो में 7.4 और नेरी में 22.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया।

मासूम को उलझाकर मोबाइल ले उड़ा शातिर चोर वारदात सीसीटीवी में कैद

नाहन। जिला मुख्यालय नाहन के अमरपुर मोहल्ला (वार्ड नंबर-4) में चोरी की एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहां एक शातिर चोर ने दुकान पर बैठे मासूम बच्चे को बातों में उलझाकर काउंटर पर रखा मोबाइल फोन चोरी कर लिया। मामले में गुन्नूघाट पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार, 15 मई को अमरपुर मोहल्ला स्थित एक दुकान पर एक छोटा बच्चा अकेला बैठा था। उसके पिता किसी निजी कार्य से पास के बाजार गए हुए थे। इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ग्राहक बनकर दुकान पर पहुंचा और बच्चे से अंडे देने को कहा। जैसे ही बच्चा अंडे लेने के लिए दुकान के पीछे की ओर गया, आरोपी ने मौके का फायदा उठाते हुए काउंटर पर रखा मोबाइल फोन उठा लिया और वहां से फरार हो गया। बच्चे को जब तक घटना का एहसास हुआ, तब तक आरोपी काफी दूर निकल चुका था। घटना की सूचना मिलते ही पीड़ित परिवार ने गुन्नूघाट पुलिस चौकी में शिकायत दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें आरोपी की शक्ल और हुलिया साफ दिखाई दे रहा है। पुलिस तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर सीडीआर और मोबाइल टावर डंप डाटा भी खंगाल रही है।

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने समारोह से पहले हजरतबल दरगाह का दौरा किया

एजेंसी (हि.स.)
श्रीनगर

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने त्योहार समारोह से पहले लोगों के लिए किए गए इंतजामों की समीक्षा करने के लिए सोमवार को हजरतबल दरगाह का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान बोलते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन ने यह सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम संभव व्यवस्था की है कि लोग भाईचारे के त्योहार को सहज और शांतिपूर्ण माहौल में मनाएं। उन्होंने कहा, ₹मैं यहां इंतजाम देखने आया था ताकि लोग भाईचारे का त्योहार खुशी से मना सकें। प्रशासन ने बेहतरीन इंतजाम करने की कोशिश की है।₹ उपराज्यपाल ने चल रहे ₹नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान₹ में धार्मिक नेताओं की भूमिका की भी सराहना की और कहा कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ जागरूकता फैलाने और युवाओं को बेहतर भविष्य के लिए मार्गदर्शन करने में उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा है। उपराज्यपाल के साथ आए अधिकारियों ने उन्हें सुरक्षा, स्वच्छता, यातायात प्रबंधन, स्वास्थ्य सुविधाओं और पवित्र मस्जिद में आने वाले लोगों के लिए की गई अन्य व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी।

मुख्यमंत्री उमर ने सीपीडब्ल्यू को नियमितीकरण के आदेश सौंपे

एजेंसी (हि.स.)
श्रीनगर

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को गांदरबल और बांदीपोरा जिलों के स्कूल शिक्षा विभाग के आकस्मिक वेतनभोगी कर्मचारियों (सीपीडब्ल्यू) को नियमितीकरण आदेश सौंपे। शिक्षा मंत्री सकीना इटू की उपस्थिति में नियमितीकरण आदेश वितरित किये गये। एक्स पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री ने आज सकीना इटू की उपस्थिति में गांदरबल और बांदीपोरा जिलों के स्कूल शिक्षा विभाग के आकस्मिक वेतनभोगी श्रमिकों (सीपीडब्ल्यू) को नियमितीकरण आदेश सौंपे। पोस्ट में लिखा है कि मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि ये कर्मचारी स्कूल शिक्षा विभाग को मजबूत करने और सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार के लिए ईमानदारी, प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ काम करना जारी रखेंगे।

आरोप | सुक्खू सरकार पर चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप

भाजपा ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई की मांग

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने हिमाचल प्रदेश में चल रहे नगर निकाय और पंचायती राज चुनावों के दौरान कांग्रेस की सुक्खू सरकार पर आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन, सत्ता के दुरुपयोग और चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोप लगाते हुए राज्यपाल को विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल की अध्यक्षता व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की मौजूदगी में पार्टी के एक प्रतिनिधमंडल द्वारा सोमवार को दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान राज्य सरकार ऐसे फैसले ले रही है, जिनसे लोकतांत्रिक व्यवस्था और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

भाजपा ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं, जिला परिषद, बीडीसी और नगर निकायों से जुड़े चुनाव चल रहे हैं और पूरे प्रदेश में

आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है। इसके बावजूद सरकार द्वारा प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं, जिनसे चुनावी माहौल प्रभावित हो रहा है। ज्ञापन में कहा गया है कि चुनावी प्रक्रिया के बीच चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के चुनावों को प्रभावित करने के लिए नियमों और अधिसूचनाओं में बदलाव की चर्चाएं भी सामने आई हैं, जो लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ हैं। भाजपा ने अपने ज्ञापन में संविधान के अनुच्छेद 243-ड और 243-अ का उल्लेख करते हुए कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव स्वतंत्र और समयबद्ध तरीके से करवाना संवैधानिक जिम्मेदारी है। पार्टी ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका का भी हवाला दिया, जिसमें चुनावी प्रक्रिया में देरी और हस्तक्षेप का मुद्दा उठाया गया है। भाजपा का कहना है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों पर दबाव बनाने और प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल कर चुनाव परिणामों को प्रभावित करने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। ज्ञापन में भाजपा ने 22 मई को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक पर भी सवाल उठाए हैं। पार्टी का कहना है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बावजूद कैबिनेट बैठक में कई ऐसे फैसले लिए गए, जिनका सीधा असर मतदाताओं, कर्मचारियों, महिलाओं और युवाओं पर पड़ता है। इनमें इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना में बदलाव, महिलाओं को आय सीमा के आधार पर 1500 रुपये देने का फैसला, विभिन्न विभागों में 2215 पद भरने की मंजूरी, 1500 शिक्षकों की भर्ती, कर्मचारियों के मानदेय और वेतन में बढ़ोतरी, प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के लिए आयोग गठन और नए कार्यालय खोलने जैसे फैसले शामिल हैं।

भाजपा ने आरोप लगाया कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान इस तरह की घोषणाएं और वित्तीय लाभ से जुड़े फैसले मतदाताओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से किए गए हैं। पार्टी ने कहा कि प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन, नए एसडीएम कार्यालयों की मंजूरी और नई घोषणाओं का चुनावी माहौल पर असर पड़ सकता है।

दैनिक सिटी दर्पण आईना सच का
न्वोन्मेषक: स्व. कृष्णा शर्मा
स्व. गीता शर्मा
संस्थापक: स्व. सतपॉल शर्मा
स्वामी, प्रकाशक मुद्रक एवं संपादक भूपिंद्र शर्मा द्वारा इंप्रेशन्ज प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, प्लॉट नं. 22, ग्राउंड फ्लोर, फेस-2, इंडस्ट्रियल एरिया, पंचकूला-134113 (हरियाणा) पर मुद्रित एवं 801/1, सेक्टर 40ए, चंडीगढ़ से प्रकाशित-160036
सभी विवादों का केंद्र न्यायालय चंडीगढ़ होगा।
स्थानीय कार्यालय
801/1, सेक्टर-40ए, चंडीगढ़।
संपर्क: 7888450261
Email: citydarpan1@gmail.com

पुलिस भर्ती व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने स्वयं पहुंचे नायब सैनी

मुख्यमंत्री ने ताऊ देवी लाल स्टेडियम में पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों से की मुलाकात, बढ़ाया मनोबल

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज सेक्टर-3 स्थित ताऊ देवी लाल स्टेडियम में पुलिस भर्ती के लिए आयोजित शारीरिक माप परीक्षण (पीएमटी) में शामिल अभ्यर्थियों से मुलाकात कर वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया।

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ताऊ देवी लाल स्टेडियम में पुलिस कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थियों की शारीरिक माप परीक्षण आयोजित की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने परीक्षा में भाग ले रहे अभ्यर्थियों के बीच पहुंचकर उनसे संवाद किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने अभ्यर्थियों से प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं को लेकर फीडबैक भी लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अभ्यर्थियों और उनके परिजनों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि व्यवस्थाओं का जायजा लेने और अभ्यर्थियों का उत्साहवर्धन करने के उद्देश्य से वे स्वयं स्टेडियम पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरी पीएमटी प्रक्रिया को पारदर्शी, सुव्यवस्थित एवं अभ्यर्थी-अनुकूल बनाने के लिए व्यापक स्तर पर व्यवस्थाएं की गई हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों के साथ आए परिजनों से भी मुलाकात की और उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर अभ्यर्थी खासे उत्साहित नजर आये। कई अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी भी ली। मुख्यमंत्री ने भी आत्मीयता से उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए उनका मनोबल बढ़ाया। अभ्यर्थियों एवं उनके परिजनों ने मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं पहुंचकर व्यवस्थाओं की जानकारी लेने और उनका उत्साहवर्धन करने की सराहना की। उन्होंने इसे संवेदनशील एवं प्रेरणादायक पहल बताया।

ताऊ देवी लाल स्टेडियम में प्रतिदिन लगभग 3 हजार अभ्यर्थियों की शारीरिक माप परीक्षण का आयोजन किया जा रहा है। अभ्यर्थियों एवं उनके परिजनों की सुविधा के लिए स्टेडियम के प्रवेश द्वार पर विश्राम क्षेत्र बनाया गया है, जहां बैठने की समुचित व्यवस्था की गई है। इसके अलावा बैगेज जमा कराने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।

इस अवसर पर उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा, पुलिस उपायुक्त श्रीमती सृष्टि गुप्ता, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य, अभ्यर्थी एवं उनके परिजन उपस्थित रहे।

हेल्प डेस्क पर मिल रही सुपवा में दाखिले की जानकारी, डिजाइन फैकेल्टी में चल रहा एडमिशन हेल्प डेस्क

सिटी दर्पण संवाददाता
रोहतक

26 जून तक कर सकेंगे यूजी कोर्सेज में दाखिल के लिए आवेदन

दादा लख्मी चंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स (डीएलसीसुपवा) में एडमिशन प्रोसेस की जानकारी देने के लिए हेल्प डेस्क बनाया गया है। इस पर लगातार पहुंच रहे छात्रों व उनके अभिभावकों को विभिन्न कोर्स में दाखिले की प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है। उन्हें बताया जा रहा है कि 26 जून सुपवा में यूजी कोर्सेज में ऑनलाइन आवेदन करने का अंतिम दिन है।

सुपवा पहुंचने वाले छात्र व उनके अभिभावकों को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसे ध्यान में रखते हुए हेल्प डेस्क बनाया गया है। जो छात्र किसी कारण से खुद ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते, उनके आवेदन भी यहीं पर कराने का इंतजाम किया गया है।

हेल्प डेस्क पर प्रत्येक फैकेल्टी से दो-दो स्टाफ सदस्य तैनात किए गए हैं, ताकि वे अपनी फैकेल्टी व इसके तहत चल रहे विभागों की संपूर्ण जानकारी आगंतुकों को दे सकें। सोमवार को डीन अकेडमिक अफेयर्स डॉ अजय कौशिक व विजुअल आर्ट्स फैकेल्टी के एफसी विनय कुमार ने हेल्प डेस्क का दौरा किया और मौजूद स्टाफ सदस्यों को टिप्स भी दिए।

डॉ अजय कौशिक ने बताया कि हेल्प डेस्क सुबह 9 से शाम 5 बजे तक कार्यरत रहता है। इसके साथ ही अलग-अलग फैकेल्टी के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए चार मोबाइल नंबर व चार लैंड लाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। इन पर छात्र व अभिभावक दाखिले के संबंध में जानकारी लेने के साथ ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने या फिर फीस जमा कराने के दौरान आने वाली किसी भी समस्या के बारे में बात कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि कुलगुरु डॉ अमित आर्य के निर्देश पर एडमिशन प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ चलाया जा रहा है। ऐसे में छात्रों को रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख का इंतजार करने की बजाए जल्द ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, ताकि यूनिवर्सिटी अपने शेड्यूल के मुताबिक एडमिट कार्ड जारी करके प्रवेश परीक्षा व स्किल टेस्ट ले सके।

मृत शिक्षकों के ऋण माफी मामलों के त्वरित निपटान के दिए निर्देश

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

किसी भी लापरवाही के लिए संबंधित अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे

हरियाणा के मौलिक शिक्षा निदेशालय ने राज्य के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर मृत शिक्षकों के ऋण माफी (ह्वंप्ी ड्डाा) मामलों के त्वरित और सटीक निपटान के निर्देश दिए हैं। विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि अक्सर शिक्षा विभाग के जिला कार्यालयों से मृत कर्मचारियों के ऋण संबंधी मामले बिना उचित निरीक्षण के निदेशालय भेज दिए जाते हैं, जिससे मामलों के निपटान में अनावश्यक देरी होती है और विभाग व सरकार पर वित्तीय भार पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए सहायक निदेशक (ऑडिट व लेखा शाखा) ने सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि भविष्य में किसी भी शिक्षक की मृत्यु के बाद उनके ऋण की राशि को माफ करने से पहले कार्यालय के अनुभाग अधिकारी से राशि को अच्छी तरह सत्यापित और वैरीफाई कराया जाए। इसके साथ ही, यदि मृतक कर्मचारी ने पंजाब नेशनल बैंक से ऋण लिया है, तो उसकी गणना भी बैंक से सत्यापित करवानी अनिवार्य होगी। इस प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए निदेशालय ने निर्देश दिए हैं कि संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा यह स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए कि मृतक कर्मचारी ने कुल कितना ऋण लिया था और वर्तमान में कितनी राशि बकाया है। ऋण की मूल राशि और उस पर लगने वाले ब्याज की पूरी गणना एक निर्धारित प्रारूप के अनुसार निदेशालय भेजी जानी चाहिए, ताकि मामलों का शीघ्र निपटान हो सके और भविष्य में किसी भी प्रकार के अनावश्यक कानूनी विवाद से बचा जा सके। विभाग ने अधिकारियों को सचेत किया है कि इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

हरियाणा में यात्रियों की सुविधा, स्वच्छता और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा: अनिल विज

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा के परिवहन मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि अब राज्य के बस अडडों पर यात्रियों की आवाजाही, स्वच्छता एवं सुरक्षा में किसी भी प्रकार की बाधा स्वीकार नहीं की जाएगी। साथ ही, बस अड्डों पर अवैध कब्जों, अतिरिक्त काउंटरों, रेहड़ी-फड़ी और अनधिकृत गतिविधियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बताया कि प्रदेश के सभी बस अड्डों पर अतिक्रमण रोकने तथा यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। गौरतलब है कि यह निर्देश गत दिनों परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में दिए गए आदेशों के अनुपालना में परिवहन विभाग के महानिदेशक द्वारा हरियाणा रोडवेज के सभी महाप्रबंधकों को जारी किए गए हैं। परिवहन मंत्री अनिल विज ने स्पष्ट तौर पर कहा कि बस अड्डे आमजन की सुविधा के लिए होते हैं और वहां यात्रियों की आवाजाही, स्वच्छता एवं सुरक्षा में किसी भी प्रकार की बाधा स्वीकार नहीं की जाएगी और बस अड्डों पर अवैध कब्जों, अतिरिक्त काउंटरों, रेहड़ी-फड़ी और अनधिकृत गतिविधियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

श्री विज ने जारी निर्देशों के अनुसार बताया कि कोई भी दुकानदार, वेंडर अथवा अन्य व्यक्ति बस अड्डे के प्लेटफॉर्म, सड़क, फुटपाथ, प्रतीक्षालय या सार्वजनिक स्थान पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करेगा। दुकान से संबंधित सामान जैसे रैक, फ्रिज, क्रेट, टेबल, बेंच, बोर्ड अथवा अन्य सामग्री केवल निर्धारित दुकान क्षेत्र के भीतर ही रखी जा सकेगी। इसके अलावा, अस्थायी स्टॉल, फेरी लगाने वाले, अनधिकृत विक्रेता तथा दुकान के बाहर अतिरिक्त काउंटर लगाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। दुकानदारों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वे यात्रियों, बसों, आपातकालीन वाहनों अथवा सफाई व्यवस्था में किसी भी प्रकार की रुकावट उत्पन्न न करें।

परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि बिना अनुमति अतिरिक्त विद्युत उपकरण या अवैध बिजली कनेक्शन लगाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि बस अड्डों पर नियमित निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी प्रकार का अतिक्रमण पाए जाने पर तुरंत उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी जाए। श्री विज ने बताया कि निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाया जाएगा। आवश्यक होने पर जुमार्ना, दुकान आवंटन रद्द करना, दुकान सील करना अथवा सामान जब्त करने जैसी कार्रवाई भी की जा सकेगी। परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश के बस अड्डों को स्वच्छ, व्यवस्थित, सुरक्षित एवं आधुनिक बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है और इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

संक्षिप्त-समाचार

आज पंचकूला जिला के उपभोक्ताओं की बिजली सम्बन्धी शिकायतों की होगी सुनवाई

चंडीगढ़। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली की आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है । उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं । उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम सर्कल फोरम पंचकूला के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के चेयरमैन एवं सदस्य मंच की कार्यवाही 26 मई को अधीक्षण अभियंता, पंचकूला के कार्यालय में की जाएगी । इस दौरान केवल पंचकूला जिला के उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई की जाएगी। मंच के सदस्य, पंचकूला जिले के उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई करेंगे इनमें मुख्यतः बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग से सम्बंधित शिकायतें, कनैक्शन काटने और जोड़ने बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं । बहरहाल, मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 से 139 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनधिकृत उपयोग के मामलों में दंड तथा जुमार्ना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से सम्बंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी।

सुरक्षित महिला ही सशक्त समाज की आधारशिला: प्रो. सोमनाथ सचदेवा

कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. सोमनाथ सचदेवा के मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय में कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और समानता सुनिश्चित करने की दिशा में एक प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत किया है। विश्वविद्यालय की आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) ने वर्ष 2025 में ऐसा सुरक्षित, संवेदनशील और विश्वासपूर्ण वातावरण विकसित किया, जहाँ पूरे वर्ष यौन उत्पीड़न से संबंधित एक भी शिकायत दर्ज नहीं हुई। यह उपलब्धि केवल प्रशासनिक सफलता नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित पारदर्शिता, जागरूकता और मानवीय मूल्यों की सशक्त अभिव्यक्ति मानी जा रही है। कुलगुरु प्रो. सोमनाथ सचदेवा ने बताया कि आंतरिक शिकायत समिति केवल शिकायतों के निवारण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य महिलाओं के लिए ऐसा शैक्षणिक एवं कार्यस्थलीय वातावरण तैयार करना है, जहाँ वे पूर्ण सम्मान, आत्मविश्वास और सुरक्षा के साथ कार्य एवं अध्ययन कर सकें। समिति द्वारा महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण के लिए प्रभावी नीतियाँ लागू की गई हैं तथा शिकायतों के निष्पक्ष, गोपनीय और समयबद्ध समाधान हेतु मजबूत तंत्र विकसित किया गया है। आंतरिक शिकायत कमेटी की चेयरपर्सन प्रो. सुनीता सिरोहा ने बताया कि किसी भी शिक्षण संस्थान की वास्तविक पहचान केवल शैक्षणिक उपलब्धियों से नहीं, बल्कि उसके मानवीय और सामाजिक मूल्यों से होती है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ऐसा वातावरण निर्मित कर रहा है, जो हर छात्रा, शोधार्थी, शिक्षिका और कर्मचारी में विश्वास और आत्मबल पैदा करता है। प्रो. सुनीता सिरोहा ने बताया कि महिला सुरक्षा और लैंगिक समानता को व्यवहारिक रूप देने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय में वर्षभर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशालाएँ, व्याख्यान, संवाद सत्र एवं प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों के माध्यम से ह्लकार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम-2013ह्व की जानकारी दी गई तथा सभी वर्गों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक किया गया। लोक सम्पर्क विभाग के निदेशक प्रो. महासिंह पूनिया ने बताया कि आंतरिक शिकायत समिति द्वारा आयोजित जेंडर सेंसिटाइजेशन विषयक विशेष व्याख्यानों ने विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों में संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व की भावना को मजबूत किया। विशेष रूप से छात्राओं और वंचित वर्ग की महिलाओं के लिए आयोजित जागरूकता सत्रों में महिला सुरक्षा से जुड़े कानूनी अधिकारों और सहायता तंत्र की जानकारी देकर उनमें आत्मविश्वास का संचार किया गया। उन्होंने कहा कि जब संस्थान संवेदनशीलता, समानता और सम्मान को अपनी कार्य संस्कृति का हिस्सा बना लेते हैं, तब सुरक्षित और सशक्त समाज की मजबूत नींव तैयार होती है।

बुजुर्गों के लिए शुरू होगा 'वृद्ध सेवा एवं स्वास्थ्य' पोर्टल : आरती राव

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा की स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान एवं आयुष मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि राज्य में नागरिकों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर और समग्र स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए जल्द ही दो बड़ी कल्याणकारी योजनाओं की शुरूआत की जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार बुजुर्गों के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर जीवन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्य के सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में हर सप्ताह गुरुवार को विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे।

इन स्वास्थ्य शिविरों के डेटा की सटीक मॉनिटरिंग और प्रबंधन के लिए 'वृद्ध सेवा एवं स्वास्थ्य' पोर्टल विकसित किया गया है, इसको जल्द ही लांच किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य राज्यभर के बुजुर्गों को मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं की पारदर्शी निगरानी करना है। आरती सिंह राव ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुदृढ़, निवारक और समग्र बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक विशेष कार्यक्रम संजीवनी योग शुरू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत ओपीडी और वेटिंग एरिया में जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए आयुष डॉक्टरों और योग सहायकों के माध्यम से योग सत्र, प्राणायाम और स्वस्थ जीवन शैली के संबंध में मार्गदर्शन दिया जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि आईपीडी वार्ड यानि अस्पतालों में भर्ती मरीजों को स्वास्थ्य विभाग के संबंधित चिकित्सा अधिकारियों और डॉक्टरों की सलाह पर विशेष योग थेरेपी और लाइफस्टाइल काउंसिलिंग (परामर्श) प्रदान की जाएगी।

उन्होंने बताया कि उक्त महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर उतारने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं , जल्द ही 'वृद्ध सेवा एवं स्वास्थ्य' पोर्टल और 'संजीवनी योग ' कार्यक्रम का आधिकारिक रूप से भव्य शुभारंभ किया जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्री ने दोहराया कि योग, प्राणायाम और आधुनिक चिकित्सा का यह अनूठा संगम हरियाणा को एक स्वस्थ और निरोगी प्रदेश बनाने में मील का पत्थर साबित होगा।

कुमारी सैलजा ने पेट्रोल-डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों पर भाजपा सरकार को घेरा

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

सिरसा की सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की सदस्य एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी सैलजा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार महंगाई बढ़ाकर आम जनता की कमर तोड़ने का काम कर रही है। पिछले 11 दिनों में चार बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर सरकार ने आम आदमी, किसान, मजदूर, व्यापारी और मध्यम वर्ग पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल दिया है।

कुमारी सैलजा ने कहा कि पेट्रोल-डीजल की कीमतों में हुई लगभग 08 रुपये की वृद्धि ने हर घर का बजट बिगाड़ दिया है। ईंधन महंगा होने से परिवहन, खाद्य सामग्री, खेती-किसानी और रोजमर्रा की वस्तुओं की लागत भी बढ़ती है, जिसका सीधा असर जनता की जेब पर पड़ता है। सांसद ने कहा कि भाजपा सरकार अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का बहाना बनाकर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। सच्चाई यह है कि केंद्र सरकार लगातार टैक्स और वेट के माध्यम से जनता से वसूली कर रही है, जबकि निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने की नीतियां अपनाई जा रही हैं।

सांसद कुमारी सैलजा उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है कि सरकार को जनता पर बोझ डालने के बजाय राहत देने की दिशा में कदम उठाने चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों को पेट्रोल-डीजल पर लगने वाले वेट और एक्साइज ड्यूटी में तत्काल कमी करनी चाहिए ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। कुमारी सैलजा ने कहा कि भाजपा सरकार की आर्थिक नीतियों का सबसे अधिक नुकसान गरीब, किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग को उठाना पड़ रहा है। महंगाई लगातार बढ़ रही है लेकिन लोगों की आय नहीं बढ़ रही। ऐसे में सरकार का दायित्व बनता है कि वह जनता के हितों को प्राथमिकता दे, न कि कुछ निजी कंपनियों के मुनाफे को।

सांसद कुमारी सैलजा ने लगातार हो रहे ईंधन के दाम में इजाफा को आम जनता के लिए महंगाई का साइलेंट टैक्स करार दिया है। कुमारी सैलजा ने कहा कि वैश्विक कच्चे तेल के दाम स्थिर होने के बावजूद घरेलू स्तर पर तेल कंपनियों को भारी मुनाफा हो रहा है और कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। सांसद ने आरोप लगाया कि सरकार को सिर्फ तेल कंपनियों के फायदे की चिंता है।

विरासत का संरक्षक बना ज्ञान भारतम मिशन

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

- हरियाणा से 27 हजार से अधिक पांडुलिपियां अपलोड
- मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने की प्रगति की समीक्षा

हरियाणा ने ज्ञान भारतम मिशन के तहत अब तक कुल 27,587 पांडुलिपियां अपलोड की हैं। यह राज्य की समृद्ध बौद्धिक, सांस्कृतिक और दस्तावेजी विरासत के संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम है। राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने कहा कि पांडुलिपियों का संरक्षण केवल अभिलेखीकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सदियों पुराने ज्ञान, परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने का महत्वपूर्ण प्रयास है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की पहल भारत की समृद्ध बौद्धिक विरासत को संरक्षित करने के साथ-साथ शोधकर्ताओं और विद्वानों के लिए इसे अधिक सुलभ बनाएगी। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने विभिन्न जिलों में चल रहे सर्वेक्षण कार्य का आकलन किया और सभी विभागों को जन-जागरूकता और दस्तावेजीकरण के प्रयासों में और तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उपलब्ध बहुमूल्य पांडुलिपियों का व्यापक दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकारी विभागों, शिक्षण संस्थानों और जिला प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण के क्रियान्वयन के लिए अभिलेखागार विभाग को राज्य नोडल विभाग नामित किया गया है। इस पहल के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्थायी समिति का गठन किया गया है। इसके अलावा, सर्वेक्षण प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सभी जिलों में जिला स्तरीय समितियां और नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। अभिलेखागार विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. साकेत कुमार ने बताया कि सर्वेक्षण की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी और जिला स्तर पर समन्वय किया जा रहा है।

एचएसवीपी की लापरवाही पर सेवा का अधिकार आयोग सख्त, प्लॉट विकास कार्य बिना ई-ऑक्शन पर जताई नाराजगी

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

आयोग ने आवंटी को 5,000 रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए, एचएसवीपी को 15 दिन में भुगतान के निर्देश

हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने फरीदाबाद स्थित प्लॉट संख्या-47, सेक्टर-89 के आवंटी श्री आयुष कटारिया की शिकायत पर सुनवाई करते हुए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर गंभीर टिप्पणी की है। शिकायतकर्ता ने अपनी अपील में कहा था कि उन्होंने एचएसवीपी की ई-ऑक्शन प्रक्रिया के माध्यम से उक्त प्लॉट खरीदा था तथा नवंबर 2023 में पूरी भुगतान प्रक्रिया एवं आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर दी थीं, लेकिन लगभग ढाई वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें प्लॉट का वास्तविक कब्जा नहीं दिया गया। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि लंबे समय से कब्जा न मिलने के बावजूद विभाग की ओर से कोई स्पष्ट समयसीमा अथवा संतोषजनक सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। एस्टेट ऑफिसर-क्क एचएसवीपी, फरीदाबाद द्वारा आयोग को भेजी गई रिपोर्ट में बताया गया कि साइट पर विकास कार्य पूरे न होने के कारण प्लॉट का कब्जा नहीं दिया जा सका। विभाग के अनुसार जलापूर्ति, सीवरेज तथा सड़क निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं, किंतु विद्युतीकरण का कार्य अभी लंबित है। इसी कारण पूर्व में जारी कब्जा प्रस्ताव वापस लिया गया तथा आवंटी को विलंबित कब्जे पर देय ब्याज भुगतान की प्रक्रिया शुरू करने के लिए बैंक विवरण उपलब्ध कराने को कहा गया है। विभाग ने आश्वासन दिया कि विद्युतीकरण कार्य पूर्ण होने के बाद नया कब्जा प्रस्ताव जारी किया जाएगा। आयोग ने अपने आदेश में कहा कि बिना विकास कार्य पूरे किए प्लॉट की ई-ऑक्शन करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। आयोग ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि विकास कार्य पूरे किए बिना प्लॉट का आवंटन कर कब्जा देने की पेशकश करना विभागीय कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। आयोग ने कहा कि किसी भी प्लॉट को ई-ऑक्शन में डालने से पहले विकास कार्य पूरे होना एक निहित शर्त है ताकि आवंटी निर्माण कार्य शुरू कर सकें। नागरिक सरकार और उसकी एजेंसियों पर विश्वास करते हुए ऐसी नीलामी में भाग लेते हैं और यह अपेक्षा करते हैं कि संबंधित विभाग अपनी जिम्मेदारी का समुचित निर्वहन करेगा। आयोग ने यह भी उल्लेख किया कि यदि निर्धारित समय में कब्जा नहीं दिया जाता है, तो एचएसवीपी द्वारा देरी पर ब्याज भुगतान किया जाना चाहिए, जबकि फरीदाबाद में ऐसा नहीं किया जा रहा था। आयोग के समान मामलों में हस्तक्षेप के बाद अब एचएसवीपी ने विलंबित कब्जे पर ब्याज देना शुरू किया है। हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले की सुनवाई के दौरान आयोग ने यह माना कि आवंटी को बढ़ती निर्माण लागत, संभावित ऋण ब्याज और मानसिक व आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। आयोग ने यह भी उल्लेख किया कि हाल ही में एक अन्य मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने एचएसवीपी की कार्यप्रणाली पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि एक सार्वजनिक प्राधिकरण होने के नाते एचएसवीपी का उद्देश्य नो प्रॉफिट-नो लॉस आधार पर किफायती आवास उपलब्ध कराना है, किंतु उसका रवैया लाभ-केंद्रित प्रतीत होता है, जो निम्न एवं मध्यम आय वर्ग के हितों के प्रतिकूल है।

आयोग ने कहा कि यद्यपि यह मामला अधिक मुआवजे का पात्र प्रतीत होता है, किंतु हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत आयोग अधिकतम 5,000 रुपये तक ही मुआवजा प्रदान कर सकता है। इसी के तहत आयोग ने श्री आयुष कटारिया को 5,000 रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। एचएसवीपी को निर्देश दिए गए हैं कि आदेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर यह राशि अदा की जाए तथा अनुपालन रिपोर्ट 5 जून 2026 तक प्रस्तुत की जाए।

आयोग ने निर्देश दिया कि एचएसवीपी प्रारंभिक रूप से यह राशि अपने कोष से अदा कर सकता है तथा विस्तृत जांच के बाद दोषी अधिकारियों से इसकी वसूली कर सकता है। भुगतान प्रक्रिया के लिए आवंटी से बैंक संबंधी आवश्यक विवरण साझा करने को कहा गया है।

साथ ही आयोग ने स्पष्ट किया कि आवंटी अधिक मुआवजे, मानसिक उत्पीड़न, आर्थिक हानि एवं अन्य कठिनाइयों के लिए उपयुक्त मंच जैसे उपभोक्ता आयोग, माननीय उच्च न्यायालय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी का दरवाजा खटखटा सकता है। आयोग ने कहा कि वर्तमान में एस्टेट ऑफिसर द्वारा गलत कब्जा तिथि वापस लेने तथा विलंबित कब्जे पर ब्याज देने की प्रक्रिया शुरू करने जैसे सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं, किंतु आयोग परिस्थितियों को देखते हुए तत्काल कब्जा सुनिश्चित कराने में असमर्थ है। आयोग ने आशा व्यक्त की कि एचएसवीपी इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करते हुए आवंटी को जल्द से जल्द प्लॉट का कब्जा उपलब्ध कराएगा।

संपादकीय

यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक: समान नागरिक संहिता की ओर असम का कदम: एक ऐतिहासिक पहल

भारतीय लोकतंत्र में कानून और समाज के बीच का संतुलन हमेशा से एक जटिल विषय रहा है। व्यक्तिगत कानूनों की विविधता, जो विभिन्न धर्मों और समुदायों के आधार पर चली आ रही है, इस देश की बहुलतावादी संस्कृति की पहचान तो रही है, किंतु साथ ही यह असमानता और भेदभाव का स्रोत भी बनती रही है – विशेषकर महिलाओं के संदर्भ में। इसी पृष्ठभूमि में असम सरकार ने एक साहसिक कदम उठाते हुए राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक प्रस्तुत किया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की ओर से संसदीय कार्य मंत्री अतुल बोरा ने विधानसभा में 'द यूनिफॉर्म सिविल कोड, असम, बिल, 2026' पेश किया। इस विधेयक पर 27 मई को चर्चा और पारित किए जाने की संभावना है। यदि यह विधेयक पारित हो जाता है, तो असम उत्तराखंड और गुजरात के बाद देश का तीसरा राज्य बन जाएगा जो इस ऐतिहासिक कानून को लागू करेगा। यह घटना महज एक विधायी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह उस सामाजिक-राजनीतिक बहस की परिणति है जो दशकों से भारत में चलती आई है। संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य को यह निर्देश देता है कि वह संपूर्ण भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करे। इसका उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए – चाहे वे किसी भी धर्म के हों – एक समान और न्यायसंगत नियम स्थापित करना है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने स्पष्ट किया है कि यह कानून धार्मिक परंपराओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि पूजा-पाठ, नमाज या किसी भी धार्मिक रीति-रिवाज को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। इसके बजाय, यह कानून विवाह की न्यूनतम आयु, बहुविवाह पर प्रतिबंध, विवाह का अनिवार्य पंजीकरण, उत्तराधिकार एवं संपत्ति के अधिकार तथा लिव-इन संबंधों के विनियमन जैसे नागरिक मुद्दों पर केंद्रित होगा। असम के यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक की एक महत्वपूर्ण और विशेष बात यह है कि इसमें जनजातीय समुदायों को पूरी तरह से इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है – चाहे वे पहाड़ी क्षेत्रों में हों या मैदानी इलाकों में। यह छूट असम की उस समृद्ध जनजातीय विविधता को ध्यान में रखते हुए दी गई है, जिसमें 200 से अधिक जनजातीय और स्वदेशी समूह शामिल हैं। इस दृष्टि से असम का यूनिफॉर्म सिविल कोड मॉडल उत्तराखंड के मुकाबले अधिक समावेशी और लचीला है। असम यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक की एक और उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इसमें लिव-इन संबंधों के अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान किया गया है। इसके लिए एक समर्पित प्रशासनिक ढाँचा तैयार किया जाएगा, जिसमें रजिस्ट्रार नियुक्त किए जाएंगे जो विवाह, तलाक और लिव-इन संबंधों का पंजीकरण संभालेंगे। यह प्रावधान समाज में उन महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है जो बिना कानूनी मान्यता के साझेदारी में रह रहे हैं और जिनके पास अभी तक कोई कानूनी अधिकार नहीं थे। इस कदम के साथ राष्ट्रीय स्तर पर समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन को लेकर बहस ने एक नया मोड़ लिया है। यह संहिता विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण जैसे विषयों पर धर्म-आधारित व्यक्तिगत कानूनों को प्रतिस्थापित कर सभी नागरिकों पर लागू होने वाले सामान्य नियमों की स्थापना करती है। सत्तारूढ़ गठबंधन का मानना है कि यह कानून सामाजिक सद्भाव, लैंगिक न्याय और संवैधानिक समानता को बढ़ावा देगा। उत्तराखंड 2024 में यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के एक वर्ष पूर्ण होने पर कहा था कि इस कानून ने महिलाओं को सशक्त किया है और सुरक्षा में सुधार लाया है। उत्तराखंड का अनुभव यह दशार्ता है कि जो आशंकाएं इस कानून को लेकर थीं, वे काफी हद तक निराधार साबित हुई हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या यह कदम वाकई सामाजिक परिवर्तन की दिशा में है या यह केवल एक राजनीतिक रणनीति है ? विपक्षी दलों और कुछ सामाजिक संगठनों की ओर से इस पर गहन निगरानी रखी जाएगी। विधानसभा में इस पर चर्चा शुरू होते ही यह एक राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण और बारीकी से देखी जाने वाली विधायी प्रक्रिया बन जाएगी। विपक्ष का यह तर्क रहा है कि ऐसे कानूनों को जल्दबाजी में नहीं, बल्कि व्यापक जन-परामर्श के बाद लागू किया जाना चाहिए। किंतु दूसरी ओर, यह भी सच है कि व्यक्तिगत कानूनों में धर्म-आधारित भेदभाव वर्षों से महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित करता आया है। बहुविवाह की प्रथा, असमान उत्तराधिकार अधिकार और विवाह-विच्छेद की एकतरफा व्यवस्थाएं समाज में असमानता को बनाए रखती हैं। एक समान नागरिक संहिता इन विसंगतियों को दूर करने में सहायक हो सकती है। असम की विविध जनसांख्यिकीय और सांस्कृतिक संरचना को देखते हुए यह कानून बनाना निश्चित रूप से एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि असम सरकार ने इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को राज्य की सामाजिक वास्तविकताओं और जनसांख्यिकीय विविधता के अनुसार अनुकूलित किया है। यह दृष्टिकोण इस बात का संकेत है कि सरकार ने एक आकार-सभी-के-लिए वाली नीति की बजाय स्थानीय परिस्थितियों को प्राथमिकता दी है। मुख्यमंत्री सरमा ने यह भी कहा कि विधानसभा में इस विधेयक की प्रस्तुति से यह अवसर मिलेगा कि 'रिकॉर्ड पर चर्चा' हो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों आवश्यक है और यह देश के संस्थापकों की दृष्टि के साथ किस प्रकार संरेखित है। यह बात महत्वपूर्ण है, क्योंकि संविधान निमार्ताओं – विशेषकर डॉ. भीमराव अंबेडकर – ने एक समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर बल दिया था। अंत में, यह कहना उचित होगा कि असम सरकार का यह कदम भले ही राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, किंतु इसका दीर्घकालिक प्रभाव इसके क्रियान्वयन की गुणवत्ता पर निर्भर करेगा। कानून बनाना पहला कदम है, उसे न्यायपूर्ण और संवेदनशील तरीके से लागू करना असली परीक्षा है। जनजातीय समुदायों को दी गई छूट, धार्मिक परंपराओं का सम्मान और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा – ये तीनों पहलू मिलकर यह तय करेंगे कि असम का यूनिफॉर्म सिविल कोड वाकई एक प्रगतिशील कानून बनता है या केवल एक राजनीतिक प्रतीक। लोकतंत्र की असल जीत तब होगी जब कानून की भाषा समाज के हर वर्ग तक पहुँचे और उन्हें सम्मान के साथ न्याय मिले।

समकालीन साहित्य और स्मृतियों का साक्ष्य

परिचय दास (हि.स)

लोक में जो संकेत, आत्मीय रचाव और सहज संचरणशीलता है, वह अतिआधुनिकता में भी स्वीकार्य है, उपयोगी है। लोक-रचनात्मकता का आधारपरक कार्य लोककला की कलात्मक एकता है। अतीत का उपयोग वर्तमान की आलोचना के बिना संभव नहीं। बिना आकांक्षा के न तो जीवन जिया जा सकता है और न ही कविता या साहित्य की रचना संभव है। समकालीन साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण है- स्मृतियों का साक्ष्य। स्मृतियां समकालीनता के विविध उपकरणों के समाहार से असंबद्ध नहीं रह सकतीं। हालांकि तार्किकता, परिवर्तनधर्मिता, शिल्प वैशिष्ट्य, गद्यपरकता इत्यादि संश्लिष्टताओं से आकार ग्रहण करता समकालीन साहित्य स्मृतिविहीन नहीं हो सकता फिर भी लोकोन्मुखता लगातार क्षीण होती गई है। स्थानीयता का पुट विविध रंगों के साथ जैसे उभरने चाहिए, उसमें कमी आती दिख रही है।

कुछ कवियों व उपन्यासकारों ने मौखिक परंपराओं व धरती के उन्मुखीकरण को आधार बनाने का यत्न किया है तो कुछ लोक को नए सिरे से समझ कर लाना चाहते हैं। कुछ कला और समुदाय के बीच के संबंधों से काम करते हैं तो कुछ लोकप्रिय रूपों व ध्वनियों के आधार पर। कुछ सामाजिक आवेग को लोक संस्कृति में समंजन करके नई भाषा रच रहे हैं तो कुछ काव्य-अभ्यास से लोक कविता की संभावनाओं के लिए नई सदी में नए दृष्टिकोण से सक्रिय हैं। लोक संस्कृति की प्रमुख आधार प्रकृति महानगरों से जैसे ओझल हुई है, उससे लेखन-सूत्र की दशा बदल गई है। प्रकृति, नदी, पर्यावरण में जैसी स्मृतियां रही हैं तथा साहित्य की धारा का जैसे गोमुख रहा है, नगरीकरण की स्थिति के चलते (अब हिन्दी साहित्य भी नगरीकरण का प्रतीक होने लगा है) स्वप्न के संदर्भ बदल गए हैं। यह सारा स्वप्न छंदमुक्तता की प्रयोजनता और वाक्यांशों की विविधताओं से भी पता चलता है।

लोक की रुचियों व अनेक जड़ताओं को साहित्य में जायज नहीं ठहराया जाना चाहिए, लेकिन उसकी तरलता या प्रवाहमयता या सुगंध का खोना स्मृति-रहित होने जैसा ही है। साहित्य का नगरीकृत होना एक फेज है, लेकिन पारंपरिक अनुगूंजों से वंचित होना दूसरी बात। स्थानीयता के कई तरह के खतरे भी हैं किंतु उसकी अलग आभा उसकी शक्ति भी है। प्रौद्योगिकी को स्थानीयता में खास व्यवहार मिलता है। साहित्य में स्थानीय संस्कृति को रचना एक खास सम्मोहन को शब्द देना है। उस सम्मोहन में एक गति भी होती है। कलात्मक प्रासंगिकता का दृश्यात्मकता व सांगीतिक अनुगूंजों से विशिष्ट संबंध है। इसीलिए लोक में जो दृश्यबंध आते हैं, उन्हें साहित्य में एक आकार दिया जा सकता है। यह अलग बात है कि समकालीनता के तनावों व लोक के समंजन का आधार क्या बनेगा या बनना चाहिए, यह विचार व अनुप्रयोग का विषय है।

नए-नए विषयों को उठाते हुए मिथक व लोक का समकालीनीकरण संभव है। कथा व कविता में तो यह विशिष्ट आकार ले ही सकता है। यदि नगरीय जीवन की संपृक्ति में लोक कविता की मूर्धन्यता को समझा जाए तो कुछ अनुभव एकत्र किए जा सकते हैं। उससे प्रस्तुति व शैली में निश्चित भिन्नताएं आएंगी। लोक संगीत के लिए "यू ट्यूब" के रूप में एक नया आधार मिला है। सामूहिक कलात्मक गतिविधि, सामाजिक काम, रोजमर्रा की जिंदगी, जीवन व प्रकृति के ज्ञान, धार्मिक प्रथाओं और विश्वासों को साहित्य में ढाल पाना इकहरा कार्य नहीं। लोक-रचनात्मकता का विशिष्ट आधारपरक कार्य लोककला की कलात्मक एकता है। लोक कला समाज के निचले तबके की आवश्यकताओं की उपस्थितियों के लिए निर्मित होती है। इसमें एक तरह का घरेलूपन है। चाहें तो उसकी "पुरातनता" में एक नवाचार भी ला दें।

कविता में पुरातनता में नवसंघनन उसका महत्वपूर्ण पक्ष है। लोक में जो संकेत, आत्मीय रचाव और सहज संचरणशीलता है, वह अति आधुनिकता में भी स्वीकार्य है, बल्कि बहु उपयोगी। अतीत का उपयोग वर्तमान की आलोचना के बिना संभव नहीं। बिना आकांक्षा न तो जीवन जिया जा सकता है और न ही कविता या साहित्य की रचना संभव है।

लोक को सस्ते फैशन परस्ती के रास्ते पर ले जाने, उसे उपभोक्तावादी सिस्टम में खपाने और तदनुकूल साहित्य के सरलीकरण को स्तरहीनतापूर्वक बल देने की भी कोशिशें जारी हैं। यह ऐसा प्रश्न है जो हमारे मानसतंत्र को बहुत बारीकी से झकझोरता है। जो लोकगीत अपने एक आम अतीत की रचनात्मक अभिव्यक्ति व समकालीन चेतना से जुड़ा है, उसे बाजार की इच्छाओं की झोंक में सौंपा जा रहा है। बाजार से सहयोग लेना बुरा नहीं, बाजार में जाना भी सहज है, किंतु उसके तंत्र का अनुकर्ता मात्र हो जाना मानवीय गरिमा के विरुद्ध है। जबकि साहित्य और लोक के अंतर्संबंध किसी भी अन्य अनुशासन की तरह हमें स्वयं को बेहतर और दूसरों को समझने के लिए सक्षम बनाते हैं। सारा मनोविज्ञान व समाजशास्त्र लोक सन्दर्भ में उपलब्ध हैं। यदि ऐसा न होता तो रामायण व महाभारत शास्त्र से लोक न बन जाते।

जब हम आंख खोलते हैं तथा स्मृति-संपन्न होते हैं तो भारतीय समाजों में रामायण व महाभारत को सुनकर अपनी स्मृति को धरती पर उतार लेते हैं। लोक संस्कृति के आत्मीय संचरण को समकालीन साहित्य में मानव अभिव्यक्ति के जबर्दस्त स्पेक्ट्रम की तरह लिया जाना चाहिए। लोक कला पारंपरिक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के माध्यम से सामूहिक कथन है, जीवन के साझे मार्ग पर गुजरना है, जिसमें सौंदर्य, अस्मिता व मूल्यों की अभिव्यक्ति हो सके। वह साहित्य व भाषा में उतरती है तो जीवंत सांस्कृतिक विरासत होती है जो अतीत व वर्तमान के मध्य सेतु होती है।

साहित्य में समकाल व लोक संस्कृति को स्थिर न समझें, बल्कि युगानुकूल उसका स्वीकरण होता रहता है। मछली, वृक्ष, हवा, खिलौना, घर, गाय, पुष्प, पत्ते इत्यादि ऐसे आलंबन हैं जो अपने साथ हमारी स्मृति लिये रहते हैं। संरक्षण, प्रक्रिया, उपकरण, सामग्री, डिजाइन, रूपांकन- सभी में एक परंपरा है। यही साहित्य में, आज के साहित्य में भी परिलक्षित होता है। ये साहित्य की परंपरा को जीवित रखने, बहुश्रुत बनाने, संबद्ध रखने, स्मृति संपन्न रखने और रचनात्मक होने को आधार देते हैं। लोक संस्कृति से कविता में विशिष्ट गतिमयता मिल सकती है, क्योंकि स्मृति, संकेत, स्वजनता,आत्मीयता से भिन्न गतिशास्त्र बनाया जा सकता है। यह एक सापेक्षता चुनती है जो कविता की धार है। इसमें सद्भाव व स्वतंत्रता है। वैयक्तिक सम्मान, लोक कल्याण की जगह सृजनात्मकता व सहित का समाहार इसमें हैं जो समकालीन साहित्य के लिए भी अपेक्षित है।

(लेखक, वरिष्ठ साहित्यकार हैं।)

पर्यावरण का पुनर्जागरण

डॉ. सत्यवान सौरभ (हि.स)

एक समय था जब भारतीय घरों, आंगनों, चौपालों और खेतों में लकड़ी की खाट या चारपाई जीवन का अभिन्न हिस्सा हुआ करती थी। सुबह की चाय से लेकर रात की नींद तक, खाट केवल एक फर्नीचर नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक जीवन का केंद्र थी। जैसे-जैसे आधुनिकता का प्रभाव बढ़ा, शहरीकरण ने गति पकड़ी और बाजार में नए-नए प्रकार के बेड, सोफा-कम-बेड तथा महंगे गद्दे आने लगे। खाट धीरे-धीरे घरों से गायब होने लगी। इसे पुरातन, ग्रामीण और पिछड़ेपन का प्रतीक मान लिया गया। परंतु समय का चक्र एक बार फिर घूम रहा है। आज लोग दोबारा लकड़ी की खाट की ओर लौट रहे हैं। यह वापसी केवल एक पारंपरिक वस्तु की वापसी नहीं है, बल्कि जीवन के प्रति बदलती सोच, स्वास्थ्य के प्रति जागरुकता और प्रकृति के साथ संतुलन की तलाश का प्रतीक भी है।

भारतीय समाज में खाट का इतिहास बहुत पुराना है। इसे चारपाई, मंजी या खटिया जैसे नामों से भी जाना जाता है। लकड़ी के मजबूत ढांचे और रस्सियों या पट्टियों से बुनी हुई यह संरचना सदियों तक भारतीय जीवन का आधार रही। गांवों में चौपाल की पहचान खाटों से होती थी। परिवार के बुजुर्ग खाट पर बैठकर निर्णय लेते थे। किसान दिनभर के श्रम के बाद खाट पर विश्राम करते थे और बच्चे उसी पर खेलते-कूदते बड़े होते थे। यह केवल आराम का साधन नहीं थी, बल्कि सामाजिक संवाद का मंच भी थी। आज भी ग्रामीण भारत में खाट पर बैठकर होने वाली चर्चाएं लोकतांत्रिक संवाद की सबसे सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति मानी जाती हैं।

पिछले कुछ दशकों में जीवनशैली में बड़े बदलाव आए। लोगों ने आधुनिक फर्नीचर को प्रगति और समृद्धि का प्रतीक मान लिया। बड़े-बड़े बेड, मोटे गद्दे और आकर्षक डिजाइन वाले फर्नीचर घरों की आवश्यकता बन गए। विज्ञापनों ने भी लोगों को यह विश्वास दिलाया कि आराम केवल महंगे गद्दों और आधुनिक बिस्तरों में ही संभव है। परिणामस्वरूप खाट धीरे-धीरे घरों से बाहर होती चली गई। अब जब लोग स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, बढ़ते तनाव और कृत्रिम जीवनशैली के दुष्प्रभावों का सामना कर रहे हैं, तब वे उन पारंपरिक विकल्पों को नए दृष्टिकोण से देखने लगे हैं जिन्हें कभी उन्होंने स्वयं ही त्याग दिया था।

लकड़ी की खाट की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण स्वास्थ्य संबंधी लाभ हैं। आधुनिक जीवनशैली में कमर दर्द, गर्दन दर्द और रीढ़ से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ी हैं। बहुत अधिक मुलायम गद्दों पर सोना कई लोगों के लिए असुविधाजनक साबित हुआ है। इसके विपरीत खाट का ढांचा शरीर को संतुलित सहारा देता है। रस्सियों से बुनी खाट शरीर के भार को समान रूप से वितरित करती है, जिससे रीढ़ पर अनावश्यक दबाव कम पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अनेक बुजुर्ग वर्षों तक खाट पर सोने के कारण बेहतर शारीरिक स्थिति में दिखाई देते हैं। यद्यपि हर व्यक्ति की स्वास्थ्य आवश्यकताएं अलग होती हैं, फिर भी खाट को प्राकृतिक और संतुलित विश्राम का साधन माना जाता है।

गर्म जलवायु वाले हमारे देश में खाट की उपयोगिता और भी अधिक है। फोम और स्प्रिंग वाले गद्दे अकसर शरीर की गर्मी को रोक लेते हैं, जिससे गर्मियों में असुविधा बढ़ जाती है। इसके विपरीत खाट के नीचे और ऊपर दोनों ओर से हवा का प्रवाह बना रहता है। यह प्राकृतिक वेंटिलेशन शरीर को ठंडक प्रदान करता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार करता है। बिजली की बढ़ती खपत और एयर कंडीशनर पर निर्भरता के इस दौर में खाट का यह गुण विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है।

पर्यावरणीय दृष्टि से भी खाट का महत्व बढ़ रहा है। आज दुनिया टिकाऊ विकास और पर्यावरण संरक्षण की बात कर रही है। आधुनिक फर्नीचर उद्योग में प्लास्टिक, सिंथेटिक फोम और रासायनिक पदार्थों का व्यापक उपयोग होता है, जिनका पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके विपरीत लकड़ी और प्राकृतिक रस्सियों से बनी खाट अपेक्षाकृत पर्यावरण-अनुकूल होती है। यह लंबे समय तक चलती है। आसानी से मरम्मत की जा सकती है और इसके अधिकांश हिस्से पुनर्चक्रित या प्राकृतिक रूप से नष्ट हो सकते हैं। ऐसे समय में जब लोग पर्यावरण के प्रति अधिक संवेदनशील हो रहे हैं, खाट उन्हें एक टिकाऊ विकल्प के रूप में दिखाई देने लगी है।

खाट की वापसी का एक कारण आर्थिक भी है। महंगे फर्नीचर और ब्रांडेड गद्दों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। दूसरी ओर, स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाई गई खाट अपेक्षाकृत सस्ती और टिकाऊ होती है। ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में आज भी खाट कम लागत में उपलब्ध है। यह वर्षों तक उपयोग में आ सकती है और आवश्यकता पड़ने पर उसकी रस्सियां बदलकर उसे फिर नया बनाया जा सकता है। इस प्रकार खाट केवल सांस्कृतिक विरासत नहीं बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी व्यवहारिक विकल्प है।

दिलचस्प बात यह है कि खाट की वापसी केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। बड़े शहरों में भी लोग इसे नए रूप में अपना रहे हैं। इंटीरियर डिजाइनरों ने पारंपरिक खाट को आधुनिक सौंदर्यबोध के साथ प्रस्तुत करना शुरू किया है। आज कई घरों में खाट को बालकनी, गार्डन, टैरेस या लिविंग स्पेस में सजावटी और उपयोगी वस्तु के रूप में रखा जा रहा है। रिसॉर्ट, कैफे और होमस्टे भी अपने परिसर में खाट का उपयोग कर रहे हैं, ताकि ग्राहकों को देसी और पारंपरिक अनुभव मिल सके। यह दिखाता है कि परंपरा और आधुनिकता का मेल किस प्रकार संभव है।

सोशल मीडिया ने भी खाट की लोकप्रियता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज 'सस्टेनेबल लिविंग', 'स्लो लाइफ', 'देसी लाइफस्टाइल' और 'रूट्स की ओर वापसी' जैसे विषय युवाओं के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं। लोग अपने घरों और फार्म हाउस में खाट के साथ तस्वीरें साझा करते हैं। अनेक युवा, जो कभी खाट को केवल गांवों की वस्तु मानते थे, अब उसे जीवनशैली और पहचान का हिस्सा समझने लगे हैं। यह परिवर्तन बताता है कि नई पीढ़ी अपनी सांस्कृतिक विरासत को नए नजरिए से देख रही है।

खाट का सांस्कृतिक महत्व भी कम नहीं है। भारतीय साहित्य, लोकगीतों और फिल्मों में खाट का उल्लेख बार-बार मिलता है। यह ग्रामीण जीवन, आत्मीयता और सामूहिकता का प्रतीक रही है। जब परिवार के सदस्य एक साथ खाट पर बैठकर बातचीत करते थे, तब संवाद स्वाभाविक रूप से विकसित होता था। आज डिजिटल युग में जहां लोग एक ही घर में रहते हुए भी मोबाइल स्क्रीन में व्यस्त रहते हैं, वहां खाट जैसे सामूहिक बैठने के स्थान फिर से सामाजिक निकटता का माध्यम बन सकते हैं।

हालांकि खाट की वापसी का अर्थ यह नहीं है कि आधुनिक फर्नीचर पूरी तरह अप्रासंगिक हो गया है। आधुनिक जीवन की आवश्यकताएं अलग हैं और कई परिस्थितियों में आधुनिक बेड अधिक सुविधाजनक भी हो सकते हैं। लेकिन खाट की बढ़ती लोकप्रियता यह संकेत अवश्य देती है कि लोग केवल सुविधा नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, पर्यावरण और सांस्कृतिक जुड़ाव को भी महत्व देने लगे हैं। वे ऐसे विकल्प खोज रहे हैं जो जीवन को अधिक संतुलित और स्वाभाविक बना सकें।

वास्तव में खाट का पुनरागमन उस व्यापक सामाजिक बदलाव का हिस्सा है जिसमें लोग अपनी जड़ों की ओर लौटने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे पारंपरिक भोजन हो, जैविक खेती हो, मिट्टी के बर्तन हों या लकड़ी की खाट–लोग अब यह महसूस कर रहे हैं कि विकास का अर्थ केवल नई तकनीक अपनाना नहीं है। विकास का वास्तविक अर्थ उन परंपराओं को भी समझना है जो समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं और जिनमें जीवन को सरल, स्वस्थ और संतुलित बनाने की क्षमता है।

आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है और जीवन पहले से अधिक जटिल होता जा रहा है, तब लकड़ी की खाट हमें सादगी का संदेश देती है। वह याद दिलाती है कि आराम केवल महंगे साधनों से नहीं, बल्कि प्रकृति के अनुकूल जीवनशैली से भी प्राप्त किया जा सकता है। खाट की ओर लौटते कदम इस बात का संकेत हैं कि समाज अपनी सांस्कृतिक स्मृतियों, पारंपरिक ज्ञान और पर्यावरणीय समझ को फिर से महत्व देने लगा है।

संभव है कि आने वाले वर्षों में खाट फिर कभी हर घर का मुख्य फर्नीचर न बने, लेकिन उसका पुनर्जागरण यह अवश्य सिद्ध करता है कि परंपरा कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होती। जब आधुनिक जीवन की चुनौतियां बढ़ती हैं, तब समाज अकसर अपनी जड़ों में समाधान खोजता है। लकड़ी की खाट की वापसी इसी खोज की कहानी है–एक ऐसी कहानी जिसमें स्वास्थ्य है, पर्यावरण है, संस्कृति है और जीवन को अधिक मानवीय बनाने की आकांक्षा भी।

यही कारण है कि आज लोग दोबारा लकड़ी की खाट पर लौट रहे हैं। वे केवल एक पुराने फर्नीचर को नहीं अपना रहे, बल्कि एक ऐसे जीवन-दर्शन को पुनर्जीवित कर रहे हैं जो सादगी, संतुलन, आत्मीयता और प्रकृति के साथ सामंजस्य पर आधारित है। यही इस वापसी का सबसे बड़ा अर्थ और सबसे बड़ी उपलब्धि है।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

आज का राशिफल

मेष: आज का दिन नए व्यापारिक अवसरों से भरपूर रहेगा। किसी नए बिजनेस की शुरूआत के लिए अनुकूल समय है। केवल भाग्य के भरोसे रहने की बजाय हर कार्य को समझदारी और सतर्कता के साथ करें। घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए खरीदारी पर जा सकते हैं। *(सिटी दर्पण)*

वृषभ: आज आपको एक साथ कई जिम्मेदारियां निभानी पड़ सकती हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से पेट संबंधी परेशानी उभर सकती है, इसलिए खानपान का विशेष ध्यान रखें। शेयर बाजार या निवेश से जुड़े मामलों में जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। *(सिटी दर्पण)*

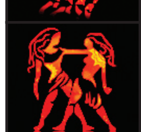
मिथुन: कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी और माहौल सकारात्मक बना रहेगा। हालांकि गुस्से पर नियंत्रण न रखने से विवाद की स्थिति बन सकती है। बिजनेस पार्टनरशिप में सोच-समझकर निर्णय लें। विरोधियों को कमजोर आंकना भारी पड़ सकता है। *(सिटी दर्पण)*

कर्क: व्यापार विस्तार के लिए आर्थिक सहायता या लोन लेने का विचार बन सकता है। मानसिक शांति बनाए रखना आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा। पढ़ाई और करियर में बेहतर प्रदर्शन के चलते नौकरी के नए अवसर मिल सकते हैं। *(सिटी दर्पण)*

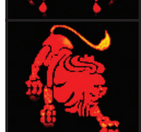
सिंह: आज आपके व्यवहार और व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। जीवनसाथी के साथ भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण योजनाएं बना सकते हैं। धार्मिक और सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। कार्यस्थल पर कर्मचारियों पर आंख बंद करके भरोसा करना ठीक नहीं होगा। *(सिटी दर्पण)*

कन्या: ऑफिस और कार्यक्षेत्र में परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। करियर से जुड़े शानदार अवसर मिलने के संकेत हैं। लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। धन निवेश या बड़े फैसले लेने के लिए दिन अनुकूल रहेगा। *(सिटी दर्पण)*

तुला: आज आपकी कोई महत्वपूर्ण योजना अधूरी रह सकती है। पड़ोसियों या आसपास के लोगों से छोटी बात पर विवाद होने की आशंका है। दिन आपको कई नए अनुभव और सीख देगा। स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना परेशानी बढ़ा सकता है। *(सिटी दर्पण)*

वृश्चिक: व्यापार में नई और बड़ी साझेदारी होने की संभावना है। घर में रिश्तेदारों और मित्रों का आगमन माहौल को खुशनुमा बनाएगा। आय के नए स्रोत बनने से आर्थिक लाभ मिल सकता है। परिवार के लोग प्रसन्न और उत्साहित रहेंगे। *(सिटी दर्पण)*

धनु: वैवाहिक जीवन में मधुरता और नया उत्साह देखने को मिलेगा। मित्रों के साथ अपने मन की बातें साझा कर सकते हैं। लंबे समय से रुके हुए कार्यों को पूरा करने का प्रयास सफल रहेगा। मीडिया और संचार क्षेत्र से जुड़े लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। *(सिटी दर्पण)*

मकर: दिन की शुरूआत सामान्य रहेगी, लेकिन शाम आपके लिए कई खुशियां लेकर आ सकती है। धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों की ओर झुकाव बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या एक्सेसरीज की खरीदारी कर सकते हैं। आज लिया गया साहसिक फैसला भविष्य में लाभ देगा। *(सिटी दर्पण)*

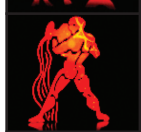
कुंभ: जीवनसाथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें। नकारात्मक सोच वाले लोगों की सलाह आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। अधिक व्यस्तता के कारण थकान महसूस होगी। अचानक धन हानि की स्थिति बन सकती है, इसलिए आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। *(सिटी दर्पण)*

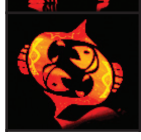
मीन: आज परिवार के साथ कहीं घूमने-फिरने की योजना बन सकती है। लोग आपकी सलाह और अनुभव का लाभ लेना चाहेंगे। जीवनसाथी को कोई उपहार देकर रिश्तों में मिठास बढ़ा सकते हैं। व्यापार में बड़ा आर्थिक लाभ मिलने के योग हैं। *(सिटी दर्पण)*

क्या गाय को 'राष्ट्रीय पशु' घोषित करने में कोई समस्या है ?

महेन्द्र तिवारी

भारत में गाय केवल एक पशु नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक चेतना और ग्रामीण जीवन का अभिन्न हिस्सा मानी जाती है। भारतीय समाज में सदियों से गाय को माता का दर्जा दिया जाता रहा है। अनेक धार्मिक ग्रंथों, लोक परंपराओं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गाय का विशेष महत्व रहा है। यही कारण है कि समय समय पर गाय को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठती रही है। कई धार्मिक संगठनों, सामाजिक समूहों और कुछ राजनीतिक दलों ने यह मांग सार्वजनिक रूप से रखी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी एक मामले की सुनवाई के दौरान गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की आवश्यकता पर टिप्पणी की थी। इसके बावजूद भारत सरकार ने अब तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। इसके पीछे केवल राजनीतिक कारण नहीं बल्कि सामाजिक, संवैधानिक, आर्थिक और प्रशासनिक जटिलताएँ भी हैं।

भारत का वर्तमान राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर है। इसे 1973 में शुरू किए गए प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत संरक्षण का प्रतीक बनाया गया था। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार देश में बाघ संरक्षण के लिए विशेष कानूनी और पर्यावरणीय ढांचा तैयार किया गया। आज भारत विश्व के लगभग 70 प्रतिशत बाघों का घर माना जाता है और देश में 50 से अधिक टाइगर रिजर्व स्थापित किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ केवल शक्ति और साहस का प्रतीक नहीं है बल्कि वह भारत की जैव विविधता और वन्यजीव संरक्षण नीति का केंद्र भी है। ऐसे में गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने का प्रश्न केवल भावनात्मक नहीं बल्कि नीतिगत बहस का विषय बन जाता है।

भारत एक बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक देश है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और अनेक आदिवासी समुदाय रहते हैं। हिंदू धर्म में गाय को पवित्र माना जाता है, लेकिन सभी समुदायों की मान्यताएँ समान नहीं हैं। पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों, केरल और गोवा जैसे क्षेत्रों में गोमांस भोजन का हिस्सा रहा है। भारतीय संविधान सभी नागरिकों को अपनी संस्कृति और भोजन की स्वतंत्रता देता है। ऐसे में यदि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाता है तो कई लोग इसे एक धर्म विशेष की मान्यताओं को सरकारी पहचान देने के रूप में देख सकते हैं। आलोचकों का तर्क है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में किसी धार्मिक प्रतीक को राष्ट्रीय पहचान बनाना संवैधानिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है।

हालांकि दूसरी ओर यह भी सच है कि भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 48 के अंतर्गत राज्यों को गोवंश संरक्षण और नस्ल सुधार के लिए प्रयास करने का निर्देश दिया गया है। देश के अधिकांश राज्यों में गोहत्या पर किसी न किसी रूप में प्रतिबंध पहले से मौजूद है। केंद्र सरकार का पशुपालन और डेयरी विभाग भी गोवंश संरक्षण और पशुधन विकास के लिए कई योजनाएँ चला रहा है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसी योजनाओं का उद्देश्य देशी नस्लों का संरक्षण और दुग्ध उत्पादन बढ़ाना है। इससे स्पष्ट होता है कि गाय को पहले से ही विशेष सरकारी संरक्षण प्राप्त है। इसलिए समर्थकों का कहना है कि राष्ट्रीय पशु का दर्जा केवल उस सम्मान को औपचारिक रूप देने जैसा होगा जो भारतीय समाज में गाय को पहले से प्राप्त है।

लेकिन वास्तविक समस्या केवल सम्मान तक सीमित नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में देश के अनेक राज्यों में आवारा पशुओं की समस्या गंभीर रूप ले चुकी है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में किसान खुले घूमते पशुओं से परेशान हैं। जब गाय दूध देना बंद कर देती है या बूढ़ी हो जाती है तो गरीब किसान उसका पालन जारी नहीं रख पाते। परिणामस्वरूप उन्हें सड़कों या खेतों में छोड़ दिया जाता है। ये पशु किसानों की फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं और सड़क दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। अनेक ग्रामीण इलाकों में रात भर खेतों की रखवाली करना किसानों की मजबूरी बन गया है। यदि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाता है और कानून और कठोर हो जाते हैं तो यह संकट और बढ़ सकता है, क्योंकि पशुओं के पुनर्वास के लिए पर्याप्त गौशालाएँ और संसाधन अभी उपलब्ध नहीं हैं।

भारत की कृषि व्यवस्था अभी भी छोटे और सीमांत किसानों पर आधारित है। अधिकांश किसान सीमित आय और बढ़ती लागत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। एक बूढ़ी या अनुत्पादक गाय का पालन करना उनके लिए भारी आर्थिक बोझ बन जाता है। चारा, दवा और देखभाल पर लगातार खर्च होता है जबकि उससे कोई आय नहीं होती। यदि सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करती है तो संभव है कि पशुधन प्रबंधन से जुड़े नियम और कड़े हो जाएँ। इससे किसानों की आर्थिक कठिनाइयाँ और बढ़ सकती हैं। इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी बड़े निर्णय से पहले पशु आश्रय, चारे की व्यवस्था और किसानों के लिए आर्थिक सहायता की मजबूत नीति आवश्यक है।

गाय से जुड़ा एक बड़ा आर्थिक पक्ष चमड़ा और मांस उद्योग भी है। भारत दुनिया के प्रमुख चमड़ा उत्पादक देशों में शामिल रहा है। इस उद्योग से लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा है। इनमें बड़ी संख्या में आर्थिक रूप से कमजोर और हाशिए पर रहने वाले समुदाय शामिल हैं। भारत में मांस निर्यात का बड़ा हिस्सा भैंस के मांस से जुड़ा होता है, लेकिन कठोर सामाजिक माहौल का प्रभाव पूरे उद्योग पर पड़ता है। यदि राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिलने के बाद कानून और सामाजिक दबाव बढ़ते हैं तो रोजगार और व्यापार दोनों प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए आर्थिक विशेषज्ञ इस विषय को केवल धार्मिक दृष्टि से देखने के बजाय रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भी देखते हैं।

पिछले कुछ वर्षों में गाय के नाम पर हिंसा और भीड़ द्वारा हमले की घटनाएँ भी सामने आई हैं। कई मामलों में गौ रक्षा के नाम पर लोगों को पीटा गया, अपमानित किया गया या उनकी हत्या तक कर दी गई। ऐसे मामलों ने देश की कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द पर गंभीर प्रश्न खड़े किए। समाजशास्त्रियों का मानना है कि यदि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाता है तो कुछ कट्टर समूह इसे अपने सामाजिक अधिकार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे प्रशासन और पुलिस के सामने नई चुनौतियाँ खड़ी हो सकती हैं। कानून का शासन किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी आवश्यकता है और किसी भी प्रतीकात्मक निर्णय का मूल्यांकन इसी आधार पर किया जाना चाहिए।

वन्यजीव संरक्षण के दृष्टिकोण से भी यह बहस महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय पशु का दर्जा सामान्यतः उन जीवों को दिया जाता है जिनके संरक्षण की विशेष आवश्यकता होती है। बंगाल टाइगर संकटग्रस्त वन्यजीवों में शामिल रहा है और उसके संरक्षण के लिए विशेष अभियान चलाए गए। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत किया गया था। इसके विपरीत गाय एक पालतू पशु है जिसकी संख्या करोड़ों में है। इसलिए कुछ पर्यावरणविद मानते हैं कि राष्ट्रीय पशु का दर्जा वन्यजीव संरक्षण की भावना से जुड़ा होना चाहिए, न कि पालतू पशुओं से।

गाय भारतीय समाज में श्रद्धा, सेवा और ग्रामीण जीवन का महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह भी सच है कि भारतीय कृषि और डेयरी व्यवस्था में उसका योगदान ऐतिहासिक रहा है। लेकिन किसी पशु को राष्ट्रीय प्रतीक बनाना केवल भावनात्मक निर्णय नहीं होता। उसके पीछे संवैधानिक संतुलन, सामाजिक विविधता, आर्थिक प्रभाव, प्रशासनिक क्षमता और पर्यावरणीय दृष्टिकोण जैसे अनेक पहलुओं पर विचार करना पड़ता है। भारत जैसे विशाल और विविध देश में किसी भी राष्ट्रीय निर्णय का प्रभाव करोड़ों लोगों के जीवन पर पड़ता है। इसलिए गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की बहस केवल आस्था की बहस नहीं बल्कि भारत की लोकतांत्रिक और सामाजिक संरचना की परीक्षा भी है।

मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत पंजाब में हाई-रिस्क डिलीवरी और नवजात शिशु देखभाल को मिला बड़ा सहारा

यज्ञांश शर्मा
चंडीगढ़

पंजाब सरकार की मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के माध्यम से हाई-रिस्क गर्भावस्था और नवजात शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को विशेष रूप से मजबूती मिल रही है। यह योजना जटिल प्रसव और गंभीर रूप से बीमार नवजात शिशुओं के इलाज को परिवारों के लिए बिना किसी आर्थिक बोझ के आसान बना रही है।

भारत के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5) पर आधारित एक महत्वपूर्ण अध्ययन के अनुसार, देश में लगभग हर दो में से एक गर्भावस्था हाई-रिस्क श्रेणी में आती है। शिक्षा की कमी, गरीबी, दो गर्भों के बीच कम अंतराल, पिछली प्रसव जटिलताएं और पहले हुई सिजेरियन डिलीवरी जैसे कारक मां और बच्चे दोनों के लिए जोखिम पैदा करते हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिलाएं सबसे अधिक जोखिम का सामना करती हैं, जिससे मातृत्व स्वास्थ्य सेवाओं और जागरूकता कार्यक्रमों को और मजबूत करने की आवश्यकता स्पष्ट होती है। स्वास्थ्य कार्ड उन महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा बनकर उभरा है, जिन्हें प्रसव के दौरान लंबे समय तक दर्द, स्वास्थ्य समस्याओं, भ्रूण की अस्वस्थ स्थिति या पहले हुई सिजेरियन डिलीवरी के कारण ऑपरेशन संबंधी इलाज की आवश्यकता पड़ती है। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी से प्राप्त आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 25 मई 2026 तक योजना के तहत मातृत्व और नवजात देखभाल के कुल 7,300 मामलों में इलाज प्रदान किया गया, जिस पर लगभग 7.04 करोड़ रुपये खर्च हुए। इनमें 5,300 हाई-रिस्क सिजेरियन डिलीवरी शामिल हैं, जिन पर 6.37 करोड़ रुपये खर्च किए गए। ये आंकड़े पंजाब में उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था और आपातकालीन प्रसूति सेवाओं में योजना की बढ़ती भूमिका को दर्शाते हैं। पटियाला की 28 वर्षीय लाभार्थी दीपिका, जिन्हें गर्भावस्था के दौरान एनीमिया सहित कई जटिलताओं का सामना करना पड़ा, ने अपना व्यक्तिगत

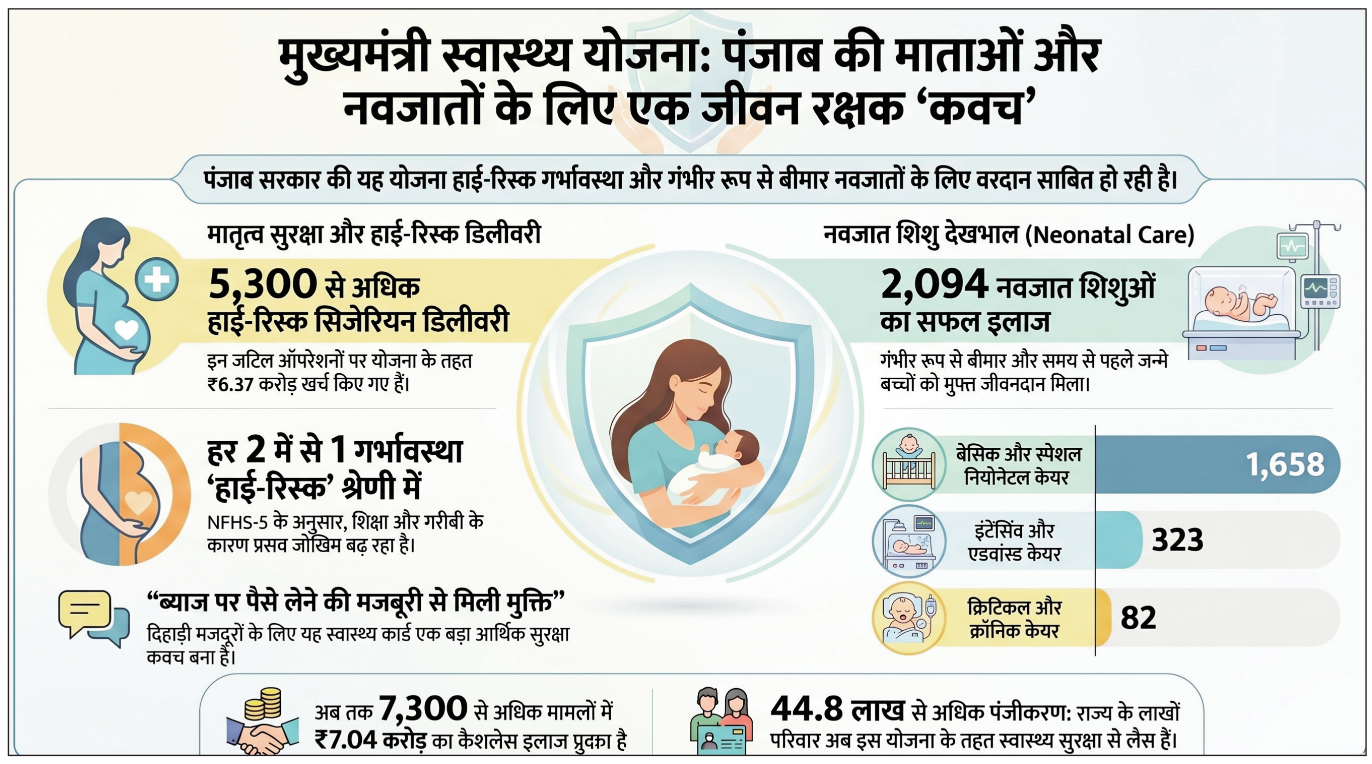

अनुभव साझा करते हुए बताया कि उनका सिजेरियन ऑपरेशन स्वास्थ्य कार्ड के तहत पूरी तरह कैशलेस हुआ। उनके पति मनोज ने कहा कि पूरा इलाज बिना किसी आर्थिक बोझ के सुचारू रूप से हुआ, जो उनके लिए बड़ी राहत की बात है। इसी तरह 31 वर्षीय दीक्षा सोनकर ने अपने तीसरे बच्चे के जन्म के दौरान पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मेडिकल कॉलेज अस्पताल में समय पर मातृत्व और नवजात देखभाल प्राप्त की, जो योजना के तहत पूरी तरह कैशलेस रही। उनके पति विकास सोनकर ने कहा, हमारी पहले से ही दो बेटियां हैं और हम चिंतित थे कि तीसरी डिलीवरी में कोई जटिलता न आ जाए।

विकास सोनकर ने आगे कहा कि जब भी घर में किसी को अस्पताल जाने की स्थिति बनती है तो आर्थिक तनाव बढ़ जाता है। विकास, जो एक दिहाड़ी मजदूर हैं, बताते हैं कि ऐसे समय में उन्हें ब्याज पर पैसे उधार लेने पड़ते हैं। यह उस कठोर सच्चाई को दर्शाता है कि स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च उठाने के लिए कम आय वर्ग के मजदूरों को किस तरह संघर्ष करना पड़ता है। उन्होंने कहा, लेकिन स्वास्थ्य कार्ड ने इस बार बड़ी राहत दी। मातृत्व सेवाओं के साथ-साथ यह योजना गंभीर रूप से बीमार और समय से पहले जन्मे नवजात शिशुओं के लिए विशेष इलाज सहायता भी प्रदान कर रही है। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी, पंजाब के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, योजना के तहत विभिन्न पैकेजों में कुल 2,094 नवजात शिशुओं का इलाज किया गया। बेसिक नियोनेटल केयर, जो उन शिशुओं को सहायता प्रदान करती है जिनका इलाज उनकी माताओं के साथ-साथ किया जाता है, के अंतर्गत 881 नवजातों का इलाज किया गया, जिस पर 5.82 लाख रुपये खर्च हुए। इसी प्रकार अल्प अवधि के इंटेंसिव केयर यूनिट (आईसीयू) इलाज की आवश्यकता वाले 777 नवजातों को स्पेशल नियोनेटल केयर पैकेज के तहत लाभ मिला, जिस पर 28.27 लाख रुपये खर्च हुए। इंटेंसिव नियोनेटल केयर पैकेज के अंतर्गत 207 नवजातों को कंटीन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर (सीपीएपी) सहायता, 24 घंटे से कम वेंटिलेशन तथा नवजात संक्रमण जैसी गंभीर स्थितियों के इलाज के लिए सहायता दी गई, जिस पर 15.65 लाख रुपये खर्च किए गए। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 1,200 से 1,499 ग्राम वजन वाले अथवा लंबे समय तक वेंटिलेटर सहायता की आवश्यकता वाले 116 अत्यंत संवेदनशील नवजातों को एडवांस्ड नियोनेटल केयर प्रदान की गई, जिस पर 9.30 लाख रुपये खर्च हुए। इसके अतिरिक्त, समय से पहले जन्म, बहु-अंग जटिलताओं अथवा गंभीर चिकित्सीय अस्थिरता से जूझ रहे 64 नवजातों को क्रिटिकल नियोनेटल केयर उपलब्ध करवाई गई, जिस पर 7.88 लाख रुपये खर्च हुए। इसके साथ ही 18 नवजातों को लंबे समय की क्रॉनिक नियोनेटल केयर सहायता भी प्रदान की गई। इसके अलावा, दीर्घकालीन नवजात देखभाल के तहत 17 शिशुओं को शामिल किया गया, जिन्हें ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया और नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस जैसी गंभीर स्थितियों के लिए लंबे समय तक इलाज की आवश्यकता पड़ी, जिसकी लागत 56 हजार रुपये रही। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना अब पंजाब के परिवारों के लिए एक बड़ा स्वास्थ्य सुरक्षा कवच बन रही है और अब तक इसके तहत लगभग 44.8 लाख पंजीकरण हो चुके हैं।

प्राकृतिक फाइबर आधारित होम टेक्सटाइल्स को बढ़ावा देने के लिए ट्राइडेंट ग्रुप और आईसीएआर राष्ट्रीय प्राकृतिक रेशा अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में रणनीतिक सहयोग की पहल

सिटी दर्पण संवाददाता
पंजाब/ चंडीगढ़

ट्राइडेंट ग्रुप ने सस्टेनबल और पर्यावरण-अनुकूल टेक्सटाइल नवाचार की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के अंतर्गत कार्यरत राष्ट्रीय प्राकृतिक रेशा अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आईसीएआर -निनफेट) के साथ रणनीतिक सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य प्राकृतिक फाइबर आधारित नवीन युग के फाइबर आधारित होम टेक्सटाइल उत्पादों के व्यावसायीकरण को गति देना है।

ट्राइडेंट ग्रुप के फाइबर एवं यार्न विभाग के फंक्शनल हेड डॉ. नेमाई चंद्र राय ने आईसीएआर-निनफेट के निदेशक डॉ. डी.बी. शाक्यवार और संस्थान के वैज्ञानिकों व वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर अनुसंधान, तकनीकी विकास और औद्योगिक उपयोग के क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की।

बैठक में प्राकृतिक फाइबरों की वैश्विक स्तर पर बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए नवाचार आधारित और व्यावसायिक रूप से उपयोगी उत्पाद विकसित करने पर जोर दिया गया। प्रस्तावित साझेदारी के तहत दोनों संस्थाएं एक समझौते (एमओयू) पर हस्ताक्षर कर लिनन जैसे कॉटनाइज्ड जूट, हेम्प और अलसी मिश्रित फाइबरों से उन्नत होम टेक्सटाइल उत्पाद विकसित करेंगी।

आईसीएआर-निनफेट की रिसर्च विशेषज्ञता और ट्राइडेंट ग्रुप की मजबूत विनिर्माण क्षमता, उत्पाद विकास अनुभव तथा वैश्विक बाजार पहुंच को मिलाकर पर्यावरण-अनुकूल होम टेक्सटाइल उत्पादों की व्यावसायिक संभावनाओं को मजबूत किया जाएगा। ट्राइडेंट ग्रुप घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में इन उत्पादों की पहुंच बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

सहयोग के तहत कॉटनाइजेशन, ब्लेंडिंग, स्पिनिंग, वीविंग और फिनिशिंग जैसी आधुनिक फाइबर प्रोसेसिंग तकनीकों पर कार्य किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाले और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार टेक्सटाइल समाधान विकसित किए जा सकें।

यह पहल देश में प्राकृतिक फाइबर इकोसिस्टम को मजबूत करने, टिकाऊ विकल्पों को बढ़ावा देने और वैश्विक टेक्सटाइल निर्यात में भारत की स्थिति को और सशक्त बनाने में सहायक मानी जा रही है। ह्यआत्मनिर्भर भारत और हरित औद्योगिक विकास की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप यह साझेदारी टेक्सटाइल क्षेत्र में नवाचार आधारित सतत विकास को आगे बढ़ाने की दिशा में ट्राइडेंट ग्रुप की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

पंजाब में नगर निकाय के 7555 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज

सिटी दर्पण संवाददाता
जैतो

पंजाब में 8 नगर निगमों,76 नगर परिषदों व 21 नगर पंचायतों के लिए 26 मई को चुनाव हो रहे हैं।इन चुनावों में प्रदेश की सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ -साथ कुल 7555 उम्मीदवार चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ -साथ आजाद उम्मीदवार अपनी -अपनी का दावा कर रहे हैं लेकिन यह तो समय ही बताएगा कि ऊंट किस ओर करवट लेता है। यह तो परिणाम आने पर ही सही पता चलेगा। यह नगर निकाय चुनाव जीतने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने एडी चोटी का जोर लगाया है। क्योंकि पंजाब में 2017 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और राजनीतिक पार्टियों का मानना है कि इन चुनावों के परिणाम का आम जनता पर प्रभाव पड़ेगा।पंजाब राज्य चुनाव आयोग के अनुसार 26 मई को होने वाले नगर निकाय आम चुनाव के लिए सभी आवश्यक प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं।

इन चुनावों में कुल 7555 उम्मीदवार मैदान में हैं जिसमें आम आदमी पार्टी के 1802 उम्मीदवार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1550, शिरोमणि अकाली दल 1251, भारतीय जनता पार्टी 1316, बहुजन समाज पार्टी 96 और 1528 उम्मीदवार निर्दलीय व 13 उम्मीदवार अन्य दलों के शामिल हैं।

संक्षिप्त-समाचार

एसआईआर शुरू होने से पहले 90 प्रतिशत तक प्री-मैपिंग करने का लक्ष्य निर्धारित: अनिंदिता मित्रा

चंडीगढ़। पंजाब राज्य में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एस.आई.आर.) शुरू होने से पहले 90 प्रतिशत तक प्री-मैपिंग करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह जानकारी आज यहां मुख्य चुनाव अधिकारी पंजाब अनिंदिता मित्रा ने दी। उन्होंने कहा कि पंजाब राज्य में प्री-मैपिंग के दौरान 84 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं की मैपिंग सफलतापूर्वक पूरी की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि प्री-मैपिंग के दौरान वर्ष 2003 में हुई एस.आई.आर. को आधार बनाकर मौजूदा मतदाता सूचियों के साथ मिलान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि किसी मतदाता की प्री-मैपिंग नहीं होती है, तो उस मतदाता को बी.एल.ओ. द्वारा दिया गया गणना फॉर्म भरकर पुनः बी.एल.ओ. के पास जमा करवाना होगा। इसके बाद संबंधित मतदाता का नाम ड्राफ्ट रोल में जोड़ दिया जाएगा। मुख्य चुनाव अधिकारी पंजाब अनिंदिता मित्रा ने पंजाब के मतदाताओं से अपील की कि वे एस.आई.आर. में बढ़-चढ़कर भाग लें और बी.एल.ओ. के साथ पूरा सहयोग करें।

पंजाब सरकार द्वारा ईद-उल-जुहा (बकरीद) की गजटेड छुट्टी 27 मई की बजाय अब 28 मई को घोषित

चंडीगढ़। पंजाब सरकार द्वारा नेगोशिएबल एक्ट-1881 की धारा 25 के अंतर्गत ईद-उल-जुहा (बकरीद) के संबंध में पंजाब राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों, बोर्डों/कॉरपोरेशनों तथा सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में 28 मई 2026 (वीरवार) को गजटेड छुट्टी घोषित की गई है।इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि पहले ईद-उल-जुहा (बकरीद) के अवसर पर 27 मई 2026 को गजटेड छुट्टी घोषित की गई थी, लेकिन अब इसमें संशोधन करते हुए यह छुट्टी 28 मई 2026 (वीरवार) को कर दी गई है। प्रवक्ता ने बताया कि इस संबंध में पंजाब सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा आज अधिसूचना जारी कर दी गई है।

फिरोजपुर मंडल के 2 टिकट चैकिंग स्टाफ को साइक्लिंग में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए महाराजा रणजीत सिंह अवॉर्ड से सम्मानित

जैतो। उत्तर रेलवे के फिरोजपुर रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक बसंत कुमार ने सोमवार को कहा कि फिरोजपुर मंडल के अमृतसर में कार्यरत टीटीआई अमरजीत सिंह तथा जलंधर सिटी में कार्यरत टीटीआई रणबीर सिंह को साइक्लिंग के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं उल्लेखनीय योगदान के लिए पंजाब सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ह्लमहाराजा रणजीत सिंह अवॉर्डह्व से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार पंजाब सरकार द्वारा खिलाड़ियों को प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च खेल सम्मान है।'महाराजा रणजीत सिंह अवॉर्ड' किसी खिलाड़ी को जीवन में केवल एक बार उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन, उपलब्धियों तथा खेलों में विशेष योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। साइक्लिंग के क्षेत्र में दोनों खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से रेलवे का नाम गौरवान्वित किया है।अंतर्राष्ट्रीय साइकिल चालक अमरजीत सिंह ने वर्ष 2018 में नई दिल्ली में आयोजित एशिया कप की टीम स्प्रिंट स्पर्धा में रजत पदक प्राप्त किया। वर्ष 2019 में थाईलैंड में आयोजित एशियाई चैंपियनशिप की स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक प्राप्त किया। वर्ष 2020 में 1 किमी टाइम ट्रायल स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। वर्ष 2022 गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में कांस्य पदक हासिल किया। उन्होंने 10 वर्षों तक लगातार सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर रिकॉर्ड बनाया हैं तथा एक किलोमीटर टाइम ट्रायल में व्यक्तिगत राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक भी है। मंडल रेल प्रबंधक संजीव कुमार ने उन्हें इस उपलब्धि पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उनकी सफलता रेलवे के खिलाड़ियों एवं युवा प्रतिभाओं के लिए प्रेरणास्रोत है।

पंजाब सरकार ने 26 मई को नगर निगम की आम चुनावों के लिए फैक्ट्रियों में कार्यरत सभी पात्र कामगारों को मतदान हेतु छूट प्रदान की

चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने फैक्ट्रियों सहित पंजाब के विभिन्न संस्थानों में कार्यरत सभी वयस्क कामगारों एवं कर्मचारियों को नगर निगम आम चुनाव 2026 में अपने मताधिकार का प्रयोग करने हेतु छूट देने की घोषणा की है। यह छूट उन संबंधित नगर निगमों के राजस्व अधिकार क्षेत्र में कार्यरत सभी पात्र मतदाताओं पर लागू होगा, जहां 26 मई 2026 को मतदान होना है।

एमसी दीनानगर, एमसी गुरदासपुर, एमसी कादियां और एमसी शाम चौरासी के सदस्यों के चुनाव हेतु आम चुनाव 10 जून 2026 को होंगे: राज्य चुनाव आयोग

चंडीगढ़। स्थानीय निकाय विभाग, पंजाब द्वारा पंजाब म्यूनिसिपल एक्ट, 1911 की धारा 13-ए के अंतर्गत दिनांक 21 मई 2026 को जारी अधिसूचना संख्या 03/01/एँ्रू3ङ्मल्लर(र-2)/टएइ/2026/78 के अनुसार, राज्य चुनाव आयोग ने एमसी दीनानगर, एमसी गुरदासपुर, एमसी कादियां और एमसी शाम चौरासी के सदस्यों के चुनाव हेतु आम चुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। जारी चुनाव कार्यक्रम के अनुसार नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 28 मई 2026 (वीरवार) से शुरू होगी। नामांकन पत्र सुबह 11:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों के कार्यालयों में दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 1 जून 2026 (सोमवार) निर्धारित की गई है। यह नामांकन पत्रों की जांच 2 जून 2026 (मंगलवार) को की जाएगी, जबकि नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 3 जून 2026 (बुधवार) दोपहर 3:00 बजे तक होगी। इन नगर परिषदों के लिए मतदान 10 जून 2026 को सुबह 8:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक करवाया जाएगा। मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद उसी दिन मतगणना की जाएगी। राज्य चुनाव आयोग द्वारा चुनावों को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं।

बलबीर सिद्धू ने मोहाली नगर निगम चुनावों में धांधली का किया खुलासा

सिटी दर्पण संवाददाता
एसएएस नगर

वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने आज यहां कहा कि कांग्रेस के महासचिव कैप्टन संदीप संधू द्वारा राज्य चुनाव आयुक्त को मोहाली नगर निगम चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता के गंभीर उल्लंघन संबंधी एक औपचारिक शिकायत दर्ज करवाई गई है। यह शिकायत पुलिस अधिकारी बलविंदर सिंह झांसल के खिलाफ की गई है।

श्री सिद्धू ने बताया कि शिकायत के माध्यम से चुनाव आयुक्त के ध्यान में लाया गया है कि पुलिस अधिकारी बलविंदर सिंह झांसल अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करते हुए आम आदमी पार्टी (अअढ) के उम्मीदवारों तथा वार्ड नंबर 10, एसएएस नगर से समर्थित स्वतंत्र उम्मीदवार परमजीत सिंह काहलों के पक्ष में मतदाताओं को प्रभावित कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने आगे बताया कि चुनाव आयुक्त को वीडियो सबूत भी सौंपे गए हैं, जिनमें पुलिस स्टिकर लगी अधिकारी की गाड़ी को चुनावी लाभ के लिए शराब की ढुलाई और वितरण करते हुए स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

श्री सिद्धू ने इसे पुलिस तंत्र और सरकारी प्रभाव का खुला दुरुपयोग बताते हुए कहा कि इससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बुनियाद कमजोर होती है।

पंजाब में कानून-व्यवस्था के पूरी तरह चरमराने पर वड़िंग ने पंजाब सरकार को घेरा

सिटी दर्पण संवाददाता
लुधियाना

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष और लुधियाना से सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने लुधियाना नगर निगम और प्रसिद्ध गायक दिलजीत दोसांझ को मिली बम धमकियों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए, कहा है कि ये घटनाएं भगवंत मान सरकार के शासन में पंजाब में कानून-व्यवस्था की पूरी तरह विफल हो चुकी स्थिति को उजागर करती हैं।

वड़िंग ने कहा कि पंजाब आज भय और असुरक्षा के माहौल में जी रहा है, जहां बार-बार बम धमकियां, पुलिस कर्मियों की निशाना बनाकर हत्याएं और आपराधिक घटनाएं चिंताजनक रूप से आम होती जा रही हैं। उन्होंने सवाल किया कि यदि पुलिसकर्मी भी निशाने पर हैं और सरकारी संस्थानों को बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं, तो एक आम नागरिक खुद को कैसे सुरक्षित महसूस कर सकता है?

उन्होंने कहा कि ताजा धमकी की जिम्मेदारी कथित ह्यखालिस्तान नेशनल आर्मीह्व द्वारा लिए जाने की बात सामने आई है, जबकि हाल ही में अमृतसर में एक एएसआई की हत्या की जिम्मेदारी कथित तौर पर ह्यतहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तानह्व ने ली थी, जो पंजाब की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है।

वड़िंग ने सरकार की कार्यप्रणाली पर निशाना साधते हुए, कहा कि भगवंत मान सरकार सोई हुई नजर आ रही है, जबकि पंजाब में हर गुजरते दिन के साथ कानून-व्यवस्था की स्थिति और बिगड़ती जा रही है। लोगों को भय के साए में जीने के लिए छोड़कर केवल विज्ञापनों और सोशल मीडिया वीडियो के सहारे सरकार नहीं चलाई जा सकती।

उन्होंने गुरदासपुर में पुलिसकर्मियों की हत्याओं और राज्यभर में सामने आई विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों से जुड़ी हालिया घटनाओं का उल्लेख करते हुए, कहा कि ये अब अलग-थलग घटनाएं नहीं रह गई हैं, बल्कि बढ़ते सुरक्षा संकट के संकेत हैं, जिससे निपटने में राज्य सरकार विफल रही है।

वड़िंग ने पंजाब सरकार से तत्काल और ठोस कार्रवाई की मांग करते हुए, कहा कि राजनीतिक दिखावेबाजी छोड़कर जनता का विश्वास बहाल करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया जाए।

उन्होंने केंद्र सरकार से भी अपील की है कि बार-बार मिल रही धमकियों और हो रही हत्याओं को गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि पंजाब की शांति और देश की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जा सकती।

उन्होंने कहा कि हम पंजाब की कठिन संघर्षों से हासिल की गई शांति को दांव पर नहीं लगा सकते। हालात और बिगड़ने से पहले सरकार को सख्ती और तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।

साहिबजादा अजीत सिंह नगर में 498 पोलिंग बूथों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना

166 वार्डों में 695 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे 4,80,781 मतदाता

सिटी दर्पण संवाददाता
साहिबजादा अजीत सिंह नगर

जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर में होने जा रहे स्थानीय निकाय चुनावों के लिए 4,80,781 मतदाता कल 166 वार्डों में चुनाव मैदान में उतरे 695 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे।

इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला चुनाव अधिकारी-कम-डिप्टी कमिश्नर श्रीमती कोमल मित्तल ने बताया कि जिले में बनाए गए 498 पोलिंग बूथों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई हैं। मतदान सुबह 8:00 बजे शुरू होगा और शाम 5:00 बजे तक जारी रहेगा।

उन्होंने बताया कि जिले में कुल 2,48,415 पुरुष मतदाता, 2,32,340 महिला मतदाता तथा 26 अन्य मतदाता हैं।उन्होंने बताया कि नगर निगम मोहाली के 50 वार्डों में 227 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। यहां 90,505 पुरुष, 84,844 महिला तथा 8 अन्य मतदाता 184 पोलिंग बूथों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।नगर परिषद जीरकपुर में 31 वार्डों से 124 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। यहां 70,226 पुरुष, 66,191 महिला तथा 8 अन्य मतदाता 128 पोलिंग बूथों पर मतदान करेंगे।

नगर परिषद डेराबस्सी में 18 वार्डों से 79 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जबकि एक उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जा चुका है। यहां 26,888 पुरुष, 24,564 महिला तथा 5 अन्य मतदाता 51 पोलिंग बूथों पर अपने मत का प्रयोग करेंगे।

इसी प्रकार नगर परिषद नया गांव के 21 वार्डों में 87 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। यहां 23,717 पुरुष, 21,266 महिला तथा एक अन्य मतदाता 51 पोलिंग बूथों पर मतदान करेंगे।

लालडू नगर परिषद के 16 वार्डों में 61 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि एक उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जा चुका है। यहां 16,031 पुरुष, 14,360 महिला तथा

3 अन्य मतदाता 33 पोलिंग बूथों पर मतदान करेंगे।

कुराली नगर परिषद के 17 वार्डों में 77 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। यहां 13,332 पुरुष तथा 14,070 महिला मतदाता 33 पोलिंग बूथों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

इसी प्रकार बनूड़ नगर परिषद के 13 वार्डों में 40 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। यहां 7,716 पुरुष, 7,045 महिला तथा एक अन्य मतदाता 18 पोलिंग बूथों पर मतदान करेंगे।

जिला चुनाव अधिकारी श्रीमती कोमल मित्तल ने अतिरिक्त जिला चुनाव अधिकारी श्रीमती सोनम चौधरी के साथ स्कूल ऑफ एमिनेंस, फेज-3बी1, मोहाली स्थित डिस्पैच सेंटर का दौरा कर पोलिंग पार्टियों की रवानगी संबंधी प्रबंधों का जायजा लिया।

उन्होंने बताया कि राज्य चुनाव आयोग, पंजाब के निदेशों के अनुसार सभी पोलिंग बूथों पर सी सी टी वी निगरानी की व्यवस्था की गई है।

उन्होंने आगे बताया कि कुल 498 पोलिंग बूथों में से 66 पोलिंग स्थानों को संवेदनशील तथा 181 को अति संवेदनशील घोषित किया गया है, जहां अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं।

मतदाताओं, विशेषकर बुजुर्गों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि बढ़ती गर्मी को ध्यान में रखते हुए वे सुबह जल्दी मतदान करने के लिए पोलिंग बूथों पर पहुंचें। उन्होंने बताया कि सभी पोलिंग बूथों पर छाया तथा पेयजल की उचित व्यवस्था की गई है।

डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं सुचारू ढंग से संपन्न करवाने तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं।

उन्होंने सभी उम्मीदवारों से भी अपील की कि राज्य चुनाव आयोग, पंजाब द्वारा जारी सभी निदेशों का पालन करते हुए चुनाव प्रक्रिया को सुचारू एवं बिना किसी व्यवधान के संपन्न करवाने में सहयोग दें।

ईरान परमाणु कार्यक्रम रोकने को तैयार ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी का दावा

अमेरिका-ईरान के बीच शांति समझौते की दिशा में तेजी, संवर्धित यूरेनियम के निपटान पर बनी सहमति

एजेंसी (हि.स.)

वाशिंगटन

अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चल रही तनावपूर्ण स्थिति के बीच एक बड़ी कूटनीतिक प्रगति सामने आई है। ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया है कि ईरान सैद्धांतिक रूप से अपने परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए तैयार हो गया है। प्रस्तावित शांति समझौते में अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम के निपटान का प्रावधान भी शामिल किया गया है।

सीबीएस न्यूज और अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारी ने बताया कि ईरान ने मध्यस्थ देशों और वार्ताकारों के माध्यम से इस प्रस्ताव पर सहमति जताई है। अमेरिका और ईरान के बीच अंतिम समझौते को लेकर बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है और दोनों पक्ष कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर व्यापक सहमति तक पहुंच गए हैं। अधिकारी के अनुसार समझौते का मुख्य उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नियंत्रित करना और क्षेत्रीय तनाव को कम करना है। इसके तहत अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम को सुरक्षित तरीके से समाप्त या स्थानांतरित करने की व्यवस्था शामिल की गई है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया

प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत लगातार जारी है। उन्होंने अमेरिकी वार्ताकारों को सलाह देते हुए कहा कि समय अमेरिका के पक्ष में है, इसलिए समझौते को लेकर जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। ट्रंप ने शनिवार को मध्य पूर्व के नेताओं के साथ चर्चा के बाद भी संकेत दिए थे कि ईरान के साथ शांति समझौता लगभग तय हो चुका है और अब केवल कुछ शर्तों पर अंतिम बातचीत चल रही है। व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने भी माना है कि समझौते को अंतिम रूप देने में अभी कुछ दिन लग सकते हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच बढ़ती सहमति को पश्चिम एशिया में स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

'ईरान में किसी को नहीं पता मोजतबा खामेनेई कहां छुपे हैं'

वाशिंगटन। ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई कहां छुपे हैं, यह उनके देश के अधिकारियों तक को पता नहीं है। ऐसा अमेरिकी अधिकारियों का कहना है। इन अधिकारियों ने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के हवाले से कहा कि ईरान के सर्वोच्च नेता किसी अज्ञात जगह पर छुपे हुए हैं। सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले की जानकारी रखने वाले अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की उन पर नजर है। मोजतबा खामेनेई असल में किसी अज्ञात जगह पर छुपे हुए हैं। वहां बाहरी दुनिया से उनका संपर्क बहुत कम है और उन तक पहुंचने का एकमात्र जरिया संदेशवाहकों का एक जटिल जाल है। इसलिए ट्रंप प्रशासन के साथ काम करने के लिए अधिकृत ईरानी अधिकारियों को अपनी ही सरकारी व्यवस्था के भीतर संवाद करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

राष्ट्रीय हितों से समझौता स्वीकार नहीं: ईरानी सांसद

तेहरान। अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते को लेकर जारी चचार्ओं के बीच ईरान के एक वरिष्ठ सांसद ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि राष्ट्रीय हितों और रणनीतिक मुद्दों पर किसी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। उनके बयान ने दोनों देशों के बीच चल रही कूटनीतिक प्रक्रिया को लेकर नई बहस छेड़ दी है। ईरानी सांसद महमूद नबावियन ने कहा कि यदि भविष्य में अमेरिका के साथ होने वाले किसी भी समझौते में ईरान की प्रमुख मांगों और सुरक्षा संबंधी हितों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता है, तो ऐसा समझौता देश के लिए लाभकारी नहीं माना जाएगा। उनका कहना था कि किसी भी समझौते का उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की रक्षा होना चाहिए, न कि रणनीतिक स्थिति को कमजोर करना।

नेपाल में महंगाई चरम पर, सब्जियों के दाम में 300 प्रतिशत से अधिक उछाल

- पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमत और वैश्विक तनाव का असर, आम लोगों की बढ़ी परेशानी

फोटोः हि.स.

एजेंसी (हि.स.)

काठमांडू

नेपाल में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में भारी वृद्धि, अमेरिकी डॉलर की विनिमय दर में उतार-चढ़ाव और अंतरराष्ट्रीय भू-राजनीतिक तनाव के कारण उपभोग की वस्तुओं के दाम तेजी से बढ़े हैं। सबसे ज्यादा असर सब्जियों की कीमतों पर देखने को मिला है, जहां कुछ वस्तुओं के दाम में 300 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

नेपाल के वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से जारी 'मूल्य विश्लेषण रिपोर्ट' के अनुसार मार्च की तुलना में अप्रैल महीने में चावल, दाल, अंडा, केला और चीनी के दाम बढ़े हैं। वहीं हरी सब्जियों और फलों की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव देखा गया। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च और अप्रैल के दौरान मौसमी सब्जियों की कीमतों में असामान्य वृद्धि दर्ज की गई। मार्च में 23 रुपये प्रति किलो बिकने वाली एक सब्जी की कीमत बढ़कर 100 रुपये तक पहुंच गई, यानी इसमें 334.79 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कई अन्य सब्जियों में भी 250 प्रतिशत तक मूल्य वृद्धि दर्ज की गई। लौकी की कीमत में 165 प्रतिशत, कद्दू में 138.89 प्रतिशत और खीरे में 125 प्रतिशत तक बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसके अलावा छोटे स्थानीय टमाटर, स्थानीय फूलगोभी, ब्रोकली और जिरी साग जैसी सब्जियों के दाम भी 100 प्रतिशत से अधिक बढ़े। विभाग ने इसे बाजार में बढ़ती अस्थिरता का संकेत बताया है। मार्च से मई के तीसरे सप्ताह तक नेपाल आयल निगम ने पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में छह बार संशोधन किया। 15 मार्च को पेट्रोल की कीमत 172 रुपये प्रति लीटर और डीजल-मिट्टी तेल 152 रुपये प्रति लीटर था, जो 15 अप्रैल तक बढ़कर क्रमशः 219 रुपये और 237 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया। हालांकि 30 अप्रैल को कुछ राहत देते हुए पेट्रोल 217 रुपये और डीजल-मिट्टी तेल 225 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया, लेकिन रसोई गैस का दाम बढ़कर 2,160 रुपये प्रति सिलेंडर हो गया। विभाग के अनुसार ईंधन की कीमतों में लगातार वृद्धि के कारण यातायात किराया, हवाई भाड़ा और माल ढुलाई महंगी हो गई, जिससे रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों पर सीधा असर पड़ा। रिपोर्ट में अमेरिकी डॉलर की विनिमय दर को भी महंगाई का बड़ा कारण बताया गया है। मार्च में डॉलर की खरीद दर 148.39 रुपये से बढ़कर 151.56 रुपये तक पहुंच गई।

जैसलमेर में मिला प्राकृतिक गैस का नया भंडार डांडेवाला फील्ड में बढ़ी ऊर्जा क्षेत्र की उम्मीदें

एजेंसी (हि.स.)

जैसलमेर

पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर जिले में प्राकृतिक गैस का नया भंडार मिलने से देश के ऊर्जा क्षेत्र को बड़ी सफलता मिली है। जैसलमेर के डांडेवाला क्षेत्र में सरकारी कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड ने जमीन से करीब 950 मीटर गहराई पर स्थित 'सानू फॉर्मेशन' से पहली बार प्राकृतिक गैस का सफल बहाव हासिल किया है।

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इसकी जानकारी साझा करते हुए इसे देश के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। परीक्षण के दौरान यहां से प्रतिदिन करीब 25 हजार स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस उत्पादन मापा गया। विशेषज्ञों के अनुसार यह गैस उच्च गुणवत्ता वाली है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बेहद कम है, जिससे इसे पर्यावरण के लिहाज से स्वच्छ ईंधन माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि देश के भीतर प्राकृतिक गैस का नया स्रोत मिलने से भारत की विदेशी तेल और गैस आयात पर निर्भरता कम होगी। उन्होंने ऑयल इंडिया लिमिटेड के वैज्ञानिकों और तकनीकी टीम की सराहना करते हुए कहा कि यह खोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' विजन को मजबूती देगी। उन्होंने कहा कि जैसलमेर में मिली यह सफलता देश में स्वच्छ ऊर्जा के विकल्प बढ़ाने में मददगार साबित होगी, जिसका लाभ घरेलू उपयोग के साथ उद्योगों को भी मिलेगा। डांडेवाला फील्ड में अब तक गहरे कुओं से गैस उत्पादन होता रहा है, लेकिन पहली बार अपेक्षाकृत कम गहराई पर स्थित 'सानू फॉर्मेशन' से गैस का सफल प्रवाह हासिल किया गया है।

मणिपुर में पांच उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार और गोला-बारूद बरामद

इंफाल। मणिपुर के चुराचांदपुर और इंफाल क्षेत्रों में सुरक्षा बलों द्वारा बीते 24 घंटे में चलाए गए अलग-अलग अभियानों में पांच उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से हथियार, गोला-बारूद और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। पुलिस ने सोमवार को बताया कि चलाए गए एक अभियान में सुरक्षा बलों ने चुराचांदपुर थाना क्षेत्र के एडेंथर रेंगकाई गांव निवासी जेहोवा राजा दत्ता को उसके घर से गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से एक इंसास राइफल, चार मैगजीन, 5.56 मिमी के 36 जिंदा कारतूस, एक कैमोफ्लाज बुलेटप्रूफ जैकेट और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। वहीं, मणिपुर रिवोल्यूशनरी आर्मी (एमआरए) के दो सक्रिय कैडरों को वांगखेई आयंगपल्ली रोड से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार उग्रवादियों की पहचान कोंगबा नांदेइबाम लैकाई, इंफाल ईस्ट निवासी निंगथौजाम विक्की सिंह उर्फ मुनाल तथा लाफुपत तेरा मयाई लैकाई, इंफाल वेस्ट निवासी निंगथौजाम ईश्वरचंद्र सिंह उर्फ लोइया उर्फ थावाइलकपा के रूप में हुई है, जो वर्तमान में लांगजिंग माखा लैकाई में रह रहा था। इसके अलावा, संयुक्त कुकी नेशनल आर्मी (यूकेएनए) के दो सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया गया।

अब आर्मी हॉस्पिटल में आधुनिक रेडियोथेरेपी तकनीक से हो सकेगा कैंसर का उपचार

एजेंसी (हि.स.)

नई दिल्ली

फोटोः हि.स.

दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल (रिसर्च एंड रेफरल) में अब कैंसर का इलाज आधुनिक रेडियोथेरेपी तकनीक से हो सकेगा, क्योंकि सोमवार को रिंग गैन्ट्री आधारित लीनियर एक्सेलरेटर की शुरूआत की गई है। अस्पताल के विकिरण ऑन्कोलॉजी विभाग में यह उन्नत तकनीक कैंसर मरीजों के लिए वरदान साबित होगी, जिससे उपचार क्षमता में वृद्धि होने की उम्मीद है। आर्मी हॉस्पिटल के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल अविनाश दास ने बताया कि रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में शुरू की गई यह सुविधा सेवारत कर्मियों, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए उन्नत रेडियोथेरेपी तक पहुंच में सुधार करेगी। यह लीनियर एक्सेलरेटर वॉल्यूमेट्रिक माड्यूलेटेड आर्क थेरेपी, इंटेंसिटी-मॉड्यूलेटेड रेडिएशन थेरेपी, इमेज-गाइडेड रेडिएशन थेरेपी, स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडिएशन थेरेपी और स्टीरियोटैक्टिक रेडियोसर्जरी सहित आधुनिक रेडियोथेरेपी तकनीकों को प्रदान करने में सक्षम है। यह आसपास के सामान्य ऊतकों पर विकिरण के प्रभाव को कम करते हुए ट्यूमर कोशिकाओं तक सटीक विकिरण पहुंचाने में मदद करता है, जिससे उपचार के बेहतर परिणाम और रोगी की बेहतर देखभाल सुनिश्चित होती है। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा (एएफएमएस) के अंतर्गत लीनियर एक्सेलरेटर की खरीद पहले के उपकरणों की तुलना में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन पुरानी तकनीक आधारित उपकरणों का अब इस्तेमाल नहीं किया जाता है।

व्हाट्सएप पर मिलेंगी सरकारी सेवाएं, गुजरात सरकार और मेटा के बीच हुआ समझौता

गांधीनगर। गुजरात सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस को नई दिशा देते हुए नागरिकों को व्हाट्सएप के माध्यम से सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ह्यनागरिक देवो भवःह्व की परिकल्पना को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार और मेटा प्लेटफॉर्म इंक (टीइं ढ'ङ्क्ष्म्रे२ क्ल्लू.) के बीच गांधीनगर में व्हाट्सएप आधारित सिटीजन सर्विस डिलीवरी को लेकर महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में हुए इस समझौते को गुजरात में वन डे गवर्नेंस से व्हाट्सएप गवर्नेंस की ओर बढ़ता बड़ा कदम माना जा रहा है। राज्य सरकार ने पहले ही ह्यसुगम डिजिटल गुजरातह्व पहल के तहत पांच प्रमुख विभागों की लगभग 20 नागरिक केंद्रित सेवाएं व्हाट्सएप चैटबॉट के माध्यम से उपलब्ध कराई हैं। अब इस नई साझेदारी के जरिए इन सेवाओं को और अधिक सरल, तेज और प्रभावी बनाया जाएगा। इस पहल के लागू होने के बाद राज्य के नागरिक अंग्रेजी और गुजराती भाषा में एक ही व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ अपने मोबाइल फोन पर घर बैठे प्राप्त कर सकेंगे। इससे लोगों को अलग-अलग सरकारी पोर्टल पर जाने या सरकारी कार्यालयों में लंबी कतारों में खड़े रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

तेज रफ्तार कार ने बाइक और मोपेड को मारी टक्कर, दो की मौत, आठ घायल

एजेंसी (हि.स.)

महेसाणा

फोटोः हि.स.

गुजरात के महेसाणा जिले में विजापुर के मोतीपुरा गांव के पास रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आठ अन्य घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब राजस्थान की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर बाइक और मोपेड से जा टकराई।

जानकारी के अनुसार, कार चालक ने अचानक वाहन से नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद कार ने सड़क से गुजर रहे बाइक और मोपेड को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों दोपहिया वाहन सड़क से उछलकर पास के खेत में जा गिरे। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। इस हादसे में बाइक और मोपेड सवार दोनों व्यक्तियों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं कार में सवार आठ लोगों को गंभीर और सामान्य चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तत्काल विजापुर सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही विजापुर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने बताया की दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण कार की तेज रफ्तार और चालक की लापरवाही माना जा रहा है, जिसकी जांच की जा रही है।

सिक्किम : प्रकृति की गोद में बसा स्वर्ग

गंगटोक

सिक्किम की राजधानी गंगटोक राज्य का सबसे लोकप्रिय और विकसित पर्यटन स्थल माना जाता है। समुद्र तल से लगभग 5,500 फीट की ऊंचाई पर बसा यह शहर प्राकृतिक सुंदरता, आधुनिक जीवनशैली और बौद्ध संस्कृति का अनोखा संगम प्रस्तुत करता है। चारों ओर फैली हरी-भरी पहाड़ियां, बादलों से ढकी घाटियां और ठंडी हवाएं यहां आने वाले पर्यटकों को सुकून का अनुभव कराती हैं। गंगटोक का एमजी रोड यहां का सबसे प्रसिद्ध आकर्षण है। यह सड़क पूरी तरह साफ-सुथरी और वाहनों से मुक्त रहती है, जहां पर्यटक आराम से घूमते हुए स्थानीय बाजार, कैफे और पारंपरिक सिक्किमी व्यंजनों का आनंद लेते हैं। शाम के समय यहां की रोशनी और पहाड़ी मौसम का नजारा बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। गंगटोक रोपवे से पूरे शहर और आसपास की पहाड़ियों का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। इसके अलावा ताशी व्यू पॉइंट से कंचनजंगा पर्वत की बर्फ से ढकी चोटियों का शानदार नजारा देखा जा सकता है। शहर में स्थित एंचे मठ और दो द्रुल चोर्टेन जैसे धार्मिक स्थल बौद्ध संस्कृति और शांति का अनुभव कराते हैं। गंगटोक एडवेंचर प्रेमियों के लिए भी खास जगह है, जहां ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग और बाइक राइडिंग जैसी गतिविधियों का आनंद लिया जा सकता है।

भारत के उत्तर-पूर्वी भाग में स्थित सिक्किम देश का एक छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत और आकर्षक राज्य है। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर यह प्रदेश अपनी बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाओं, हरी-भरी घाटियों, शांत झीलों, बहती नदियों और प्राचीन बौद्ध मठों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हिमालय की गोद में बसे इस राज्य की मनमोहक वादियां हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। सिक्किम की सबसे बड़ी पहचान दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा पर्वत है। बर्फ से ढकी इसकी चमकदार चोटियां सूर्योदय और सूर्यास्त के समय बेहद अद्भुत दिखाई देती हैं। प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए यह दृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं माना जाता। यहां की स्वच्छ हवा, शांत वातावरण और हरियाली लोगों को शहरों की भागदौड़ से दूर सुकून का एहसास कराती है। सिक्किम केवल प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी समृद्ध संस्कृति और बौद्ध परंपराओं के लिए भी जाना जाता है। यहां स्थित रुमटेक, पेमा यांग्त्से और एंचे जैसे प्रसिद्ध मठ पर्यटकों को आध्यात्मिक शांति का अनुभव कराते हैं। रंग-बिरंगे प्रार्थना झंडे, बौद्ध स्तूप और पारंपरिक संस्कृति यहां के वातावरण को और भी खास बनाते हैं। राज्य की राजधानी गंगटोक आधुनिकता और प्राकृतिक सुंदरता का अनोखा संगम है। यहां का एमजी रोड, रोपवे और आसपास के व्यू पॉइंट पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। इसके अलावा त्सोमगो झील, नाथू ला पास, युमथांग वैली और पेलिंग जैसे पर्यटन स्थल अपनी अलग पहचान रखते हैं। बर्फीली चोटियां, फूलों से ढकी घाटियां और शांत झीलें यहां आने वाले पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। एडवेंचर पसंद लोगों के लिए भी सिक्किम किसी जन्नत से कम नहीं है। यहां ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग और माउंटेन बाइकिंग जैसी कई रोमांचक गतिविधियों का आनंद लिया जा सकता है। कंचनजंगा नेशनल पार्क में दुर्लभ वन्यजीव और घने जंगल प्रकृति प्रेमियों को खास आकर्षित करते हैं। सिक्किम की सबसे बड़ी खासियत यहां की स्वच्छता और अनुशासित जीवनशैली है। यह भारत के सबसे साफ-सुथरे राज्यों में गिना जाता है। यहां के लोग बेहद सरल, शांत और मेहमाननवाज होते हैं, जो पर्यटकों का खुले दिल से स्वागत करते हैं। स्थानीय भोजन, पारंपरिक त्योहार और सांस्कृतिक कार्यक्रम यहां की यात्रा को और यादगार बना देते हैं। प्राकृतिक सुंदरता, शांति, संस्कृति और रोमांच का अनोखा संगम होने के कारण सिक्किम हर यात्री के लिए एक यादगार पर्यटन स्थल बन चुका है। जो लोग प्रकृति के करीब कुछ शांत और खूबसूरत पल बिताना चाहते हैं, उनके लिए सिक्किम किसी स्वर्ग से कम नहीं है।

छांगू (त्सोमगो) झील

छांगू झील, जिसे त्सोमगो लेक भी कहा जाता है, सिक्किम की सबसे खूबसूरत प्राकृतिक झीलों में से एक है। यह झील गंगटोक से लगभग 40 किलोमीटर दूर और समुद्र तल से करीब 12,400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच स्थित यह झील मौसम के अनुसार अपना रंग बदलती हुई दिखाई देती है। सर्दियों में झील पूरी तरह बर्फ की चादर से ढक जाती है, जबकि गर्मियों में इसका नीला और शांत पानी पर्यटकों को बेहद आकर्षित करता है। झील के आसपास फैले बर्फीले पहाड़ और ठंडी हवाएं यहां के वातावरण को और मनमोहक बना देते हैं। यहां आने वाले पर्यटक पारंपरिक पोशाक पहनकर फोटोग्राफी कराते हैं और याक की सवारी का आनंद लेते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार यह झील धार्मिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। कहा जाता है कि पुराने समय में बौद्ध भिक्षु झील के पानी के रंग को देखकर भविष्य की भविष्यवाणी किया करते थे। प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के कारण यह स्थान प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए बेहद खास माना जाता है।

नाथू ला पास

नाथू ला पास सिक्किम का सबसे चर्चित और ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। यह दर्रा भारत और चीन की सीमा पर लगभग 14,140 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। नाथू ला प्राचीन सिल्क रूट का महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था, जिसके माध्यम से भारत और तिब्बत के बीच व्यापार होता था। गंगटोक से नाथू ला तक का सफर बेहद रोमांचकारी माना जाता है। रास्ते में बर्फ से ढकी पहाड़ियां, घुमावदार सड़कें और बादलों से घिरे दृश्य पर्यटकों को रोमांच से भर देते हैं। यहां भारतीय सेना की मौजूदगी पर्यटकों में देशभक्ति की भावना पैदा करती है। सीमा क्षेत्र होने के कारण यहां जाने के लिए विशेष परमिट की आवश्यकता होती है। सर्दियों के दौरान यह पूरा इलाका बर्फ से ढक जाता है, जिससे इसकी सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है। यहां से दिखाई देने वाले पर्वत, घाटियां और बर्फीले मैदान पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। नाथू ला पास केवल प्राकृतिक सुंदरता ही नहीं, बल्कि भारत के सामरिक महत्व और ऐतिहासिक विरासत को भी दर्शाता है।

युमथांग वैली

युमथांग वैली को 'वैली ऑफ फ्लावर्स' यानी फूलों की घाटी कहा जाता है। यह घाटी उत्तर सिक्किम में लगभग 11,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। चारों ओर फैली हरियाली, बर्फीली चोटियां, रंग-बिरंगे फूल और बहती नदियां इस घाटी को स्वर्ग जैसा रूप प्रदान करती हैं। वसंत ऋतु के दौरान यहां हजारों प्रकार के फूल खिलते हैं, जिनमें रोडोडेंड्रोन सबसे प्रमुख माना जाता है। फूलों से ढकी यह घाटी पर्यटकों को बेहद आकर्षित करती है। यहां बहने वाली तीस्ता नदी की सहायक नदियां और ठंडी हवाएं वातावरण को और सुहावना बना देती हैं। सर्दियों में यह पूरा क्षेत्र बर्फ से ढक जाता है और चारों ओर सफेद चादर जैसी सुंदरता दिखाई देती है। युमथांग घाटी प्राकृतिक प्रेमियों, ट्रैकिंग करने वालों और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए बेहद खास मानी जाती है। घाटी के पास स्थित गर्म पानी के झरने भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हैं।

पेलिंग

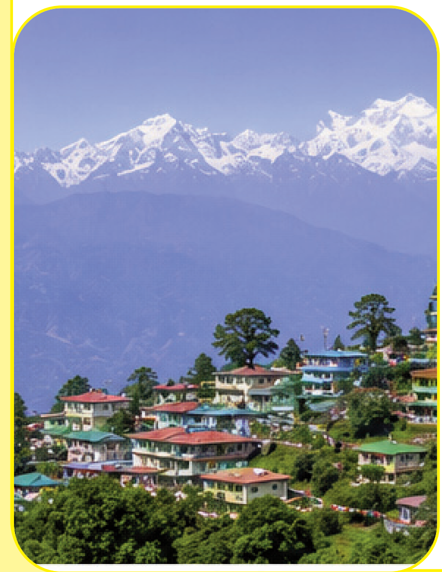

पेलिंग सिक्किम का एक शांत और बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है। यह स्थान पश्चिम सिक्किम में स्थित है और यहां से दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। सुबह के समय सूरज की किरणें जब बर्फीली चोटियों पर पड़ती हैं, तब यहां का दृश्य बेहद मनमोहक लगता है। पेलिंग अपने झरनों, मठों और प्राकृतिक वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। यहां स्थित कंचनजंगा फॉल्स और रिम्बी वाटरफॉल पर्यटकों को खूब आकर्षित करते हैं। पेमा यांग्त्से मठ सिक्किम के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण बौद्ध मठों में शामिल है, जहां पर्यटक बौद्ध संस्कृति और कला को करीब से देख सकते हैं। पेलिंग का ग्लास स्काई वॉक और विशाल चेनरेजिग प्रतिमा भी यहां के प्रमुख आकर्षण हैं। एडवेंचर पसंद पर्यटक यहां ट्रैकिंग और कैंपिंग का भी आनंद लेते हैं। शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता के कारण पेलिंग परिवार और हनीमून यात्रियों के बीच काफी लोकप्रिय है।

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए तैयार भारतीय महिला हॉकी टीम, पहला मुकाबला आज

नेशंस कप की तैयारी के तहत खेलेगी चार मैचों की मैत्री श्रृंखला

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

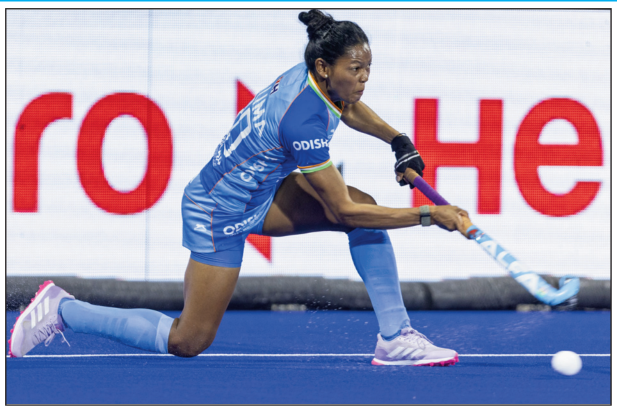

भारतीय महिला हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चार मैचों की बहुप्रतीक्षित मैत्री श्रृंखला खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह दौरा आगामी एफआईएच महिला हॉकी नेशंस कप न्यूजीलैंड 2025-26 की तैयारियों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।श्रृंखला का पहला मुकाबला 26 मई को पर्थ हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा।

इस साल की शुरूआत में अर्जेंटीना दौरे पर शानदार प्रदर्शन करने के बाद भारतीय टीम आत्मविश्वास से भरी हुई है। दुनिया की दूसरे नंबर की टीम अर्जेंटीना के खिलाफ भारत ने चार मैचों की श्रृंखला 2-2 से बराबर की थी। शुरूआती दो मुकाबले हारने के बाद भारतीय टीम ने दमदार वापसी कर अपनी क्षमता का परिचय दिया था। मुख्य कोच सजॉर्ड मारिजने की देखरेख में भारतीय टीम ने हाल के हफ्तों में साई बेंगलुरु में आयोजित राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में कड़ी तैयारी की। खिलाड़ियों ने सामरिक अभ्यास, पेनल्टी कॉर्नर संयोजन, फिटनेस और संरचनात्मक खेल पर विशेष ध्यान दिया। टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने दौरे को लेकर हॉकी इंडिया के हवाले से कहा,पूरी टीम इस दौरे को लेकर बेहद उत्साहित है। ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ उनके घरेलू मैदान पर खेलना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है और यही चुनौती हमें इस समय चाहिए। पर्थ में होने वाला हर मुकाबला हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। उन्होंने आगे कहा,हम ऑकलैंड में होने वाले नेशंस कप में आत्मविश्वास और सकारात्मक लय के साथ उतरना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया हमें हमारी सीमाओं तक चुनौती देगा और हम इस अवसर का उपयोग खुद को और मजबूत टीम बनाने के लिए करना चाहते हैं। 22 सदस्यीय भारतीय टीम में अनुभव और युवा खिलाड़ियों का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिल रहा है। सोनम, हीना बानो और लालथांतलुआंगी जैसी युवा खिलाड़ी भी अपनी छाप छोड़ने को तैयार हैं। एफआईएच विश्व रैंकिंग में नौवें स्थान पर मौजूद भारतीय टीम आठवें स्थान की ऑस्ट्रेलियाई टीम को कड़ी चुनौती देने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला मुकाबला 26 मई को भारतीय समयानुसार शाम 5 बजे खेला जाएगा।

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया कार्यक्रम

पहला मैच – 26 मई, शाम 5:00 बजे
दूसरा मैच – 27 मई, शाम 5:00 बजे
तीसरा मैच – 29 मई, सुबह 11:00 बजे
चौथा मैच – 30 मई, सुबह 11:00 बजे

भारतीय महिला हॉकी टीम

गोलकीपरः सविता, बिचु देवी खारीबाम
डिफेंडरः निकी प्रधान, इशिका चौधरी, सुशीला चानू पुखरामबम, लालथांतलुआंगी, ज्योति, शिल्पी डबास
मिडफील्डरः सलीमा टेटे, लालरेमसियामी, नेहा, साक्षी राणा, सुनेलिता टोप्पो, दीपिका सोरेंग, सोनम
फॉरवर्डः नवनीत कौर, बलजीत कौर, दीपिका, अन्नू, इशिका, हीना बानो, ऋतुजा दादासो पिसाल।

यूनिटी कप के लिए 17 खिलाड़ियों के साथ लंदन पहुंची भारतीय फुटबॉल टीम

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

फोटोः हि.स.

भारतीय सीनियर पुरुष फुटबॉल टीम यूनिटी कप 2026 में भाग लेने के लिए 17 खिलाड़ियों के साथ 24 मई को लंदन पहुंच गई। रविवार तड़के बेंगलुरु से रवाना हुई भारतीय टीम 2002 के बाद पहली बार ब्रिटिश धरती पर कोई मुकाबला खेलने गई है। मुख्य कोच खालिद जमील की टीम ने 22 मई को बेंगलुरु में अभ्यास शिविर शुरू किया था, जो इंडियन सुपर लीग 2025-26 के समापन के एक दिन बाद लगाया गया था। हालांकि, 23 मई को मोहम्मडन बागान सुपर जायंट ने अपने खिलाड़ियों को राष्ट्रीय शिविर से वापस बुला लिया। इसके बाद भारत बाकी 17 खिलाड़ियों के साथ लंदन रवाना हुआ। गोलकीपर ऋतिक तिवारी अलग से यात्रा कर रहे हैं और आज टीम से जुड़ेंगे।

फीफा रैंकिंग में 136वें स्थान पर मौजूद भारत का सामना 27 मई की मध्यरात्रि (भारतीय समयानुसार 28 मई) को दूसरे सेमीफाइनल में जमैका (71वीं रैंकिंग) से होगा। पहले सेमीफाइनल में 26वीं रैंकिंग वाली नाइजीरिया टीम का मुकाबला 130वीं रैंकिंग वाली जिम्बाब्वे से होगा। दोनों सेमीफाइनल हारने वाली टीमें 30 मई को तीसरे स्थान के मुकाबले में आमने-सामने होंगी। प्रतियोगिता के सभी मुकाबले लंदन स्थित 'द वैली' स्टेडियम में खेले जाएंगे, जो चार्लटन एथलेटिक फुटबॉल क्लब का घरेलू मैदान है। मैचों का सीधा प्रसारण फैनकोड पर किया जाएगा।

यूनिटी कप 2026 के लिए भारत की टीम

गोलकीपरः गुरप्रीत सिंह संधू, ऋतिक तिवारी, अल्बिनो गोम्स।
डिफेंडरः राहुल भेके, निखिल पुजारी, रोशन सिंह नाओरेम, संदेश झिंगन, आकाश मिश्रा, बिजॉय वर्गीज, प्रमवीर।
मिडफील्डरः जैक्सन सिंह थौनाओजाम, नौफल पीएन, रिकी शाबोंग।
फॉरवर्डः रयान विलियम्स, एडमंड लालरिंडिका, लालियानजुआला छांगते, रहीम अली, फारुख चौधरी।

यूनिटी कप 2026 कार्यक्रम

पहला सेमीफाइनल- 27 मई, रात 12:00 बजे (भारतीय समयानुसार) नाइजीरिया बनाम जिम्बाब्वे। **दूसरा सेमीफाइनल**- 28 मई, रात 12:00 बजे (भारतीय समयानुसार) जमैका बनाम भारत। **फाइनल और तीसरे स्थान का मुकाबला**- 30 मई 2026 **स्थानः** द वैली स्टेडियम, लंदन।

आईपीएल 2026 प्लेऑफ चरण के फैन पार्क पांच शहरों में होंगे आयोजित

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने सोमवार को टाटा इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के प्लेऑफ चरण के लिए फैन पार्कों के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इस पहल के तहत देश के पांच राज्यों के पांच शहरों में क्रिकेट प्रशंसकों को आईपीएल प्लेऑफ मुकाबलों का रोमांचक अनुभव मिलेगा।

आईपीएल फैन पार्क 29 और 31 मई को आयोजित किए जाएंगे, जहां प्रशंसक मेले जैसे माहौल में आईपीएल प्लेऑफ के रोमांच का आनंद उठा सकेंगे। इन फैन पार्कों में टाटा आईपीएल 2026 प्लेऑफ मुकाबलों का लाइव प्रसारण किया जाएगा।इसके साथ ही दर्शकों के लिए संगीत, मनोरंजन, फूड कोर्ट, बच्चों के खेलने के क्षेत्र और कई इंटरैक्टिव गतिविधियों की भी व्यवस्था रहेगी। प्रशंसकों के लिए वर्चुअल बैटिंग जोन, बॉलिंग नेट्स, फेस पेंटिंग और लोकप्रिय खेल गतिविधियां जैसे पिच परफेक्ट, गेम ऑफ थ्रोस और डोंट मिस द बॉल भी आकर्षण का केंद्र रहेंगी।

इन शहरों में फैन पार्क होंगे आयोजित

ग्वालियर, मध्य प्रदेश
गाजीपुर, उत्तर प्रदेश
मंगलुरु, कर्नाटक
काकीनाडा, आंध्र प्रदेश
अगरतला, त्रिपुरा

डीपीवीएल चरण-1 ट्रायल्स में दिल्ली के युवा वॉलीबॉल खिलाड़ियों का दिखा जबरदस्त उत्साह

नई दिल्ली। दिल्ली प्रो वॉलीबॉल लीग (डीपीवीएल) के पहले चरण के ट्रायल्स में राजधानी के उभरते वॉलीबॉल खिलाड़ियों का भारी उत्साह देखने को मिला। भीषण गर्मी और लू जैसी कठिन परिस्थितियों के बावजूद बड़ी संख्या में युवा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और खेल के प्रति अपना समर्पण, जु ट्रायल्स में दिल्ली वॉलीबॉल संघ के सदस्य कुलबीर सिंह और प्रियंक शर्मा भी मौजूद रहे। उनकी उपस्थिति ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने का काम किया। इन ट्रायल्स का उद्देश्य जमीनी स्तर से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान करना था। कई युवा खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से चयनकर्ताओं को प्रभावित किया। डीपीवीएल प्रबंधन ने प्रतिभागियों की गुणवत्ता पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि लीग का लक्ष्य दिल्ली में भविष्य के वॉलीबॉल सितारों को मजबूत मंच प्रदान करना है। पारदर्शी और पेशेवर चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए लीग ने अनुभवी चयन समिति का गठन किया था। खिलाड़ियों का मूल्यांकन तकनीकी क्षमता, फिटनेस, खेल की समझ और कोर्ट पर प्रदर्शन के आधार पर किया गया। ट्रायल्स के दौरान भारतीय वॉलीबॉल खिलाड़ी विनीत कुमार और प्रिंस मलिक भी पहुंचे।

टेनिस ऑस्ट्रेलिया के नए सीईओ बने एंड्रयू अब्डो, क्रेग टाइली की लेंगे जगह

एजेंसी (हि.स.)
मेलबर्न

ऑस्ट्रेलियाई टेनिस संस्था 'टेनिस ऑस्ट्रेलिया' ने सोमवार को नेशनल रग्बी लीग (एनआरएल) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एंड्रयू अब्डो को नया सीईओ नियुक्त किया है। वह क्रेग टाइली की जगह लेंगे, जिन्होंने फरवरी में अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की थी। ऑस्ट्रेलिया की दोनों खेल संस्थाओं ने सोमवार को आधिकारिक बयान जारी कर इस नियुक्ति की पुष्टि की। क्रेग टाइली ने फरवरी में बताया था कि वह ऑस्ट्रेलियन ओपन टूनार्मेंट निदेशक और टेनिस ऑस्ट्रेलिया के सीईओ पद छोड़कर अमेरिका टेनिस संघ (यूएसटीए) से जुड़ेंगे, जो यूएस ओपन का संचालन करता है।

दक्षिण अफ्रीका मूल के टाइली वर्ष 2006 में ऑस्ट्रेलियन ओपन के टूनार्मेंट निदेशक बने थे। उनके कार्यकाल में टूनार्मेंट का विस्तार 15-दिवसीय आयोजन तक हुआ और दर्शक संख्या व राजस्व के कई रिकॉर्ड टूटे। वर्ष 2013 में उन्हें टेनिस ऑस्ट्रेलिया का सीईओ बनाया गया था।

नए सीईओ एंड्रयू अब्डो भी दक्षिण अफ्रीका से हैं। वह वर्ष 2013 से ऑस्ट्रेलिया की नेशनल रग्बी लीग से जुड़े हुए हैं। शुरूआत में उन्होंने मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी के रूप में काम किया और वर्ष 2020 में सीईओ बने। कोविड-19 महामारी के दौरान लीग को संभालने, विस्तार और विकास में उनकी अहम भूमिका रही। अब्डो ने अपने बयान में कहा, टेनिस ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियाई खेलों में एक विशेष पहचान है। ऑस्ट्रेलियन ओपन पहले से ही दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजनों में शामिल है। अब लक्ष्य इसे और आगे ले जाना है – एक वैश्विक आयोजन, शानदार फैन अनुभव और ज्यादा लोगों को टेनिस से जोड़ने वाले मंच के रूप में।

टेनिस ऑस्ट्रेलिया ने बताया कि वैश्विक स्तर पर भर्ती प्रक्रिया के दौरान 150 से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, लेकिन उच्चस्तरीय खेल लीग में नेतृत्व अनुभव के कारण अब्डो सबसे उपयुक्त साबित हुए। क्रेग टाइली ने कहा, टेनिस ऑस्ट्रेलिया देश के सबसे लोकप्रिय खेल संगठनों में से एक है और इसमें लगातार भागीदारी बढ़ रही है। हमारे पास विश्वस्तरीय खिलाड़ी और अगली पीढ़ी के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों व कोचों को तैयार करने वाली बेहतरीन टीम मौजूद है।

संक्षिप्त-समाचार

महिला टी20 विश्व कप से पहले ऑस्ट्रेलियाई कोच शेली निट्शके ने 2029 तक बढ़ाया कार्यकाल

मेलबर्न। ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की मुख्य कोच शेली निट्शके ने टीम के साथ अपना अनुबंध तीन साल के लिए बढ़ा लिया है। अब वह 2029 के मध्य तक ऑस्ट्रेलियाई टीम की मुख्य कोच बनी रहेंगी। यह घोषणा इंग्लैंड में होने वाले महिला टी20 विश्व कप से ठीक पहले सोमवार को की गई है। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर शेली निट्शके ने वर्ष 2022 में मैथ्यू मोट की जगह मुख्य कोच का पद संभाला था। उनके कार्यकाल में ऑस्ट्रेलिया ने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक और 2023 महिला टी20 विश्व कप का खिताब जीता। हालांकि हाल के वनडे और टी20 विश्व कप में टीम सेमीफाइनल तक ही पहुंच सकी थी। निट्शके के नए अनुबंध के तहत वह अगले चार बड़े टूनार्मेंटों में ऑस्ट्रेलिया की जिम्मेदारी संभालेंगी। इनमें 2026 और 2028 महिला टी20 विश्व कप, 2027 चैंपियंस ट्रॉफी और 2028 ओलंपिक शामिल हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया 2027 में इंग्लैंड दौरे पर एशेज खेलेगा, जबकि 2029 में घरेलू एशेज सीरीज की मेजबानी करेगा। शेली निट्शके ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के हवाले से कहा, इस टीम के साथ काम करना और इतने शानदार खिलाड़ियों व सपोर्ट स्टाफ के साथ आगे बढ़ना मेरे लिए गर्व की बात है। हमने साथ मिलकर काफी उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन आने वाले वर्षों में यह टीम और भी बहुत कुछ कर सकती है। आगे कई बड़े टूनार्मेंट और चुनौतियां हैं, जिनके लिए मैं बेहद उत्साहित हूं। महिला टी20 विश्व कप से पहले ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन अनौपचारिक अभ्यास मैच खेलेगा। इसके बाद टीम इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के खिलाफ आईसीसी के अभ्यास मुकाबलों में उतरेगी।

शुरूआती कारोबार में शेयर बाजार में तेजी का रुख, मुनाफा वसूली के बावजूद सेंसेक्स और निफ्टी मजबूत

नई दिल्ली। पॉजिटिव ग्लोबल संकेतों के कारण आज शुरूआती कारोबार में शेयर बाजार में तेजी का रुख नजर आ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होने की उम्मीद और होर्मुज स्ट्रेट के फिर से खुलने के आसार के कारण उत्साहित घरेलू शेयर बाजार ने आज सप्ताह के पहले कारोबारी दिन ही मजबूती के साथ कारोबार शुरू किया। कारोबार की शुरूआत होते ही खरीदारी के सपोर्ट से पहले 10 मिनट में ही सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सूचकांक की मजबूती और बढ़ गई, जिससे बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों के मार्केट कैप में पांच लाख करोड़ रुपये से भी अधिक की बढ़ोतरी हो गई। हालांकि इसके बाद मुनाफा वसूली शुरू हो जाने की वजह से इन दोनों सूचकांक की चाल में कुछ गिरावट भी आई। सुबह 10 बजे तक का कारोबार होने के बाद सेंसेक्स 1.01 प्रतिशत और निफ्टी 0.91 प्रतिशत की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। सोमवार प्रातः 10 बजे तक का कारोबार होने के बाद स्टॉक मार्केट के दिग्गज शेयरों में से आयशर मोटर्स, श्रीराम फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक और बजाज फाइनेंस के शेयर 5.15 प्रतिशत से लेकर 2.23 प्रतिशत की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। दूसरी ओर, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, ओएनजीसी, टीसीएस, मैक्स हेल्थकेयर और सन फार्मास्यूटिकल्स के शेयर 2.01 प्रतिशत से लेकर 0.24 प्रतिशत की गिरावट के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे थे। अभी तक के कारोबार में स्टॉक मार्केट में 2,786 शेयरों में एक्टिव ट्रेडिंग हो रही थी।

कच्चे तेल में नरमी का रुख, मई में पहली बार 100 डॉलर से नीचे आई कीमत

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी तनाव को खत्म करने के लिए अमेरिका और ईरान के एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) के मसौदे पर काफी हद तक सहमत हो जाने की खबर के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में आज बड़ी गिरावट का रुख नजर आ रहा है। मई के महीने में पहली बार कच्चा तेल अंतरराष्ट्रीय बाजार में 100 डॉलर प्रति बैरल के स्तर से भी नीचे आ गया है। ब्रेंट क्रूड ने सोमवार 4.93 डॉलर प्रति बैरल की गिरावट के साथ मई के महीने में पहली बार 100 डॉलर प्रति बैरल के स्तर से नीचे जाकर 98.61 डॉलर प्रति बैरल के स्तर से कारोबार की शुरूआत की। ट्रेडिंग शुरू होने के बाद इसकी कीमत उछल कर 99.47 डॉलर प्रति बैरल के स्तर तक पहुंची, लेकिन इसके बाद इसकी चाल में गिरावट का रुख बन गया। थोड़ी देर में ही ब्रेंट क्रूड गिर कर 97.40 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर आ गया। भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:15 बजे तक का कारोबार होने के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड 5.61 डॉलर प्रति बैरल यानी 5.42 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 97.93 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर कारोबार कर रहा था। ब्रेंट क्रूड की तरह ही वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड ने भी आज 4.59 डॉलर प्रति बैरल की कमजोरी के साथ 92.01 डॉलर प्रति बैरल के स्तर से कारोबार की शुरूआत की। शुरूआती कारोबार में डब्ल्यूटीआई क्रूड उछल कर 92.55 डॉलर प्रति बैरल के स्तर तक आया, लेकिन इसके बाद इसकी चाल में गिरावट आ गई। थोड़ी देर में ही डब्ल्यूटीआई क्रूड गिरकर 90.45 डॉलर प्रति बैरल के स्तर तक आ गया।

सर्राफा बाजार में सांकेतिक गिरावट, सोना और चांदी की कीमत में मामूली कमी

नई दिल्ली। घरेलू सर्राफा बाजार में सोमवार शुरूआती कारोबार के दौरान सोना और चांदी के भाव में सांकेतिक गिरावट का रुख बना हुआ नजर आ रहा है। कीमत में आई कमजोरी के कारण देश के ज्यादातर हिस्सों में 24 कैरेट सोना आज 1,59,050 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,60,680 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं 22 कैरेट सोना सोमवार 1,45,790 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,47,290 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। इसी तरह, चांदी के भाव में सोमवार मामूली गिरावट आने के कारण ये चमकीली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में 2,84,900 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिक रही है। दिल्ली में आज 24 कैरेट सोना 1,59,200 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,45,940 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,59,050 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,45,790 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 1,59,100 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,45,840 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना आज 1,60,680 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 1,47,290 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है।

वनडे विश्व कप 2027 के लिए कमिंस-स्टार्क-हेजलवुड पर ऑस्ट्रेलिया का भरोसा कायम

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

फोटोः हि.स.

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम प्रबंधन ने 2027 वनडे विश्व कप को ध्यान में रखते हुए अपने अनुभवी तेज गेंदबाजों- पैट कमिंस, मिशेल स्टार्क और जोश हेजलवुड पर पूरा भरोसा जताया है। फिटनेस और लगातार क्रिकेट के दबाव के बावजूद ऑस्ट्रेलिया को उम्मीद है कि यह तिकड़ी विश्व कप तक पूरी तरह फिट और शानदार फॉर्म में रहेगी।

तीनों खिलाड़ियों को पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ आगामी सीमित ओवरों की श्रृंखलाओं से आराम दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने बताया कि तीनों खिलाड़ी इन दौरों के लिए उपलब्ध थे, लेकिन टीम प्रबंधन ने लंबे कार्यक्रम और खिलाड़ियों के कार्यभार को देखते हुए उन्हें विश्राम देने का फैसला किया। मैकडोनाल्ड ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के हवाले से कहा, लोग केवल मौजूदा मुकाबलों को देखते हैं और पूछते हैं कि खिलाड़ी क्यों नहीं खेल रहे हैं, लेकिन यदि आप 2027 विश्व कप तक का पूरा कार्यक्रम देखें, तो यह उनके शरीर को तैयार करने और उन्हें फिट बनाए रखने का सबसे महत्वपूर्ण समय है। हमारी योजना है कि तीनों खिलाड़ी 2027 विश्व कप में खेलें। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की बढ़ती उम्र को देखते हुए उन्हें फिट रखना आसान नहीं होगा। फिलहाल स्टार्क 36, हेजलवुड 35 और कमिंस 33 वर्ष के हैं। मुख्य कोच ने कहा ,हमारी सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इन तेज गेंदबाजों को लगातार क्रिकेट के बीच कैसे फिट रखा जाए। मेडिकल और खेल विज्ञान विभाग इस पर लगातार काम कर रहा है।

मैकडोनाल्ड ने यह भी साफ किया कि खिलाड़ी अपनी इच्छा से श्रृंखलाएं नहीं छोड़ रहे हैं।उन्होंने कहा, ऐसा नहीं है कि खिलाड़ी खुद तय करते हैं कि कौन सी श्रृंखला खेलनी है। ये फैसले भविष्य के कार्यक्रम और फिटनेस को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं।

ग्लोबल मार्केट से पॉजिटिव संकेत, एशिया में भी तेजी का रुख

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में शांति होने की उम्मीद बढ़ने और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में आई गिरावट की वजह से आज ग्लोबल मार्केट से पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी बाजार पिछले सत्र के दौरान मजबूती के साथ बंद हुए थे। डाउ जॉन्स फ्यूचर्स भी आज फिलहाल बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यूरोपीय बाजार में भी पिछले सत्र के दौरान लगातार तेजी बनी रही। वहीं एशियाई बाजार में भी आज आमतौर पर खरीदारी का रुख बना हुआ है। अमेरिकी बाजार में पिछले सत्र के दौरान उत्साह का माहौल बना रहा, जिसके कारण वॉल स्ट्रीट के सूचकांक हरे निशान में बंद होने में सफल रहे। एस एंड पी 500 इंडेक्स 0.37 प्रतिशत की मजबूती के साथ 7,473.47 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह नैस्डेक ने 0.19 प्रतिशत की तेजी के साथ 26,343.97 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। वहीं डाउ जॉन्स फ्यूचर्स आज फिलहाल 395.65 अंक यानी 0.78 प्रतिशत की बढ़त के साथ 50,975.35 अंक के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यूरोपीय बाजार में भी पिछले सत्र के दौरान खरीदारी होती रही। एफटीएसई इंडेक्स 0.22 प्रतिशत उछल कर 10,466.26 अंक के स्तर पर बंद हुआ।

फ्रेंच ओपन 2026: नोवाक जोकोविच ने पहले दौर में जियोवानी म्पेत्शी पेरिकार्ड को हराया

एजेंसी (हि.स.)
पेरिस

सर्बिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने रिकॉर्ड 25वें ग्रैंड स्लैम खिताब की अपनी चुनौती की शानदार शुरूआत करते हुए फ्रेंच ओपन 2026 के पहले दौर में रविवार देर रात फ्रांस के जियोवानी म्पेत्शी पेरिकार्ड को 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 से हराया। इस मुकाबले के साथ ही नोवाक जोकोविच पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम मुकाबलों में सबसे ज्यादा 82 बार खेलने वाले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया। हालांकि, रोलां गैरो में खेले गए इस मुकाबले में शुरूआत में जोकोविच अपने सर्वश्रेष्ठ लय में नजर नहीं आए।

फ्रांसीसी खिलाड़ी जियोवानी म्पेत्शी पेरिकार्ड ने पहले सेट में शानदार खेल दिखाते हुए 6-5 की बढ़त बनाई और फिर दमदार ऐस लगाकर सेट अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही वह 17 वर्षों में पहले ऐसे खिलाड़ी बने जिन्होंने फ्रेंच ओपन के पहले दौर में जोकोविच से सेट जीता। मैच के बाद जोकोविच ने कहा, जियोवानी को बधाई। मैंने पहली बार उनके खिलाफ खेला और उनकी सर्विस को पढ़ना बेहद मुश्किल था। मेरे करियर में मैंने ऐसी सर्विस बहुत कम खिलाड़ियों की देखी है। तीसरे वरीय जोकोविच ने दूसरे सेट में वापसी करते हुए निर्णायक मौकों का फायदा उठाया और मुकाबले को बराबरी पर ला दिया। इसके बाद अनुभवी सर्बियाई खिलाड़ी ने अपना आक्रामक खेल दिखाया और तीसरा सेट आसानी से जीत लिया। चौथे सेट में जियोवानी म्पेत्शी पेरिकार्ड को कलाई और हाथ में परेशानी के कारण उपचार लेना पड़ा। हालांकि उन्होंने संघर्ष जारी रखा, लेकिन जोकोविच ने 4-3 की बढ़त बनाकर मैच पर नियंत्रण कर लिया और लगातार 22वीं बार फ्रेंच ओपन के पहले दौर में जीत दर्ज की।

कनाडियन ग्रां प्री में किमी एंटोनेली की लगातार चौथी जीत, बनाया ऐतिहासिक रिकॉर्ड

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

मॉन्ट्रियल के सर्किट गिल्स विलेन्यूव में रविवार को आयोजित कनाडियन ग्रां प्री में किमी एंटोनेली ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार चौथी जीत दर्ज की। 19 वर्षीय एंटोनेली ने यह रेस जीतकर इतिहास रच दिया। मर्सिडीज के ड्राइवर एंटोनेली और उनके टीम साथी जॉर्ज रसेल के बीच रेस के दौरान जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। दोनों कई बार बढ़त बदलते रहे, खासकर 13वें लैप में दोनों के बीच रोमांचक टक्कर रही। हालांकि, 68 लैप की रेस के 30वें लैप में जॉर्ज रसेल की कार के पावर यूनिट में खराबी आ गई, जिससे उन्हें रेस बीच में छोड़नी पड़ी।

एंटोनेली 1952 में अल्बर्टो अस्कारी के बाद लगातार चार रेस जीतने वाले पहले इतालवी ड्राइवर बन गए हैं। इसके साथ ही वह अपने करियर की शुरूआती चारों रेस लगातार जीतने वाले पहले फॉमूर्ला-1 ड्राइवर भी बन गए हैं। रेस जीतने के बाद एंटोनेली ने कहा, मैं इस तरह जीतना नहीं चाहता था। जॉर्ज के साथ शानदार मुकाबला चल रहा था, लेकिन जीत तो जीत होती है। एंटोनेली ने 1 घंटा 28 मिनट 15 सेकंड में रेस पूरी की और फेरारी के लुईस हैमिल्टन को लगभग 11 सेकंड से पीछे छोड़ दिया। रेड बुल के मैक्स वर्स्टैपेन तीसरे स्थान पर रहे। अब तक इस सीजन की पांचों ग्रां प्री रेस मर्सिडीज ने जीती हैं। ड्राइवर्स चैंपियनशिप में एंटोनेली 131 अंकों के साथ शीर्ष पर हैं, जबकि जॉर्ज रसेल 88 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। अपनी कार में आई खराबी पर रसेल ने निराशा जताते हुए कहा, अचानक सब कुछ बंद हो गया। इंजन रुक गया, इलेक्ट्रॉनिक्स काम नहीं कर रहे थे और ब्रेकिंग भी सही नहीं थी। यह बेहद निराशाजनक है।

समर्पण

कहा, चक्रवर्ती की जुझारू भावना को सलाम

वरुण दर्द में भी टीम के लिए खेले: अजिंक्य रहाणे

एजेंसी (हि.स.)
कोलकाता

कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के कप्तान अंजिक्य रहाणे ने खुलासा किया है कि टीम के स्टार स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने पैर की उंगली में फ्रैक्चर होने के बावजूद खेलने का फैसला खुद लिया था। रहाणे ने कहा कि वरुण की टीम के प्रति प्रतिबद्धता और जुझारूपन काबिल-ए-तारीफ है।

दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ रविवार को केकेआर के आखिरी लीग मैच के बाद रहाणे ने कहा कि वरुण को खिलाने का फैसला मेडिकल टीम की सलाह के बाद लिया गया था। उन्होंने बताया कि केकेआर के फिजियो, बीसीसीआई की एनसीए टीम और भारतीय टीम के मेडिकल स्टाफ के बीच इस मामले पर विस्तार से चर्चा हुई थी। रहाणे ने कहा, मैं मेडिकल मामलों में दखल नहीं देता। मेरा काम सिर्फ यह देखना होता है कि खिलाड़ी का मानसिक स्तर कैसा है, वह खेलने के लिए तैयार है या नहीं और कितना जोखिम है। फिजियो का मानना था कि खेलने से वरुण की चोट और नहीं बढ़ेगी। दरअसल, वरुण चक्रवर्ती को 3 मई को हैदराबाद में मैच के दौरान चोट लगी थी, जब ईशान किशन का सीधा शॉट उनके बूट पर जा लगा। इससे उनके बाएं पैर की उंगली में फ्रैक्चर हो गया। आईपीएल 2026 में यह उनका तीसरा फ्रैक्चर था, क्योंकि इससे पहले उनकी दो उंगलियां भी चोटिल हो चुकी थीं। रहाणे ने कहा कि इतनी गंभीर चोट के बावजूद वरुण लगातार टीम के लिए खेलने को तैयार थे। उन्होंने कहा, पूरा श्रेय वरुण को जाता है। ऐसी चोट में भी अगर खिलाड़ी खेलने की इच्छा दिखाता है तो यह बताता है कि टीम उसके लिए कितनी मायने रखती है।

मैं कभी पीछे हटने वालों में नहीं रहा : रहाणे

सीजन के दौरान केकेआर की लगातार हार और अपनी कप्तानी पर उठे सवालों को लेकर भी रहाणे ने खुलकर बात की। उन्होंने साफ कहा कि कप्तानी छोड़ने का विचार कभी उनके मन में नहीं आया। रहाणे ने कहा, मैंने हमेशा सकारात्मक सोच के साथ क्रिकेट खेला है। मेरा मानना है कि जब टीम मुश्किल में हो, तभी आपके चरित्र की असली परीक्षा होती है। दबाव हर खिलाड़ी पर होता है, लेकिन जरूरी यह है कि आप घबराएं नहीं। उन्होंने कहा कि लगातार हार के बावजूद टीम ने हार नहीं मानी और यही केकेआर की सबसे बड़ी ताकत रही। रहाणे ने कहा, हमारे लिए सबसे जरूरी था वर्तमान में बने रहना। क्रिकेट में चीजें कभी भी बदल सकती हैं। मैं कभी पीछे हटने वालों में नहीं रहा और कप्तानी छोड़ने का विचार मेरे मन में कभी नहीं आया।

भारतीय गेंदबाजों पर भरोसा करना पड़ा सही फैसला

रहाणे ने यह भी बताया कि सीजन के दौरान कई तेज गेंदबाज चोटिल हुए, लेकिन उन्होंने भारतीय गेंदबाजों पर भरोसा बनाए रखा। इसका फायदा टीम को बाद में मिला। उन्होंने कहा, मैं भारतीय गेंदबाजों को समय देना चाहता था। मुझे भरोसा था कि अगर हम उनका समर्थन करेंगे तो वे दबाव में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। शुरूआती मैचों में हम कुछ मौकों का फायदा नहीं उठा सके, लेकिन टीम ने जिस तरह वापसी की, उस पर मुझे गर्व है। बता दें कि केकेआर को अपने आखिरी लीग मैच में दिल्ली के खिलाफ 40 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। इस हार के साथ ही केकेआर ने आईपीएल 2026 में 13 अंकों के साथ सातवें स्थान पर अपना अभियान समाप्त किया।

राज्यसभा सांसद ने पीएम श्री सरकारी स्कूल के 10वीं के विद्यार्थियों को वितरित की साईकिल

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने पंचकूला/पिंजौर के फोरेस्ट कांप्लेक्स में आयोजित कार्यक्रम में पीएम श्री सरकारी स्कूल के 10वीं के विद्यार्थियों को साइकिलें वितरित की और कहा कि जो विद्यार्थी 10वीं-11वीं कक्षा में टॉप करेगा, उसे वे इलेक्ट्रिक व्हीकल सम्मान स्वरूप पुरस्कार देंगे। इस अवसर पर भाजपा विधायक शक्ति रानी शर्मा भी उपस्थित रही। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेट्रोल डीजल बचाने को लेकर किए गए आहवान पर सभी बच्चों व लोगों को गाडियों का कम इस्तेमाल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हो सके तो लोग साइकिलिंग करें, इससे सेहत भी बनेगी और फ्यूल एनर्जी भी बचेगी।

राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि स्कूल में पढने वाले बच्चे यहां मेहनत करके अपनी दिशा व दशा निर्धारित करते हैं। इसमें परिजन, शिक्षकों, दोस्तों सभी का योगदान होता है, इसलिए सही दिशा में बढ़ें और खूब पढ़ें लिखें। हमारा भविष्य आप सभी लोग हैं। उन्होंने कहा कि आज सिर्फ साइकिल वितरण का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि जिस रास्ते पर आप निकलने की शुरूआत कर रहे हैं, उसका श्रीगणेश है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर बनने का आान किया है, इसलिए हमें समय की जरूरत को देखते हुए वैश्विक परिस्थितियों के अनुसार आगे बढना है और आत्मनिर्भर बनना है। सरकारी नौकरियां अब पारदर्शिता के अनुसार मिलती है। अब भारत बदल रहा है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2047 तक देश विकसित भारत बनेगा। अब बच्चे नौकरी तो पाएंगे ही बल्कि अपना काम भी शुरू करेंगे और नौकरी लेने वाले नहीं अब नौकरी देने वाले बनेंगे।

उन्होंने कहा कि आज एआई के जमाने में बहुत कुछ किया जा सकता है। आज 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनियां शुरू करने वाले भारत के लोग बड़े घरों से नहीं बल्कि भारत के आम परिवारों के लोग हैं। यह कंपनियां हजारों करोड़ों रुपये की कंपनियां बन रही है।

विधायक शक्ति रानी ने कहा कि आज जो साइकिलें वितरित की गई हैं यह कोई बड़ी सौगात तो नहीं लेकिन इसके फायदे बहुत बड़े हैं। उन्होंने कहा कि बच्चे समय की कद्र करें और इसका सदुपयोग करें, क्योंकि समय से कोई भी चीज बड़ी नहीं है। उन्होंने कहा कि बच्चे समय पर स्कूल पहुंचे और परिजनों पर निर्भर न रहें, इसलिए आज यह साइकिलें बांटी गई हैं। इस अवसर पर भाजपा नेता भवनजीत, हरीश मोंगा, कृष्ण कुमार, पवन कुमारी, कृष्ण कुमार लांबा, जिला शिक्षा अधिकारी सहित अनेक अधिकारीगण मौजूद रहे।

कृष्ण लाल पंवार ने पंचकूला में अवैध खनन पर की सख्त कार्रवाई

- सहायक खनन अभियंता निलंबित, जांच समिति गठित
- जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में 13 शिकायतों पर सुनवाई
- बिना लाइसेंस मीट दुकानों पर 10 दिन में करें कार्रवाई
- श्री कृष्ण लाल पंवार ने अधिकारियों को समयबद्ध शिकायत समाधान के दिए निर्देश
- पंचकूला जिला कष्ट निवारण समिति को सर्वश्रेष्ठ बनाने पर दिया जोर

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

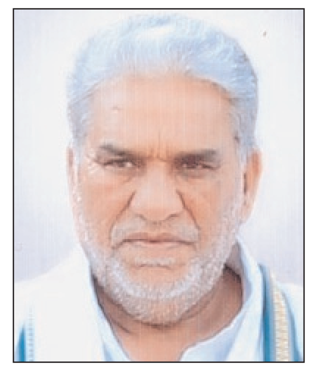

हरियाणा के विकास एवं पंचायत तथा खनन मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने गांव खेड़ावाली, कालका में अवैध खनन की शिकायत पर कड़ा संज्ञान लेते हुए सहायक खनन अभियंता राजेंद्र प्रसाद को निलंबित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिले में किसी भी प्रकार का अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार आज सेक्टर-1 स्थित लोक निर्माण विश्राम गृह में आयोजित जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस अवसर पर उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा भी उपस्थित रहे। बैठक में कुल 13 शिकायतें रखी गईं, जिनमें से 9 का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि 4 शिकायतों को लंबित रखते हुए संबंधित अधिकारियों को आगामी बैठक से पूर्व उनका समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

खेड़ावाली, कालका निवासी ने शिकायत में बताया कि गांव में सरकारी नियमों के विपरीत अवैध खनन किया जा रहा है। इस संबंध में अधिकारियों को शिकायत देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा रायपुररानी क्षेत्र में भी अवैध खनन का मामला उठाया गया। शिकायतों पर गंभीर रुख अपनाते हुए मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने सहायक खनन अभियंता राजेंद्र प्रसाद को निलंबित करने तथा एक जांच समिति गठित करने के निर्देश दिए। यह समिति अवैध खनन के मामलों की जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उन्होंने पुलिस विभाग को रात्रि गश्त बढ़ाने के निर्देश देते हुए कहा कि अवैध खनन में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

गांव बुढ़नपुर के निवासियों ने इंदिरा कॉलोनी के समीप बिना लाइसेंस मीट बेचने की शिकायत रखी। इस पर मंत्री ने संबंधित विभागों को अभियान चलाकर आगामी 10 दिनों के भीतर बिना लाइसेंस संचालित सभी मीट दुकानों को हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस विभाग को इंदिरा कॉलोनी क्षेत्र में एक पीसीआर वाहन तैनात करने के निर्देश भी दिए। साथ ही कहा कि बिना वैध लाइसेंस के मीट बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। गांव ईशरनगर, पिंजौर निवासी ने आंगनवाड़ी केंद्र के सामने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत दी। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए मंत्री ने नगर परिषद कालका के कार्यकारी अधिकारी को पूरे खसरे की निशानदेही करवाकर अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए।

एनएच फार्मास्यूटिकल्स, पेट कैमिस्ट शॉप एवं पार्लर तथा पेट एनिमल मेडिकल सेंटर-3, पंचकूला द्वारा सेक्टर-3 स्थित सरकारी पेट अस्पताल में अनियमितताओं की शिकायत दी गई। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि पिछले कई महीनों से कार्रवाई के निर्देश दिए जाने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस पर मंत्री ने स्पष्ट किया कि रिहायशी क्षेत्रों में किसी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति नहीं है। उन्होंने एसडीएम पंचकूला को निर्देश दिए कि ऐसे मामलों में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और अगली बैठक से पहले समाधान प्रस्तुत किया जाए। बरवाला से भरेली तक सड़क की खराब स्थिति की शिकायत पर मंत्री ने लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता को गड्ढे भरने एवं सड़क की मरम्मत के निर्देश दिए, ताकि आमजन को बेहतर आवागमन सुविधा मिल सके।

सेक्टर-11 पंचकूला निवासी ने शिकायत में कहा कि स्टिल्ट पार्किंग की सुविधा होने के बावजूद कई घरों के पीछे अवैध रैंप, बगीचे और गेट बनाए गए हैं, जिससे सड़क संकरी हो गई है और लोगों को परेशानी हो रही है। इस पर मंत्री ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से कार्रवाई की जानकारी मांगी। प्राधिकरण के संपदा अधिकारी ने बताया कि अवैध अतिक्रमण हटाने की योजना तैयार कर ली गई है और सेक्टर-11 में प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। गांव बतौड़, बरवाला निवासी ने गंदे पानी की निकासी न होने की समस्या उठाई। शिकायतकर्ता ने बताया कि पानी जमा होने से गंदगी फैल रही है और लोगों को आने-जाने में कठिनाई हो रही है। मंत्री ने जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी को प्राथमिकता के आधार पर समस्या का समाधान कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

मंत्री ने निर्देश दिए कि जिला स्तरीय अधिकारी स्वयं बैठकों में उपस्थित रहें तथा अधीनस्थ कर्मचारियों को बैठक में भेजने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने अधिकारियों से टीम भावना के साथ कार्य करने का आान किया।

परमात्मा के बोध से स्वत मिट जाते हैं भेदभाव: निरंकारी सतगुरु माता जी

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़/पंचकूला

श्रद्धा ,भक्ति, प्रेम एवं आध्यात्मिक चेतना से परिपूर्ण दिव्य वातावरण में परम श्रद्धेय सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता रमित जी की पावन छत्रछाया में रविवार को बांसवाड़ा शिवप्रिया फाम बालावाला में भव्य निरंकारी संत समागम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में यह संदेश दिया कि मनुष्य जन्म केवल सांसारिक जीवन जीने के लिए नहीं अपितु परमात्मा को जानकर उससे इकमिक होने की अवस्था है। यही मानव जीवन का वास्तविक लक्ष्य है।

इस दिव्य आयोजन में सतगुरु माता जी ने श्रद्धालुजनों को सम्बोधित करते हुए फरमाया कि कण.कण में बसे परमात्मा का एहसास हर एक गुरुसिख के जीवन में विनम्रता दया करुणा प्रेम के भाव को उजागर करता प्रत्येक व्यक्ति की जीवन यात्रा अलग होती हैए इसलिए दूसरों का आंकलन करने के बजाय आत्ममंथन कर स्वयं को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। परमात्मा का एहसास जीवन का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए,ऐसा एहसास जो केवल अनुमान या कल्पना से नहींए बल्कि प्रत्यक्ष दर्शन प्रेम आस्था एवं भक्ति से प्राप्त होता है। जब मनुष्य गुरुसिख संबंध को समझते हुए गुरमत के मार्ग पर चलता हैए तब उसके जीवन में दिव्य गुण स्वतः ही विकसित होने लगते हैं।

सतगुरु माता जी ने आगे कहा कि जब परमात्मा से प्रेम होता है तो संपूर्ण सृष्टि से प्रेम होने लगता है और जातिए रूप.रंगए अमीर.गरीब जैसे भेदभावों से ऊपर उठ जाता है। सच्चा संत वही है जो मानवता को जोड़ने का कार्य करे, सबके प्रति समान भाव रखे और मिलवर्तन की भावना के साथ जीवन व्यतीत करे। गुरु की शिक्षा केवल सुनने तक सीमित न रहकर जीवन में उतरनी चाहिए तभी वास्तविक आध्यात्मिक परिवर्तन संभव होता है।

इस आयोजन में गीतकारोंए कवियों एवं विचारकों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से हृदय की गहन अनुभूतियों को अभिव्यक्त किया जिसका प्रत्येक शब्द और स्वर आत्मिक आनंद एवं आध्यात्मिक उल्लास की दिव्य अनुभूति करा रहा था जिसे सुनकर वहां उपस्थित हर श्रद्धालु भक्त भावविभोर हो उठा। चारों ओर दिव्यता एवं आध्यात्मिकता का अनुपम वातावरण प्रदर्शित हो रहा था। मसूरी जोन के जोनल इंचार्ज श्री हरभजन सिंह ने सतगुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी का आयोजन में दिव्य उपस्थिति हेतु हृदय से अभिवादन किया। साथ ही आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रशासन के सकारात्मक सहयोग सेवादारो श्रद्धालु भक्तों का आभार व्यक्त किया।

सात-दिवसीय वर्कशॉप संपन्न

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन चंडीगढ़ ने 24 मई 2026 रिसर्च मेथोडोलॉजी की बुनियादी बातें समझना विषय पर सात-दिवसीय वर्कशॉप सफलतापूर्वक संपन्न की। इस वर्कशॉप को भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा वित्तपोषित किया गया था। इस वर्कशॉप का उद्देश्य पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के नर्सिंग पेशेवरों और शिक्षाविदों के बीच रिसर्च क्षमताओं को मजबूत करना था, जिसके लिए उन्हें रिसर्च मेथोडोलॉजी के विभिन्न पहलुओं में व्यापक प्रशिक्षण और व्यावहारिक सत्र प्रदान किए गए। इस वर्कशॉप में एक गहन शैक्षणिक कार्यक्रम शामिल था, जिसमें विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर किया गया, जिसमें PICOT प्रारूप का उपयोग कर-के रिसर्च समस्याओं की पहचान, रिसर्च के नैतिक पहलू, मात्रात्मक और गुणात्मक रिसर्च डिजाइन, मिश्रित-पद्धति रिसर्च, सैंपलिंग तकनीकें, रिसर्च उपकरणों की वैधता और विश्वसनीयता, डेटा संग्रह के तरीके, सांख्यिकीय विश्लेषण और प्रकाशन के लिए पांडुलिपि लिखना शामिल था।

इस वर्कशॉप का आयोजन NINE की प्रिंसिपल डॉ. सुखपाल कौर के विशेषज्ञ मार्गदर्शन में किया गया था। PGIMER चंडीगढ़ के प्रतिष्ठित संकाय सदस्य और विशेषज्ञ, जिनमें डॉ. सुषमा कुमारी सैनी, डॉ. सौरभ दत्ता, डॉ. मंजू धंदापानी, डॉ. जोसेफ एल. मैथ्यू, डॉ. निताशा शर्मा, डॉ. मधु गुप्ता, डॉ. कविता नारंग, डॉ. अशोक कुमार, डॉ. अंकिता, डॉ. अजय प्रकाश और डॉ. गीतांजलि कल्याण शामिल थे, संसाधन व्यक्ति के रूप में उपस्थित थे। इस वर्कशॉप में दैनिक समूह गतिविधियों और व्यावहारिक सत्रों के माध्यम से 'हैंड्स-ऑन लर्निंग' (कर-के सीखने) पर जोर दिया गया। इन सत्रों में साहित्य खोज, फंडिंग के लिए रिसर्च प्रस्ताव तैयार करना, नमूना आकार की गणना, SPSS, MS Exce' और Zotero जैसे विभिन्न सॉफ्टवेयर का उपयोग और उपकरण विकास जैसे विषय शामिल थे।

पोस्टर मेकिंग और नुक्कड़ नाटक के जरिये नशे के खिलाफ युवाओं को जागरूक करेगा एनआईए

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

विश्व तंबाकू निषेध दिवस-2026 पर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान पंचकूला की ओर से तंबाकू और निकोटीन की बढ़ती लत के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। जागरूकता अभियान के जरिये युवाओं और आमजन को तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों से अवगत कराने के साथ नशामुक्त जीवन शैली अपनाने के प्रति प्रेरित किया जाएगा। अभियान की शुरूआत 29 मई से होगी, जोकि एक जून तक चलेगा। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के कुलपति प्रोफेसर (डॉ.) संजीव शर्मा और डीन प्रोफेसर गुलाब चंद पमनानी के मार्गदर्शन में नशा मुक्त अभियान को साकार करने में संस्थान अहम भूमिका निभा रहा है। डीन इंचार्ज प्रोफेसर सतीश गंधर्व ने बताया कि बढ़ती निकोटीन लत विशेषकर युवाओं के स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी है। धूम्रपान और तंबाकू सेवन फेफड़ों, हृदय और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का प्रमुख कारण है। ऐसे में समाज को जागरूक करना और लोगों को नशा मुक्त जीवन की ओर प्रेरित करना समय की बड़ी आवश्यकता है। संस्थान के उप चिकित्सा अधीक्षक डॉ. गौरव गर्ग ने बताया कि संस्थान में अगद तंत्र विभाग की ओपीडी में नशे की लत से प्रभावित रोगियों का उपचार किया जा रहा है। इसके साथ ही, भारत सरकार और हरियाणा सरकार की ओर से चलाए जाने वाले नशा मुक्ति अभियान में भी संस्थान की भागीदारी रहती है। अगद तंत्र विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. सुनीता यादव ने बताया कि 29 मई को पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें संस्थान के विद्यार्थी हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर आने वाले विद्यार्थियों को योग दिवस पर पुरस्कृत किया जाएगा। 30 मई को नशे के खिलाफ जागरूकता रैली निकाली जाएगी। रैली की शुरूआत एनआईए से होगी और दो से तीन किलोमीटर क्षेत्र को कवर करने के बाद संस्थान में समापन होगा। 31 मई को श्रमिकों को नशे के खिलाफ जागरूक किया जाएगा।

मलोया के निवासियों के लिए समाधान शिविर आयोजित

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

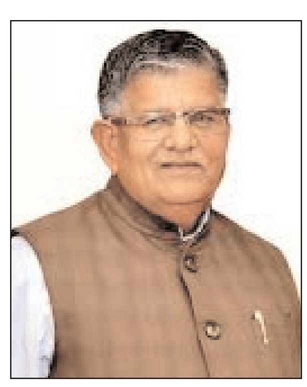

चंडीगढ़ प्रशासन की पारदर्शी, उत्तरदायी एवं जन-केंद्रित शासन व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए पंजाब के राज्यपाल एवं यू.टी. चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया ने आज मलोया के निवासियों के लिए समाधान शिविर आयोजित किया। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा आयोजित यह तीसरा समाधान शिविर था, जिसमें महापौर श्री सौरभ जोशी, यू.टी. चंडीगढ़ के मुख्य सचिव श्री एच. राजेश प्रसाद, पंजाब के राज्यपाल के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विवेक प्रताप सिंह, वित्त सचिव श्री दीपर्वा लाकड़ा, पुलिस महानिदेशक डॉ. सागर प्रीत हुड्डा, उपायुक्त श्री निशांत कुमार यादव सहित प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

शिकायत निवारण शिविर के दौरान विभिन्न विभागों की टीमों ने निवासियों से कुल 84 शिकायतें एवं आवेदन प्राप्त किए। शिविर स्थल पर प्राप्त सभी शिकायतों का विधिवत पंजीकरण कर उन्हें आवश्यक कार्रवाई एवं समयबद्ध समाधान हेतु संबंधित विभागों को भेजा गया। निवासियों ने स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति, बिजली, सड़कें, स्ट्रीट लाइट, आवास, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा अन्य आधारभूत ढांचे से जुड़े कई मुद्दे उठाए। मलोया की पंजाब सीमा से निकटता को देखते हुए शिक्षा, खेल अवसंरचना, स्वच्छता, सुरक्षा एवं नशा मुक्ति से संबंधित विषय भी प्रमुखता से सामने आए। निवासियों ने क्षेत्र में बेहतर संपर्क एवं आवागमन को सुगम बनाने के लिए वैकल्पिक मार्ग की मांग भी उठाई, साथ ही बकाया किराये पर अधिक ब्याज देनदारी से जुड़ी चिंताएं भी व्यक्त कीं।

संबंधित विभागों के अधिकारियों ने मौके पर ही शिकायतों एवं प्रश्नों का उत्तर देते हुए निवासियों को उठाए गए मुद्दों के समाधान हेतु की जा रही कार्रवाई की जानकारी दी। कई मामलों का तुरंत निस्तारण किया गया, जबकि अन्य मामलों को त्वरित एवं समन्वित कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को सौंपा गया। प्रशासक ने अधिकारियों को शिकायतों के समयबद्ध निपटारे के निर्देश देते हुए जवाबदेही, नियमित निगरानी एवं विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया।

प्रशासन की जनसंपर्क आधारित कार्यशैली पर बल देते हुए श्री कटारिया ने कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन नागरिकों तक शासन को पहुंचाने तथा जनता के साथ प्रत्यक्ष संवाद को और अधिक मजबूत करने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है।

संबंधित अधिकारी नागरिकों की मूलभूत समस्याओं का बिना विलंब, करें समाधान: सतपाल शर्मा

उपायुक्त ने समाधान शिविर में सुनी जनसमस्याएं, त्वरित समाधान के दिए निर्देश

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

- गांव साकेतड़ी में मानव कॉलोनी में पेयजल समस्या पर लिया संज्ञान, संबंधित अधिकारी को जल्द से जल्द पेयजल समस्या को हल करने के दिए निर्देश

उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा ने लघु सचिवालय के सभागार में समाधान शिविर में आज गांव साकेतड़ी में मानव कॉलोनी के नागरिकों द्वारा पेयजल समस्या की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए जनस्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग के कार्यकारी अभियंता को जल्द से जल्द पेयजल समस्या को हल करने के निर्देश दिए। उपायुक्त लघु सचिवालय के सभागार में समाधान शिविर में आज जिलावासियों की समस्याएं सुन रहे थे। उपायुक्त ने समाधान शिविर में जिलावासियों की 13 समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर बिना विलंब किए समाधान करने के निर्देश दिए।

उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को सख्त संदेश देते हुए कहा कि सभी अधिकारी नागरिकों के लिए मूलभूत सुविधाओं का प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द निवारण करें ताकि लोगों को पेयजल, सीवरेज व अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशानी का सामना ना करना पड़े। उपायुक्त ने समाधान शिविर में सेक्टर-31 नाडा साहब के पार्क में झूले व ओपन जिम लगवाने की मांग पर सेक्टर-31 निवासियों को जल्द से जल्द झूले व जिम लगवाने का आश्वासन दिया और संबंधित अधिकारी को मौके का मुआयना कर अस्टीमेट बनाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

सतपाल शर्मा ने मोरनी खंड के गांव कादरभोज के ग्रामीणों की गली बनवाने की मांग पर संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारी को मौके का मुआयना कर जल्द से जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के निदेशानुसार जिले में समाधान शिविर का आयोजन लगातार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अलग अलग कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े और उनकी समस्याओं का समाधान एक ही जगह पर हो सके। इसी उद्देश्य के साथ प्रत्येक सोमवार व वीरवार को प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक समाधान शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी विभागों के संबंधित अधिकारी एक ही स्थान पर उपस्थित रहकर लोगों की समस्याएं सुनते है और उनका समाधान करते है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री स्वयं भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समाधान शिविर में जुड़ कर लोगों से फीडबैक लेते है। उपायुक्त ने अधिकारियों को समाधान शिविर में आने वाली सभी समस्याओं का बिना विलंब के जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त निशा यादव, नगराधीश जागृति, वन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी विशाल कौशिक, डीडीपीओ विशाल पराशर, जनस्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग के कार्यकारी अभियंता समीर शर्मा, एमिनेंट पर्सन जसमेर बंजारा, सत्यवान भारद्धाज, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, आबकारी व कराधान, मत्स्य, महिला बाल विकास, समाज कल्याण, नगर निगम, पुलिस सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

संक्षिप्त-समाचार

स्कूलों में योग विशेषज्ञों द्वारा विद्यार्थियों को दिया गया योग प्रशिक्षण

पंचकूला। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस-2026 के उपलक्ष्य में आयुष विभाग हरियाणा के महानिदेशक श्री संजीव वर्मा के निदेर्शानुसार, जिला प्रशासन पंचकूला एवं आयुष विभाग के द्वारा 21 जून 2026 को 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डा. दिलीप कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस-2026 के अवसर पर तीन दिवसय प्रशिक्षण शिविर के तहत जिले के स्कूलों में आयुष विभाग के योग विशेषज्ञों और स्कूलों के प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा, पी0टी0आई0 व डी0पी0आई0 द्वारा विद्यार्थियों को योग प्रशिक्षण दिया गया। योग विशेषज्ञों और स्कूलों के प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा, पी.टी.आई व डी.पी.आई. द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के स्कूलों में विद्यार्थियों को योग प्रोटोकॉल का अभ्यास करवाया गया । इस तीन दिवसय प्रशिक्षण शिविर में स्कूलों के लगभग 1600 विद्यार्थियों ने पूर्ण उत्साह से योग प्रोटोकॉल का अभ्यास किया। प्रशिक्षण शिविर का आंरभ प्रार्थना मंत्र के उच्चारण से किया गया तदोपरांत योग क्रियाओं का अभ्यास करवाते हुए इन यौगिक क्रियाओं द्वारा होने वाले लाभों की भी जानकारी दी गई।

एसडीएम ने सेक्टर-5 व 9 के नाईट क्लबों व रूफटॉप होटलों का किया औचक निरीक्षण

पंचकूला। उप-मंडल अधिकारी (नागरिक) पंचकूला श्री चंद्रकांत कटारिया ने नागरिकों के लिए कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने लोगों की सुविधा के उद्देश्य से सेक्टर-5,8,9,10,11की दुकानों, व नाईट क्लबों व होटलों में रूफटॉप पार्टियों मे बजने वाले म्यूजिक के मद्देनजर और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ निरीक्षण अभियान चलाया। निरीक्षण अभियान के दौरान एसडीएम ने सभी नाईट क्लब व रूफटॉप होटलों से तेज आवाज में चल रहे म्यूजिक को नोर्म के अनुसार व प्रशासन द्वारा तय समय सीमा में चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि रूफटॉप होटलों से आ रही म्यूजिक आवाज से रिहायशी क्षेत्र के लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। म्यूजिक को कम आवाज में तय नोर्म के अनुसार ही चलाया जाए। उन्होंने नाईट क्लब के मालिकों को भी प्रशासन द्वारा तय समय सीमा के अनुसार क्लब चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जो नाईट क्लब व रूफटॉप होटल तय नोर्म के बाहर चलते पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि समय समय पर होटलों व नाईट क्लबों की मॉनिटरिंग कर रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय में जमा करवाए। उन्होंने बताया कि अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान उनके साथ आबाकारी व कराधान विभाग, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पुलिस बल व अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

राजकीय महाविद्यालय कालका में ग्रेजुएशन कोर्स के लिए दाखिले की प्रक्रिया आरंभ

पंचकूला/ कालका। राजकीय महाविद्यालय कालका में ग्रेजुएशन कोर्स के लिए दाखिले की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। दाखिले के लिए विद्यार्थियों को उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा के ऑनलाइन ऐडमिशन पोर्टलपर आवेदन करना होगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए कॉलेज प्राचार्या डॉ गीता सुखीजा ने बताया कि स्नातक कार्यक्रमों के लिए एडमिशन की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। महाविद्यालय में विद्यार्थी बीए, बी.ए. भूगोल ऑनर्स, बीकॉम, बीकॉम ऑनर्स, बैचलर ऑफ लाइफ साइंस, बैचलर ऑफ फिजिकल साइंस , बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट, बी.बी.ए मे दाखिला ले सकते हैं। विद्यार्थी 31 मई तक एडमिशन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि राजकीय महाविद्यालय कालका में बी.ए. पाठ्यक्रम में 320, बीकॉम में 320, बीकॉम ऑनर्स में 60, बैचलर ऑफ लाइफ साइंस में 40, बैचलर ऑफ फिजिकल साइंस में 80, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में 40, बैचलर ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट में 60, बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स इन ज्योग्राफी में 30 सीटें उपलब्ध है। महाविद्यालय में प्रवेश संबंधी जानकारी लेने हेतु विद्यार्थी एवं अभिभावक अत्यंत उत्साहित है।श्रीमती अरुणा आसफ अली सरकारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कालका, एक प्रमुख ठअअउ इ+ मान्यता प्राप्त संस्थान और हरियाणा सरकार द्वारा उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त संस्थान है।

इग्नू ने जून 2026 टीईई की सत्रांत परीक्षा के लिए हॉल टिकट जारी किए

पंचकूला। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने 1 जून 2026 से शुरू होने वाली जून 2026 (टीईई) सत्रांत परीक्षा के लिए हॉल टिकट/प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। जून 2026 टीईई के लिए आवेदन करने वाले सभी शिक्षार्थियों को जून 2026 टीईई परीक्षा फॉर्म भरने के दौरान उनके द्वारा पहले से बनाई गई लॉगिन आईडी के माध्यम से समर्थ पोर्टल से हॉल टिकट/प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सलाह दी जाती है। डॉ. भानु प्रताप सिंह, इग्नू क्षेत्रीय केंद्र चंडीगढ़ के वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक ने बताया कि क्षेत्रीय केंद्र चंडीगढ़ ने 11 परीक्षा केंद्र स्थापित किए हैं। राजकीय स्नातकोत्तर कॉलेज, सेक्टर 46बी, चंडीगढ़ (06027) , जीजीडीएसडी कॉलेज, सेक्टर 32सी, चंडीगढ़ (06036), सीएसई विभाग, यूआईईटी, पंजाब विश्वविद्यालय, सेक्टर 25, चंडीगढ़ (0601), एमडीएसडी कॉलेज, अंबाला शहर, अंबाला (1036), राजकीय स्नातकोत्तर कॉलेज, कबाड़ी बाजार, अंबाला कैंट (06038), जीएमएन स्नातकोत्तर कॉलेज, अंबाला कैंट (06024), राजकीय स्नातकोत्तर कॉलेज, सेक्टर 1, पंचकुला (06033), राजकीय स्नातकोत्तर कॉलेज, कालका (06003डी) और गणित विभाग, पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला (2203) जिसमें सेंट्रल जेल अंबाला और मॉडल जेल चंडीगढ़ में 02 परीक्षा केंद्र शामिल हैं जो केवल जेल के कैदियों के लिए हैं।